

**Session : 9**

**Date : 14-12-2006**

**Participants :** [Verma Shri Ravi Prakash](#),[Sethi Shri Arjun Charan](#),[Yadav Dr. Karan Singh](#),[Varma Shri Ratilal Kalidas](#),[Gehlot Shri Thawar Chand](#),[Bwiswmuthiary Shri Sansuma Khunggur](#),[Athawale Shri Ramdas](#),[Paswan Shri Virchandra](#),[Singh Shri Arjun](#),[Yerrannaidu Shri Kinjarapu](#),[Singh Shri Arjun](#),[Thangka Balu Shri K.V.](#),[Yadav Shri Devendra Prasad](#),[Tahir Shri Mohammad](#),[Panda Shri Prabodh](#),[Chakraborty Shri Sujan](#),[Pradhan Shri Dharmendra](#),[Ganesan Shri L.](#),[Annayyagari Shri Sai Prathap](#),[Owaisi Shri Asaduddin](#),[Gowda Dr. \(Smt.\) Tejasvini](#),[Yadav Shri Ram Kripal](#),[Kharventhan Shri Salarapatty Kuppusamy](#),[Chander Kumar Shri](#),[Satpathy Shri Tathagata](#),[Shiwankar Shri Maha Deo Rao](#),[Gao Shri Tapir](#),[Bhakta Shri Manoranjan](#),[Malhotra Prof. Vijay Kumar](#),[Virendra Kumar Shri Rawat Prof. Rasa Singh](#),[Krishnaswamy Shri A.](#),[Gulshan Smt. Paramjit Kaur](#),[Ramadass Prof. M.](#),[Radhakrishnan Shri Varkala](#),[Yerrannaidu Shri Kinjarapu](#),[Gangwar Shri Santosh Kumar](#),[Ponnuswamy Shri Mohan](#),[Paswan Shri Ramchandra](#),[Swain Shri M.A. Kharabela](#)

>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Bill, 2006 moved by Shri Arjun Singh (Bill passed).

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(SHRI ARJUN

SINGH): Madam, I beg to move\* :

“That the Bill to provide for the reservation in admission of the students belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizen, to certain central educational institutions established, maintained or aided by the Central Government, and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

सभापति महोदया : अर्जुन सिंह जी, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे?

SHRI ARJUN SINGH: I have moved the Bill for consideration.

MADAM CHAIRMAN: Motion moved:

“That the Bill to provide for the reservation in admission of the students belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizen, to certain central educational institutions established, maintained or aided by the Central Government, and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

---

## \*Moved with the Recommendation of the President

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदया, मैं केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर आरक्षण विधेयक, 2006 जो अभी माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अनुरक्षित या सहायता प्राप्त कतिपय केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के विद्यार्थियों के प्रवेश में आरक्षण तथा उनसे संबंधित या उनके आनुंगिक वियों का उपबंध करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। चूंकि समाज के जो कमजोर वर्ग हैं और उनके उत्थान के लिए तथा उनको समान अवसर देने के लिए यह विधेयक लाया गया है, इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ लेकिन इसके पहले चूंकि मैं बोलने में राजभाा हिन्दी का प्रयोग कर रहा हूँ और मेरे सामने हिन्दी का बिल है तथा एक तरफ अंग्रेजी का बिल है, मैं इसमें आपका संरक्षण चाहूंगा कि दोनों में से मैं किसके ऊपर बोलूँ? इसमें जो पहले हिन्दी वाला बिल है, इससे सरकार की नीयत का पता चलता है। इसमें जो ओबीसी की परिभाा दी गई है, अंग्रेजी वाले में जो लिखा हुआ है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्त करना चाहूंगा। मैं पहले वह पढ़ता हूँ:

“ ‘Other Backward Classes’ means the class or classes of citizens who are socially and educationally backward and are so defined by the Central Government.”

एससी और एसटी की परिभाा तो संविधान के अनुसार है और इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इन्होंने हिन्दी प्रति में जो लम्बा-चौड़ा क्रिमी लेयर का लिखा है, पता नहीं उसमें क्या-क्या दे दिया है। इसमें लिखा है:

“अन्य पिछड़े वर्ग से ऐसे वर्ग व वर्गों के नागरिक हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार अवधारित हैं किन्तु,”

किन्तु में 7 लाइनें हैं जिसमें क्रिमी लेयर को अलग करने की बात अंकित है । क्या इसे बिल्कुल आखिरी समय में स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था? जब यह बिल माननीय अर्जुन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उस समय मुंशी जी भी खड़े हुए थे कि इसमें अनुवाद की गलती है और इसे ठीक कर दिया जाएगा। क्या ठीक किया गया है? ये अगर सुधरा हुआ बिल हमारे सामने प्रस्तुत करते तो इनका सही मैसेज पहुंच जाता। अब इसमें क्रिमी लेयर भी शामिल है। इससे सरकार की नीयत के बारे में मैं कह रहा हूँ कि मूल रूप से सरकार क्या चाहती थी? यह शायद इनको ऑफ्टर थॉट आया कि समर्थक दल और दूसरे दलों की क्या स्थिति थी ? मैं इसकी प्रामाणिकता की बात कह रहा हूँ। आखिर अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रति में इतना अंतर क्यों है ? इसमें चौथा क्लॉज जो है, मैं आपके सामने हिन्दी का क्लॉज भी रखूंगा लेकिन मैं पहले अंग्रेजी का क्लॉज पढ़ता हूँ :[\[r36\]](#)

“The provisions of Section 3 of this Act shall not apply to ...” ये शब्द लिखे हुये हैं। हिन्दी प्रति में लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित पर लागू होंगे। अंग्रेजी में ‘नो’ तथा हिन्दी में ‘नहीं’ का प्रयोग नहीं हुआ है । अब इसमें जो कुछ लागू नहीं होगा, इसमें वह लिस्ट दी गई है लेकिन जिन पर लागू नहीं होगी, वह भी दिया गया है, फिर भी संगत

नहीं बनता । मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसी गलती राजभाषा हिन्दी के साथ की गई है, जिसे संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आप समाज के कमजोर वर्गों के लिये यह बिल ला रहे हैं । उनकी भाषा में इतनी गलतियाँ ? ... (व्यवधान)

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) :** सभापति जी, जब इंट्रोडक्शन हुआ तो यह गलती हमारी नज़र में आयी थी और हमने कहा था कि यह गलती हुई है, इसलिये अंग्रेजी वर्सन मान लिया जाये, जो सदन की प्रॉपर्टी हो जाये। मिनिस्ट्री ने इसे वापस नहीं किया, इसलिये यह बात आ गई है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार ही बिल को पारित करायेंगे जिसमें क्रिमीलेयर शब्द नहीं आयेगा।

**प्रो. रासा सिंह रावत :** लेकिन, क्या यह हिन्दी भाषा की उपेक्षा नहीं है?

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** इसमें हिन्दी की उपेक्षा नहीं हुई है। हमने करेक्शन स्लिप जोड़ दी है।

**प्रो. रासा सिंह रावत :** सभापति जी, इसलिये जो कुछ है, वह लागू नहीं हो रहा है।

सभापति जी, जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, जिसकी आबादी 52 प्रतिशत बनती है, उनके कल्याण के लिये तथा उनके लाखों विद्यार्थियों के लिये यह विधेयक लाया गया है। संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिये शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया गया था किन्तु वह सरकारी कानून के अंतर्गत था और अब इस बिल के पारित होने पर स्टैचूटरी राइट्स के रूप में एस.सी.एस.टी. और ओ.बी.सी. के लिये क्रमशः 15 प्रतिशत, साढ़े सात प्रतिशत और 27 प्रतिशत आरक्षण के लिये कहा गया है। कुछ उच्च शिक्षण संस्थाओं - आई.आई.टी., आई.आई.एम. में आरक्षण दिये जाने के लिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

इस बिल के 7 सैक्शन और एक शेड्यूल था जिनके अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ़ एक्सीलेंस की लिस्ट दी गई है। इसके अलावा जिन और संस्थाओं के नाम हैं, वे भी लिस्ट में जोड़े गये हैं। इनमें होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, मुम्बई और उसके कांस्टिट्यूट्स, टाटा नेशनल नार्दर्न इंडिया इंस्टीट्यूट भी हैं जिन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ़ एक्सीलेंस मान लिया गया है। यह बिल इन पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि क्या ओ.बी.सी. की एक्सीलेंस में कोई शंका है? जब आप इन लोगों का अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं, समानाधिकार देने जा रहे हैं, शेड्यूल दिया गया है, फिर ऐसा क्यों किया गया है। पं. जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, बंगलौर, फिज़िकल रिसर्च लैबोरेट्री और स्पेस फिज़िकल सेंटर भी हैं, - क्या इनके इंस्टीट्यूट ऑफ़ एक्सीलेंस में कोई शंका है? कौन गरीब है, कौन अमीर है, कोई एस.सी.एस.टी. या ओ.बी.सी. या जनरल क्लास का है, यह सब शेड्यूल में दिया गया है तो इन्हें किस आधार पर छोड़ा गया है। माननीय मंत्री जी अपने तर्कसंगत उत्तर में बता सकते हैं कि ये सब इंस्टीट्यूट ऑफ़ एक्सीलेंस हैं और यह नहीं होना चाहिये था। यह बात एक हद तक तो ठीक है लेकिन क्या बाद में इन्हें एक्सीलेंस का दर्जा दिया जायेगा जब कुछ योग्य बनकर इन वर्गों से प्रवेश लेंगे । प्रतिभा किसी की बपौती नहीं होती । माननीय मंत्री जी इस बारे में स्पष्टीकरण दें।

सभापति महोदया, इससे पहले कि मैं बिल के बारे में चर्चा करूँ, मैं थोड़ा ओ. बी.सी. के बारे में कहना चाहूँगा। जो इनके बारे में ओ बी सी कमीशन बना हुआ है, मैं बताना चाहूँगा कि the backward classes or classes of citizens which form part of the weaker sections of the people, are socially stigmatized from time immemorial and educationally pushed back to a very distant position and made to suffer in their low social status compared to the advanced sections of the people into the disability they undergo due to the prolonged suppression and oppression and subjected to serious exploitation as well to unjustifiable and unreasonable discrimination on many grounds particularly in the matter of their legitimate rights, privileges and immunities pertaining to them as citizens of India. लेकिन अभी मौन धारण किया हुआ है। 1993 में मंडल कमीशन की तरफ सरकार का ध्यान गया था जिसकी वजह से आज शिक्षण संस्थाओं में उन लोगों के लिये आरक्षण की स्थिति बन गई है।<sup>[s37]</sup>

हमारे संविधान में लिखा है - securing to all its citizen, justice, liberty, equality and fraternity including social justice and political justice as well as equality of status. उसी के आधार पर ओबीसी और एससी, एसटी को उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया जा रहा है, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। जैसा मैंने कहा कि भारत के संविधान में आर्टिकल 14, 15 और 16, फालिंग अंडर फंडामेंटल राइट्स, उसके अंतर्गत आर्टिकल 45 और 46, फालिंग अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पालिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान में जो बातें कही गई थी, जो प्रावधान किया गया है, उसके आधार पर सन् 2000 में संविधान में 82वां संशोधन हुआ, जिसके अंतर्गत उप-धारा 338 जोड़ कर अभी जो प्रावधान किया गया, उसी श्रृंखला में अब उच्च शिक्षण संस्थानों में ओ बी सी का प्रावधान किया जा रहा है।

माननीय मंत्री जी मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ। इस समय उच्च शिक्षण संस्थानों की तरफ आपका ध्यान गया। देश में मंडल कमीशन 1992-93 में लागू हुआ और आपका 14 साल बाद ध्यान इस तरफ गया। एक प्रो-एक्टिव शब्द आता है - लगता है कि इस मामले में बहुत ज्यादा हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले कुछ राज्यों के चुनावों की खातिर, वोट बैंक की खातिर आप यह बिल लाए हों - नहीं तो इतना विलम्ब क्यों हुआ, क्या कारण था, इसका थोड़ा स्पटीकरण देने का कट करें। जब काकासाहेब कालेलकर की अध्यक्षता में 41 वां पहले पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, उन्होंने भी सिफारिश की थी कि ओबीसी के लिए शिक्षा में सुविधाएं दी जाएं। फिर बी. पी. मंडल आया, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना - इनकी अध्यक्षता में मंडल आयोग बना। उसके गठन के बाद नौकरियों में उस समय प्रावधान हो गया था, लेकिन मंडल आयोग के गठन के 26 वां बाद यह बिल आया है। इंदिरा साहनी तथा अन्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था। उसके 13 वां बाद, पहले भी इन्हीं की सरकारें थीं, अब भी ढाई साल हो गए और अब ये इस बिल को लाए हैं। ओबीसी के लोग शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे कि वह दिन जल्दी आए। संविधान में पहले प्रावधान था, सरकारी आदेशों में एससी, एसटी के आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन ओबीसी के लिए नहीं था। अब मंत्री जी इस बिल को लाए हैं - चलो 'देर आए दुरुस्त आए', इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ कि देर से ही सही, लेकिन आए तो सही।

इसके सैक्शन थ्री में आबादी का अनुपात तय किया गया है। हमारे देश में जो सेंसस होता है, शायद ओबीसी का तो होता ही नहीं है, लेकिन नेशनल सेंसल सर्वे द्वारा और कतिपय मंडल आयोग के संबंध में जब ध्यान गया कि सारे देश में कितनी ओबीसी की जातियां हैं, राज्यों और केन्द्र की लिस्टें देखीं गईं, उनके आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया, लेकिन एससी, एसटी की प्रारम्भ से ही गिनती होती रही है, जब भी दस साल बाद देश में जनगणना होती है, एससी की 15 प्रतिशत, एसटी की साढ़े सात प्रतिशत है परंतु ओबीसी की 27 प्रतिशत जनसंख्या को आरक्षण दिया गया है, जब कि ओबीसी की आबादी को मंडल आयोग ने 52 प्रतिशत माना और एससी को 15 प्रतिशत और एस टी को 7 1/2 प्रतिशत। उसी आधार पर सेंट्रल सर्विसेस में इन्हें जो नौकरियां मिलती हैं, सिविल पोस्ट्स एंड सर्विसेस में 15 प्रतिशत, एसटी को साढ़े सात प्रतिशत इनका आरक्षण रहता है, शिक्षण संस्थानों में भी वही आरक्षण रहता है, लेकिन ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत जो अब तय किया है, जबकि ये 52 प्रतिशत थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था कि 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए उसी में एडजस्ट करने के लिए 27 प्रतिशत मान लिया गया है। 52 प्रतिशत ओबीसी की आबादी है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में 41 प्रतिशत आया है, किसी में 32 प्रतिशत की आबादी बताई है। यदि 32 प्रतिशत ही ओबीसी की आबादी है, इसमें मुस्लिम आबादी 11 प्रतिशत और मिला दी जाए तो ओबीसी की 52 प्रतिशत आबादी हो जाती है।<sup>[rep38]</sup>

महोदया फिर भी 27 प्रतिशत आरक्षण उच्च संस्थानों में किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा सिर्फ मंडल आयोग की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है या सरकार इसे आगे बढ़ाने के लिए कोई मैकेनिज्म तय करेगी? यदि ओ. बी.सी. के लोगों की आबादी ज्यादा है और उन्हें ज्यादा आरक्षण देने की आवश्यकता हो, तब क्या स्थिति होगी? दक्षिण के राज्यों, कर्नाटक, केरल, तामिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आजादी से पहले से ही आरक्षण प्रारम्भ कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप वहां टोटल आरक्षण कुल मिलाकर किसी राज्य में 69 परसेंट है, किसी में 70 परसेंट है और किसी में और भी ज्यादा है। देश में ओ. बी.सी. की आबादी 52 परसेंट है, इसमें हिन्दू और नॉन हिन्दू दोनों ही हैं। इसमें आपने एक क्लॉज दी है कि मायनॉरिटी इंस्टीट्यूशन्स और मायनॉरिटी पर यह लागू नहीं होगा। इसके ऊपर मुझे बहुत आपत्ति है, क्योंकि मायनॉरिटी की जो संस्थाएं हैं, चाहे वह अल्पसंख्यक आयोग हो, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हों अथवा जो विधेयक अभी पारित करके कानून बनाया गया, उसमें आपने जो व्यवस्था की है उसमें मुस्लिम ओ.बी.सी. के लोगों के लिए तो कम से कम मायनॉरिटी इंस्टीट्यूशन्स में प्रवेश की व्यवस्था

वस्था होनी चाहिए। उन्हें इससे क्यों वंचित रखा जा रहा है? चाहे वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या अन्य संस्थाएं हों, जिनके बारे में आपने विधेयक पारित कराया और कानून बनाया, उनमें तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि मायनॉरिटी ओ.बी.सी. के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

यहां दलित मुस्लिमों की बात की जाती है, दलित आदिवासियों की बात की जाती है, क्रिश्चियन आदिवासियों की बात की जाती है, इसमें उनका आरक्षण होना चाहिए। केरल में तो ज्यादातर मायनॉरिटी इंस्टीट्यूशन्स हैं। तामिलनाडु में भी कई पुराने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो उच्च टेक्नीकल हैं, जैसे आई.आई.टी. और आई.आई.एम. लैवल की संस्थाएं हैं, बड़े-बड़े सेंटर ऑफ एक्सैलेंस हैं, उन मायनॉरिटीज की संस्थाओं में एस.सी., एस.टी. या मुस्लिम ओबीसी को प्रवेश से आपने वंचित कर दिया। उनमें हिन्दू के प्रवेश का तो प्रश्न ही नहीं है, जो मायनॉरिटी के लोग हैं, उनमें जो ओ.बी.सी. के बच्चे हैं, उन्हें तो कम से कम उन संस्थानों में प्रवेश मिलना चाहिए। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें।

महोदया, मंत्री जी ने हायर टेक्नीकल इंस्टीट्यूट्स के लिए 27 प्रतिशत तक प्रावधान रखा है। मैं दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। यह अच्छी बात है कि ओ.बी.सी. के लाखों छात्रों को आई.आई.टी. और आई.आई.एम. जैसी उच्च संस्थाओं में आरक्षण मिलेगा। संविधान के 93वें संशोधन के अनुसार जिस प्रकार आपने कमजोर वर्गों के लिए लिए संसद और राज्य विधान सभाओं में कानून बनाया और प्रावधान करके कहा है कि वा 2007 के सत्र से केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में यह लागू होगा - ऐसी व्यवस्था आपने की है, यह अच्छी बात है। आपने कहा है कि सामान्य वर्ग की मान लीजिए 100 सीटें हैं, तो वे सामान्य वर्ग के लिए ही रहेंगी और आरक्षित वर्गों के लिए आप 100 सीटें और बढ़ाएंगे, जिनमें 5 प्रतिशत प्रथम वर्ग में, 10 प्रतिशत द्वितीय वर्ग में और तृतीय वर्ग में 12 प्रतिशत, इस प्रकार आप तीन सालों में 27 प्रतिशत कोटा पूरा करेंगे और तीन सालों में आरक्षण की यह सुविधा उच्च शिक्षण संस्थाओं में पूरी तरह से लागू हो जाएगी। इससे सामान्य वर्ग का अहित नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि उनका ध्यान रखा गया है, लेकिन साथ ही जो ओ.बी.सी. की सीटें हैं, जितनी ऐसी संस्थाएं हैं, चाहे वे एडेड हैं, अनएडेड हैं अथवा सरकारी संस्थाएं - आई.आई.टी. या आई.आई.एम. हैं, उनमें सीटें बढ़ाने पर जितना खर्च होगा, वह पैसा केन्द्र सरकार देगी, लेकिन सरकार ने वित्तीय ज्ञापन में सभी बातें गोलमोल लिखी हैं। यदि केन्द्र सरकार पैसा नहीं देगी, तो राज्य सरकारें पैसा कहाँ से लाएंगी? उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वे इन संस्थाओं को फायनेंस उपलब्ध करा सकें। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक बार तो सीटें बढ़ाने और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर पर केन्द्र सरकार को पूरा खर्च उठाना चाहिए।<sup>[r39][r40]</sup> ताकि सही अर्थों में वास्तव में इन तीन वर्गों के अन्दर जो ओ.बी.सी. को आरक्षण देने वाला 27 परसेंट का मामला है, वह पूरा हो सके। एस.सी. और एस.टी. को भी 15 परसेंट और 7.5 परसेंट का आरक्षण पूरा हो सके। वित्तीय प्रावधानों का भी मंत्री जी जब उत्तर दें तो इन बातों को स्पष्ट करने की कोशिश करें। यह ठीक है कि पहले जिस संस्था में जितनी सीटें उपलब्ध थीं, उन सीटों की संख्या में कोई कमी नहीं की जायेगी, यह तो अच्छी बात है कि उसमें कमी नहीं होगी, लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आरक्षण एक सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए लागू किया गया था, समाज में समरसता पैदा करने के लिए लागू किया गया था, लेकिन इसमें एक प्रावधान रखा है, जिसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगा कि यह जो चौथे कॉलम के अन्दर कहा गया है-

**“The provisions of Section 3 of this Act shall not apply to a minority educational institution as defined in this Act.”**

इस एक्ट में माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन की परिभाषा भी दी है, उसे दोहराने का समय नहीं है कि मैं सारी परिभाषा पढ़ूँ। बाकी नोर्थ ईस्ट में जहां जनजातियां रहती हैं, उन संस्थानों में लागू नहीं होगा, यह तो ठीक बात है, लेकिन माइनोरिटी इंस्टीट्यूशंस में, जैसा मैंने कहा कि वहां कम से कम माइनोरिटी में ओ.बी.सी. के लिए, दलित मुस्लिमों के लिए हों, एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जहां ओ.बी.सी. के लिए हम आरक्षण का पूरा समर्थन करते हैं, इस्लाम और ईसाइयत के अन्दर कहा जाता है कि वहां इक्वेलिटी है, वहां कोई ऊंच-नीच नहीं है, वहां कोई छुआछूत नहीं है और संविधान में जब आरक्षण का प्रावधान

किया गया था तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, ये शब्द थे। अब जो मजहब के आधार पर सच्चर रिपोर्ट का नाम बहुत चर्चित हो रहा है, सरकार की तरफ से आये दिन कुछ बयान दिये जा रहे हैं और जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा, माननीय मानव विकास संसाधन मंत्री जी बहुत प्रो-एक्टिव हो रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि अभी तो यह पास कर दें और बाद में जो कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें भी माइनोरिटी शब्द का प्रयोग किया है, हमने उसका डिसेंट नोट दिया है कि आरक्षण जातियों के आधार पर हो, लेकिन धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का आरक्षण असंवैधानिक और अनुचित है, जिसका हम विरोध करते हैं। जो सोशल स्टेटस के आधार पर ओ.बी.सी. में मुस्लिम्स भी आ जाते हैं, जैसे पहले भी आये हैं, मंडल आयोग के अन्दर, उनकी जितनी जरूरत हैं, वे सारे आये।

मैं एक अन्तिम बात कहकर कि ओ.बी.सी. में कितनी जातियों की सूची है, यह थोड़ा उत्तर दें तो स्पष्ट करें कि राज्य वाइज़ अलग होगा, केन्द्रीय स्तर पर अलग होगी, उनकी सूची क्या है, क्योंकि इन्क्लूज़न तो है, लेकिन एक्सक्लूज़न नहीं है। 1993 में जब से मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुईं, अब तो यह वोट बैंक बन गया है, राजनैतिक आर्काण पैदा करने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जो जातियां मांग करती हैं, अब शेर और बकरी एक साथ कैसे साथ निभेंगे, आप ही अनुमान लगा सकते हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि कई जातियां जैसे-जैसे दबाव बढ़ा रही हैं, कई जातियों को सम्मिलित किया जा रहा है और उसमें संख्या बढ़ती जा रही है। उसमें इन्क्लूज़न है तो इसका एक्सक्लूज़न भी कभी होगा। क्रीमीलेयर की बात, क्योंकि ओ.बी.सी. में पढ़े-लिखे लोग कम हैं, इसलिए ओ.बी.सी. में कुछ राज्यों में ऐसा किया गया है। पहले उत्तर प्रदेश में माननीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे और कर्नाटक वगैरह 6 राज्यों में पिछड़े वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और बहुत अधिक पिछड़ा वर्ग, इन तीन कैटेगरीज़ में बांटा गया, ताकि उनको सुविधा मिले। फिर भी बच जायें तो क्रीमीलेयर, ओ.बी.सी. में क्रीमीलेयर, उनको काम में लिया जाये, यह बात ध्यान में रखी जाये। लेकिन इसके साथ-साथ, जैसा मैंने कहा कि एस.सी. का वित्त निगम है, एस.टी. का वित्त निगम है, एस.सी. को स्कालरशिप्स मिलती हैं, एस.टी. को स्कालरशिप्स मिलती हैं, एजुकेशन फ्रीशिप्स मिलती हैं तो क्या ओ.बी.सी. के लिए भी स्कालरशिप्स की व्यवस्था, वित्त निगम की व्यवस्था, लोनिंग वगैरह हो सके, क्या ये सारी व्यवस्थाएं हो सकेंगी, इसके बारे में भी मंत्री जी जब जवाब दें तो थोड़ा प्रकाश डालें।

इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[R41]

#### **14.00 hrs**

SHRI K.V. THANGKABALU (SALEM): Madam, thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Bill, 2006. This is one of the milestone Bills being brought forward by our Government.

Madam, at the outset, I would like to congratulate the hon. Minister for bringing this innovative and important Bill to this august House. At the same time I would like to salute Shrimati Sonia Gandhi for her actions in helping to bring forward this Bill. At the time of formation of this Government under the leadership of Shrimati. Sonia Gandhi, this Government announced a Common Minimum Programme in which a commitment was made for the weaker sections of the society -- namely, for the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Minorities and Other Backward Classes – that they will be protected and their interests will be taken care of. In keeping with that commitment, a number of issues have been dealt with and decisions were taken and those are being implemented one by one. This historic Bill is also one such step that is being taken by this Government to fulfill the commitment of safeguarding the interests of the weaker sections of the society, more particularly, the people belonging to the Other Backward Classes.

My special thanks are also due to the hon. Minister for his untiring efforts in bringing this Bill and also for his commitment towards the weaker sections of the society, the people belonging to

the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Minorities and the Other Backward Classes. That is why today the mood amongst them is jubilant and happy. I belong to the OBC category. Time and again we had requested the hon. Minister, Shrimati Sonia Gandhi and the hon. Prime Minister to bring forward such a legislation and all of them had made a collective effort to finally bring forward this Bill and make a move towards implementing the commitment made to the nation through the Common Minimum Programme.

Sir, the OBCs constitute more than 60 per cent of the population in the country. Though there are Reports that say the OBC population is 42 per cent, 52 per cent, but the Mandal Commission Report has said that 52 per cent at the minimum is the OBC population in the country. I would, first of all, like to urge upon the hon. Minister to order for a caste census in order to clear the doubts of some vested interests in the country, who are putting it at 30 per cent and 40 per cent, about the percentage of OBC population in the country. If a Commission is set up and a census is taken on caste lines, then the truth will come out. There will not be any doubt about it.

Sir, the first Constitutional amendment in this regard was introduced and passed at the instance of our great leader the late Kamaraj, the then Chief Minister of Tamil Nadu. The then Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru accepted his proposal of introducing a Constitutional amendment for the welfare of the weaker sections of the society in this country. That is how the concept of reservation came into the political system. It was again during the Congress Government at the Centre that the Mandal Commission gave its report and in keeping with the wishes and aspirations of the people belonging to the Other Backward Classes, 27 per cent reservation for people belonging to these classes were implemented in the year 1993 by the then Congress Government led by the then Prime Minister, the late Narasimha Rao. [\[R42\]](#)

At that time, I was the Minister handling the Department and so, I know the position. I should support the implementation of it. It is because at that time also, the condition was very crucial and many people were opposing it. Even Shri V.P. Singh had glamourised for the implementation of this Report and he announced it also. But he could not implement it because of certain vested interests in the country. But the Congress Party, with the commitment towards the weaker sections of the country, implemented it in 1993 with great care and ability. It was implemented and accepted by all sections in both the Houses and the people of the country. That is how 27 per cent reservation in Central Govt. jobs is in place and the OBCs are enjoying it. From that day onwards, we have been insisting that reservation in education is a must and we have taken a number of steps for it. Again, after a lapse of 14 years, only when the Congress-led Government has come into power, this Bill could see the light of the day. It is the commitment of the Congress that, under the leadership of Madam Sonia Gandhi and the hon. Prime Minister, we have brought this Bill today. We always stand on what we say and it is on this direction that we see that this Bill is brought today. There was hue and cry from various sides to implement this reservation. Different quarters said that it should not be implemented at one-go.

A Committee was appointed under Shri Veerappa Moily and it submitted its report with a number of recommendations. In fact, the Veerappa Moily Committee is not giving help to the OBCs. It is contrary to the aspirations of the people of India and that is why, I urge upon the hon.

Minister on this point. That Report says about 'in one-go, in one year and 5 per cent, 7 per cent and 5 per cent'. It is not going to materialize and it is not going to be easy. If 27 per cent is under constitutional authority, then where is the problem? I know that the hon. Minister is very much convinced and very categorical in saying that it should be implemented in one-go. Over months, I have been hearing his statements and I thank him for his commitment. I appeal to him being the senior most Minister in the Government and the senior most leader in the country. Through you Sir, I request that he should come forward to implement in one-go. It is possible to do justice to the OBCs if it is three years time because when you make it three years, there will be a problem. We are not against other communities. Let other communities enjoy the benefits. We are not against them. We have no problem regarding SCs or STs or minorities. We are not against these communities because we want all weaker sections in the country to be given weightage and they should get their due share. They should equally share the socio-economic benefits through our Government programmes and schemes.

I urge upon the Minister to kindly reject the Veerappa Moily Committee Report because that Report is not going to help the people in any way. That Committee has no commitment, conviction or wisdom. I am sorry to say this because I know the position as I also belong to one such community.

I wish that that Committee Report will be rejected, your will and wisdom will follow suit, and then things will be all right.

The other issue that I would like to deal with is, reservation has to be on the basis of population. Today though the population of such communities being 60 per cent and above, they are getting only 27 per cent reservation.

Why? The OBC communities are not very wealthy. If you see their position at the grassroots level, they are also like Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In each and every community, there are rich and poor people. In this community also there are labourers, farmers, etc. and they do all sorts of jobs. This is also a hard fact.

I congratulate and thank the Government because through the Sachar Committee the Government has brought the minority issues into light. Likewise, I wish and demand, through you, that a Committee be formed to consider and find out the status of the OBC communities in the country so that the real picture will come out and we can certainly do justice to the OBCs. As Scheduled Castes and Scheduled Tribes are given separate percentage of reservation, like 15 per cent and 7.5 per cent, likewise the OBCs should also be given 27 per cent. There should not be any problem. For minorities also, separate reservation should be given. There is no doubt about it because they also belong to weaker sections of the society.

The Sachar Committee has very categorically and clearly informed the people today. We should accept that. They should also get separate reservation for minorities.

In the implementation of the OBC reservation, we have been emphasizing two or three important issues. We do not have an OBC Parliamentary Forum. We



do not have a separate Ministry for OBCs. When I was there in the Government, I recommended a separate Ministry for the Tribal Welfare. Today, it has come. I initiated and our Government initiated steps for having a separate Ministry for minorities. Today, it has come. But OBCs are clubbed with the Ministry of Social Justice and Empowerment. It should be immediately bifurcated and a separate Ministry should be formed. Then only will the OBCs get their due share. Why I am demanding this is due to the following facts and figures. You will be astonished to hear that from 1996 to 2006, the amount allocated in the plan expenditure of the Government for the Ministry of Social Justice and Empowerment is: 2001-02 – Rs. 1,322 crore; 2002-03 – Rs. 1,410 crore; 2004-05 – 1,481 crore; 2005-06 – 1,495 crore. Out of these, the OBC share in 2001-02 was Rs. 71 crore; in 2002-03, it was Rs. 68.85 crore; in 2003-04, it was Rs. 62.10 crore and in 2006, it is Rs. 65 crore. See the anomaly! Sixty per cent of the population is getting only Rs. 65 crore. With Rs. 65 crore, what will the Department dealing with the OBCs do? They will pay only the salaries and allowances to the officers of the Department. No money will go to the welfare and development of the OBCs. This is a hard reality and hard fact. ... (*Interruptions*)

Madam, I represent the Congress Party. I should be given more time. Nobody else is going to speak from my Party.

MADAM CHAIRMAN : There are six more Members to speak from your Party.

SHRI K.V. THANGKABALU : Madam, even then you can give me some more time.

In the non-plan expenditure, the OBC community got Rs. 1.55 crore in 2001; in 2005 it was Rs. 2 crore only. This is the hard reality.

I urge upon the hon. Minister to kindly see as to how the OBC communities are being treated. The OBC communities should be given the priority in the fund allocation also. That is why I demand a separate Ministry for them. If a separate Ministry for OBCs is formed, then they will take up issues on merit and the Government of India will have to announce more funds for their welfare and development.[\[MSOffice43\]](#)

With regard to the Budgetary Support, I had mentioned it. That is why, we wanted a separate Ministry. Then only the welfare and development of the backward communities will be taken care of.

The other issue is that from 1993 onwards, we have been implementing the 27 per cent reservation. There are vacancies over the years. If you see, the backlog vacancies are not being filled up because there is no mechanism. That mechanism is important. We want that to be implemented immediately. For example, I quote this example that in the Central Government services, the total number of Class-I officers is 81,325. The number of other communities is only 71,779 and OBCs are to the extent of 4,147. In Class-II services, the total number is 3,52,827 and the total of OBCs is only 59,000. In the public sector undertakings, the total number of people employed is 503337 out of which OC/Class-II is 3,65,785 out of which the other communities were 73,623. The total number of OBCs is only 3719. Likewise, in Class-II services, the total is 3,65,785

and OC people is 2,60,097 and the total number of OBCs is only 36,000. Please see the plight of the OBCs in the country.

Sir, you are the well wisher. You are the guardian of the OBCs, SCs, STs and the minorities. Under your leadership, I would request you to kindly see that the backlog vacancies in respect of the OBCs are filled immediately on a priority basis. When we were in the Government in 1991-96, for the SCs and the STs, I had done my best to clear the backlog vacancies. Three Special Recruitment Drives were conducted in the wisdom of the Government at that time. Subsequently, I do not know what happened. Now, I urge upon you, Sir, to see that the Special Recruitment Drive for the OBCs is ordered. They should get their due share. Now, only three to four per cent people in the Central Government services are from the OBC community and the remaining percentage has to be given immediately. Then only real justice would be given to OBCs.

Our friends were telling that there is no Commission for the OBCs, SCs, STs and the Minorities. Our Government during the 1991-96 period created three Corporations, the National Backward Classes Finance and Development Corporation was initiated. The National Minorities Development and Finance Corporation was initiated. The Scheduled Caste Finance and Development Corporation and the Scheduled Tribes Finance and Development Corporation are there. These are all constitutionally appointed bodies. The Chairman and other members are functioning.

As I mentioned earlier, fund allocation to these Corporations are not adequate. If these Corporations are empowered with more powers, if they are given more money, they can do well in the field of education, employment and empowerment. They can cover all the three areas thereby the problem faced by the communities can be solved easily. That is why, I urge upon you, Sir, that these Corporations should be given more money, more importance and more allocation than what is given now.

I come to the Reservation Policy. Even in this Bill, there is no security for the community. There are one or two areas. In this Bill, it has been mentioned about certain institutions. As a Member from the ruling party, I cannot give notice of an amendment. So, I can only urge upon you to kindly remove the word "certain." If the word "certain" is removed, then the uncertainty would also be removed thereby all sections of OBCs will get priority. I would, therefore, urge upon you, Sir, that in your wisdom, you should bring forward an amendment to this Bill itself so that it will solve the problem.[\[R44\]](#)

The other thing is, there is no reservation in apprenticeship programme for the OBCs before appointment whereas it is provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. So, apprenticeship programme should be given to the OBCs also.

Then, after 1993, reservation in promotion for the OBC is a question mark even today. But our brothers and sisters belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are getting that benefit. So, the OBCs should also be given this benefit. If it is not given to them, then they will not be able to see any progress in their lives or achieve any position of esteem. Therefore, I urge upon

the hon. Minister to consider giving this benefit to them. For this, amendment of article 16 (4) (B) of the Constitution is required. Then only this problem can be solved. Hence, I urge upon the hon. Minister to bring another Bill of this nature and solve this problem.

Then, representation for OBCs in the Interview and Selection Committees is not there now. I would request the hon. Minister to give direction through the Department of Personnel and Training so that they get this representation thus fulfilling their aspirations.

MADAM CHAIRMAN : Please conclude. You have taken too much time.

SHRI K.V. THANGKABALU : Madam, I will just conclude within a minute.

As you are aware, the OBC population varies from State to State. The Supreme Court has given a ruling that reservation should not exceed more than 50 per cent. In 1993, an all party meeting was called on this matter and all the leaders have agreed on this issue and so, only Tamil Nadu and Karnataka continue to have more than 50 per cent reservation now. Now, they need to go to court every time and get the remedy. A solution to this problem should be found immediately.

MADAM CHAIRMAN : You please conclude now. I am not going to you allow you more time.

SHRI K.V. THANGKABALU : There are only two more issues Madam and after that I will conclude.

I urge upon the hon. Minister to bring a Bill for this purpose so that according to the desire of the State Government concerned and as per the Census of OBC population in each State, the States should be allowed to have population based reservation.

Then, the aspirations of the OBCs can be fulfilled only by creating a separate Ministry in the Government. I would request the hon. Minister to do the needful in this regard. Moreover, there are more than 170 hon. Members of Parliament belonging to the OBCs. So, a separate Parliamentary Committee should be constituted for the welfare of the OBCs.

I hope that all the issues raised by me would be favourably considered by the Government. I thank the hon. Minister for his untiring efforts to see that this Bill is passed. I welcome this historic Bill. I would also like to compliment our hon. leader Shrimati Sonia Gandhi and the Prime Minister Dr. Manmohan Singh for bringing this Bill and support this Bill.

सभापति महोदया : सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अगर आप सभी बोलने में समय सीमा का ध्यान रखें, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकमोडेट कर सकेंगे।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : सभापति महोदया, आपने मुझे केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था(प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2006 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

हिंदुस्तान में अजीब सी विसंगति यह है कि यह देश भिन्न-भिन्न जातियों में बंटा हुआ है। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस दरम्यान भी यह मुद्दा बार-बार उठाया गया था और जब वतन आजाद हुआ तब भी इन मुद्दों पर बातचीत हुई। सच्चाई तो यह है कि जब तक पूरे हिंदुस्तान के सभी लोग, चाहे वे दलित जातियों के हों या पिछड़ी जातियों के हों, सभी जातियों के लोग आंदोलन में शरीक नहीं हुए, आजादी का संघर्ष परवान नहीं चढ़ा। गांधी जी के नेतृत्व में जब दबे-कुचले, पिछड़े सभी लोग आजादी की लड़ाई में आगे आए, तभी आजादी का सुनहरा दिन देखने को मिला। [H45] यह महसूस किया गया था कि जिस तरीके से हिन्दुस्तान की राजनीतिक आजादी [R46]सबकी भागीदारी से ही सम्भव हुई है, अब हिन्दुस्तान की आर्थिक आजादी के लिए इन सभी तबकों की भागीदारी भी आवश्यक होगी। यह एक दुखद बात थी कि समाज के पिछड़े, दबे-कुचले और आदिवासी वर्गों में शिक्षा के स्तर का अभाव था और वे इस मामले में दुर्बल थे। 1927 को जब सरदार भगत सिंह ने इसी असेम्बली में बम और पर्चा फेंका था तो उन्होंने कहा था कि हिन्दुस्तान में लाचारी से आजादी मिलनी चाहिए। इसके लिए हर आदमी को आगे आना होगा और जेहनी अंधेरे से तथा आदमी को आदमी के शोण से मुक्ति के लिए संघर्ष करना होगा।

मैं मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने सेंट्रल इंस्टीट्यूशन्स में आरक्षण का प्रावधान करके उस भावना को पूरा करने का काम किया है। पहले दूसरे संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन इनमें नहीं था। हमारे पूर्व वक्ता बालू साहब कह रहे थे कि यह अजीब सी विसंगति है कि समाज में जहां हम सहारा देने के लिए इन लोगों को आरक्षण दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं भी समाज में हो रही हैं कि इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि सभी आरक्षित पदों को भरा जाना चाहिए था।

आज इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। राष्ट्र को इस बारे में महसूस करना चाहिए कि आज जो हिन्दुस्तान का आर्थिक विकास हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान उन तत्वों का है, जो आदिवासी, दलित और पिछड़े तबकों के लोग कहलाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें वाजिब शेयर नहीं मिल रहा है। सदन में बहस के दौरान हमने इस चीज को देखा है कि जो प्राइमरी सेक्टर है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और खेती के कार्य में लगे मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हें पूरा हिस्सा अपने योगदान का नहीं मिल रहा है। आर्थिक विकास में हमारे साथ माइनोरटीज के साथी भी हैं। लेकिन वह तबका जो शहरों में रहता है या परिकृत है, जिन्हें हमेशा समाज में आर्थिक क्रियाओं की उपलब्धियां हासिल हुई हैं, उनका आर्थिक क्रियाओं का दायरा काफी विस्तृत रहा है।

मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में और विश्वविद्यालयों में पिछड़े वर्ग, दलित और आदिवासी लोगों को आरक्षण देने का काम सुनिश्चित किया है। वह इसके लिए बधाई के पात्र हैं। यह जरूर है कि इसमें कुछ समय लगा है। पिछले सात-आठ सालों से मैंने इस बाबत कई पत्र प्रधान मंत्री जी को और पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी लिखे हैं। इसके अलावा सभी सम्बन्धित विभागों को भी लिखा है। हर जगह से यही जवाब सुनने को मिलता था कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है, लेकिन तुरंत कार्यवाही नहीं हो सकी। आखिर में संसद की स्थाई समिति के माध्यम से इस बिल का मूल्यांकन किया गया और आज यह बिल सदन में चर्चा के लिए पेश किया गया है।

मुझे आशा है कि जितने भी सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशन्स हैं, उनमें अविलम्ब इस पर अमल किया जाएगा। एक विचार यह भी आया था कि तीन वर्षों तक इसे पूरा किया जाएगा। इसलिए हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि बिना किसी विलम्ब के आप इसे तत्काल पूरा करने का काम करें। जो इक्विलिजन की बात आई है, यह सच्चाई है कि संविधान के अनुच्छेद के मुताबिक कई जातियां हैं, जिन्हें इससे जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन निरंतर प्रयास हो रहा है कि उन्हें भी जोड़ा जाए। जहां तक एक्सक्लूजन की बात है, मैं समझता हूँ जातीय आधार पर यह समझदारी की बात नहीं होगी, क्योंकि सभी जातियों में बहुत से कमजोर लोग हैं। ऐसा न हो कि कहीं जरा सी गलती की वजह से हम सामाजिक आधार पर एक्सक्लूजन का काम शुरू कर दें। इससे बहुत से लोगों को न्याय नहीं मिल सकेगा, यह कहकर कि इनकी आमदनी बढ़ गई है और ये उच्च श्रेणी में आ गए हैं। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखकर इन वर्गों के सभी लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए एक्सक्लूजन की नीति बनाते हुए इस पर ध्यान रखा जाए कि किसी भी समाज में विशेष तौर पर दलित या पिछड़े वर्ग जो हैं, जनरलाइज एटीट्यूड नहीं रखा जाए, वरना इससे दिक्कत हो सकती है। सचर आयोग की रिपोर्ट में भी इसी बात को सामने लाया गया है कि हिन्दुस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति काफी खराब है। मुझे लगता है कि हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा। मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि धार्मिक आधार को दरकिनार करते हुए विचार किया जाए। [R47]

महोदया, मेरा कहना है कि संविधान में जो पिछड़े वर्गों की व्याख्या की गई है, वह मूलतः आर्थिक और सामाजिक आधार पर की गई है। मैं समझता हूँ कि एक बार फिर से नया सर्वे करने की जरूरत है या जो पहले सर्वे किया जा चुका है, उसकी समीक्षा करने की जरूरत है कि जो लोग हिंदुस्तान में पिछड़े हुए हैं, समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें समान रूप से समाज की मुख्यधारा में आने के लिए अवसर मिलना चाहिए।

महोदया, हिंदुस्तान में उच्च शिक्षा के लिए दाखिले का जो प्रतिशत है, वह सिर्फ 7 या 8 प्रतिशत है। मैं समझता हूँ कि हमें यथास्थितिवादी हो कर इन परिस्थितियों को नहीं देख सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे आस पास के देशों में, एशिया में और दूसरे बड़े मुल्कों में उच्च शिक्षा में दाखिले का प्रतिशत 30 से 40 प्रतिशत है। हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ता हुआ राट्र है। हमें लगता है कि आने वाले वर्षों में भारत सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से भी आगे बढ़े तो उच्च शिक्षा में वायबल 30 परसेंट, 40 परसेंट, 50 परसेंट दाखिला सुनिश्चित करना पड़ेगा।

महोदया, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो आंकड़े हैं, उनके अनुसार हिंदुस्तान में व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। मैंने पहले भी सदन में यह बात कही है कि आज समय आ गया है कि हम हिंदुस्तान में सभी क्षेत्रों से मैन पावर रिसोर्स का निर्माण करें और उसे हिंदुस्तान से बाहर निर्यात करके विदेश नीति का हिस्सा बनाएं। आज स्थिति यह है कि हमारे पास बहुत बड़ी तादात में प्रोफेशनल्स हैं जो विदेशों में जा रहे हैं, लेकिन जो पिछड़े तबकों, ट्राइबल तबकों से जुड़े हैं, अगर उन्हें आगे बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से 10+2 लेवल पर या उससे उच्च शिक्षा में व्यावसायिक है, उसे आज जो 5 प्रतिशत है, उससे आगे ले जाना पड़ेगा। जैसा मुझे बताया गया है कि हिंदुस्तान में 143 के करीब ट्रेड हैं, जिनमें व्यावसायिक शिक्षण दिया जा रहा है और दुनिया में 3000 से ज्यादा ट्रेड हैं, जहां व्यावसायिक शिक्षण दिया जाता है। पूरी दुनिया में 95 प्रतिशत लोगों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध होती है। मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ा बैकलॉग है, जिसे देखना बहुत जरूरी है।

हिंदुस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान सबसे नई उम्र का राट्र है। हमारे यहां नौजवानों की तादाद 50 प्रतिशत के करीब हो चुकी है। ऐसे मौके पर यदि शिक्षा के प्रति प्रैगमेटिक अप्रोच लेकर चलेंगे, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान बहुत कम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा।

महोदया, इसमें जो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस की बात इसमें कही गई है, उसके बारे में भी मेरा कहना है कि उसमें भी बराबरी का भाव रहना चाहिए। मेरा कहना है कि अगर इस बार किसी व्यक्ति को मौका मिला है जो पिछड़ा नहीं है, तो अगली बार किसी पिछड़े व्यक्ति को मौका दिया जाना चाहिए। जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती मित्र ने कहा कि आज शिक्षा का प्रसार हो रहा है। हमारा राट्र ज्ञान पर आधारित राट्र बन रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि समाज के सभी वर्गों तक ज्ञान की पहुंच बराबर हो। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस की जो सूची है वह घटाई या बढ़ाई जा सकती है। मैं समझता हूँ कि इस प्रक्रिया के लिए इस सदन को, लोकसभा को कांफिडेंस में लेना बहुत ही आवश्यक है। आप इस प्रकार का प्रावधान कर दीजिए, जिससे कि मनमानी न हो सके। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में माननीय मंत्री जी का जो प्रयास है और समाज के प्रयास से जो माहौल बन सकेगा, उसमें सभी वर्गों को साथ में लेकर हिंदुस्तान की तरक्की का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर):** सभापति महोदया, आज सदन में माननीय मंत्री जी ने ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया है, इसलिए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ, क्योंकि 52 प्रतिशत से 54 प्रतिशत लोगों के बच्चे-बच्चियों को पढ़ने का मौका मिलेगा जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं और समाज की मुख्यधारा में आने का प्रयास कर रहे हैं[MSOffice48]।

आपको याद होगा कि जब 25 अगस्त को यह बिल आया था उसी स्वरूप में आज भी उसे प्रचारित कर दिया गया है और लास्ट में दो लाइन्स लगा कर सर्कुलेट कर दिया है। पृष्ठ दो और पंक्ति 35 जो 40 हिन्दी की है, उसमें क्रिमी लेयर का जिक्र

था। पिछली बार इंटरडिक्शन स्टेज में इसका विरोध करके कहा गया था कि असंवैधानिक लैंग्वेज यूज की गई है और संविधान में इसका कहीं कोई प्रावधान नहीं है। कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी है। आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है जो एक सोशल इशू है। कई लोग इसे लेकर दूसरी तरह से चर्चा कर रहे हैं। एक से एक टैलेन्ट लोग बुद्धि बेच कर देश को भी बेचना चाहते हैं। वे बुद्धि बेच कर देश को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ ले गए हैं। ठीक है, इंटरनैशनल फिनौमिना है लेकिन वे सामाजिक मामले में बुद्धि न बेचे तो अच्छा है। इकोनॉमिक मामले में जितनी बुद्धि और प्रतिभा लगानी हो, लगाएं। सोशल इशू को इकोनॉमिक इशू बनाने पर मुझे बहुत अचरज होता है। माननीय मंत्री जी को मैं साधुवाद और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। काफी जद्दोजहद के बाद माननीय मंत्री जी इस बिल को लेकर आए हैं। वह शुरू से इस बिल को लाने के बारे में अड़े रहे हैं। सामाजिक न्याय दिलाने के लिए यह एक पहल और शुरुआत है। इसलिए भी मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। बिल का मसौदा तैयार करने वाले बाबू लोगों के बारे में सब लोग जानते हैं।

महोदया, आप भी जानती हैं कि कैसे कार्यपालिका के लोग बिल का मसौदा तैयार करते हैं? इसलिए रावत जी ने नीयत पर शक किया था। यूपीए सरकार की नीयत पर शंका करना अच्छी बात नहीं है। बुद्धि में गड़बड़ी हो सकती है। बिल का मसौदा तैयार करने वाले ऑफिसर बड़े विद्वान होते हैं। आईएस अधिकारी और नीचे के बाबू बड़े बुद्धि वाले होते हैं और वे किन्तु, परन्तु और बट में ऐसी चीज लगा देते हैं कि न्यायालय में बिल का परपज फॉरफिट हो जाता है। इतनी बुद्धि वाले लोग इसमें लगे रहते हैं। पृष्ठ संख्या 2 और 35 से 40 पंक्तियों को डिलिट किया है जो संशोधित रूप में अभी हमें मिला नहीं है। दो लाइन लगा दी गई हैं जिस के कारण मैं मानता हूँ कि डिलीट होने के बाद यह अच्छा बिल हो गया है। इंग्लिश के बिल के प्रथम पृष्ठ में लिखा है कि

“To provide for the reservation in admission of the students belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes of citizens to certain central educational institutions established maintained or aided by the Central Government, and for matters connected therewith or incidental thereto.”

सर्टेन शब्द पर बैनिफिट ऑफ डाउट उठाया जा सकता है। मैं सत्ता पक्ष का सदस्य हूँ इसलिए संशोधन नहीं दे सका और मैं मर्यादा का पालन करता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि सर्टेन शब्द डिलिट कर दिया जाए। जिस संस्थान में यह लागू होने जाएगा वहां के लोग कह सकते हैं कि कुछ संस्थाओं में है और मेरी संस्था का इसमें जिक्र नहीं है। यहां एक्सक्लूसिव शब्द आया है। मैं चाहूंगा कि सर्टेन शब्द को डिलिट कर दिया जाए। इसमें कुछ संस्थाओं के नाम भी आ रहे हैं जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून। इसे एक्सक्लूड किया गया है। इस संस्था में आरक्षण लागू नहीं होगा। मैं इसका ठीक से अर्थ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या इतनी प्रतिभा किसी में नहीं है कि वह डाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का भी नहीं कर सकता हो? यह मेरी समझ से परे है। इसका जिक्र रावत जी ने भी किया है और सर्टेन शब्द का जिक्र थंगबालू जी ने अपने भाषण के लास्ट में किया है। इसमें फिजिकल रिसर्च लैबोरेट्री, अहमदाबाद का भी जिक्र है। क्या ओबीसी के लोग लैबोरेट्री का भी काम करने लायक नहीं हैं? बाबू लोगों ने अपनी मानसिकता से लिस्ट में कुछ नाम दे दिए हैं और उसकी स्वीकृति हो गई जिस पर गौर से विचार नहीं किया गया। कुछ संवेदनशील और टेक्निकल संस्थान हैं, जहां ट्रेनिंग देने की और एक्सपर्टीज की जरूरत है जो मानने लायक है। ओबीसी के लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, देहरादून में नहीं रहेंगे। यह क्या हो रहा है? इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांसड साइंटिफिक रिसर्च, बैंगलौर को शामिल किया गया है जिस पर विचार करना चाहिए। इसे लेकर एक संशोधन लाना चाहिए। वहां से सक्षम लोगों को नहीं हटाना चाहिए। [a49]

प्रतिभा कैसे मापी जाएगी और उसका क्या पैरामीटर होगा? मैं इसी पर अपनी बात कहना चाहता हूँ। सेंट्रल एजुकेशनल इनस्टीट्यूशन्स (रिजर्वेशन इन एडमिशन) बिल 2006 में एक्सक्लूड करने की जो लिस्ट दी गई है, उसके द्वारा प्रतिभा का क्या पैरामीटर है? किस आधार पर कुछ लोग योग्यता के काबिल नहीं हैं? वे किस आधार पर टेलेंट नहीं हैं, उनमें योग्यता नहीं है, मेरिट में नहीं है। योग्यता कैसे नापी जा सकती है? यह योग्यता का मामला है।

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि वर्ष 1990 में मैं इस सदन का सदस्य था और उस समय श्री वी.पी. सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। 7 अगस्त, 1990 को यह कानून बना था और कैबिनेट से पास हो कर सदन में आया था कि ओबीसी को रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में दिया जाए। उच्च नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान और फैसला श्री वी.पी. सिंह के समय में हुआ था। जिस समय फैसला हुआ था, उस समय बहुत से सवाल उठे थे, इसलिए मैं उनका जिक्र करना चाहता हूँ। वर्ष 1990 में जब जिक्र हुआ तो 1992 में मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। दो साल तक लोग सड़क पर रिहर्सल करते रहे। कहीं आत्मदाह की लड़ाई होती रही। आजादी के 59 वर्ष बीतने के बाद भी जो अघोषित आरक्षण है, उसका कभी जायजा नहीं लिया गया। अघोषित आरक्षण का मतलब है, अनडिक्लेयर्ड रिजर्वेशन। जो डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन पूरी तरह रिजर्वेशन है। सभी चीजों में आरक्षण है, शिक्षा में आरक्षण है, आदि। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में रिजर्वेशन है। इस तरह से उनका पूरी तरह से वर्चस्व है। अघोषित आरक्षण जब टूटने का खतरा होता है, तो कुछ लोगों का दिल टूटने लगता है। वर्ष 1990 में भी कुछ लोगों का दिल टूटा था। आज भी सुना है कि अस्पतालों में जो डॉक्टर नियुक्त हैं, वे आत्महत्या करने चले जाते हैं। यह क्या हो रहा है? जो नया लड़का है, जिसे किसी प्रकार का नुकसान होना है, अगर वह सड़क पर आ जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन जो डॉक्टर नियुक्त है और अघोषित आरक्षण को खत्म नहीं होने देने के लिए उनकी जो मोनोपोली है, उस मोनोपोली को खत्म नहीं होने देने के लिए रा्ट्र की मुख्यधारा से ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया है जो 54 प्रतिशत होगा। आज देश में नए दिमाग वाले लोग आ गए हैं। नया एनएसएस एक अखबार ने निकाल दिया है। मैंने इंडियन एक्सप्रेस में देखा था और उसमें ओबीसी की संख्या घटा दी गई। जब ओबीसी को मुख्यधारा में जोड़ने की लड़ाई शुरू होती है तो आंकड़े घटा दिए जाते हैं। वर्ष 1996 में मैं इस देश में फूड मिनिस्टर के पद पर था। उस समय प्लानिंग कमीशन द्वारा बीपीएल का एस्टीमेट लाया गया था। चूंकि बीपीएल का एस्टीमेट फूड मिनिस्टर नहीं दे सकता है, प्लानिंग कमीशन दे सकता है। उस समय प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष श्री मधु दंडवते थे। [a50] वे गरीबों के हिमायती और समाजवादी नेता रहे हैं, उन्होंने स्टेटिक्स दिया और यहां पर इतना बड़ा काम हुआ कि वर्ष 2001 का स्टेटिक्स ही घटा दिया, कहा गया कि अब 26 परसेंट बीपीएल है। इसका मतलब है कि 35.95 परसेंट यानि 36 परसेंट गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे थे उसे घटाकर 26 परसेंट कर दिया गया। अभी 26 परसेंट ही चल रहा है, प्लानिंग कमीशन का स्टेटिक्स वही चल रहा है। इस तरह से गरीबों की संख्या घटा दी। अब जब ओबीसी को रा्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने की बात हो रही है, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को लागू करने की बात हो रही है तो स्टेटिक्स घटा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि ओबीसी घट रहा है, यह 35 परसेंट ही है। यह कैसा खेल है? यह कितना बढ़िया मैजिक हो रहा है कि सबकी संख्या बढ़ रही है लेकिन ओबीसी घट रहा है क्योंकि ओबीसी शैक्षणिक संस्थाओं, मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थाओं में दाखिला चाहता है। वर्ष 1990 में कहा गया था कि नौकरियों में आरक्षण देने की क्या जरूरत है, इससे योग्यता और प्रतिभा खत्म हो जाएगी इसलिए इन्हें शिक्षा में प्रॉयोरिटी दी जाए। यह बुद्धि का तर्क आया, इसलिए मैं इसके बारे में बोलूंगा जबकि अन्य लोग और प्वाइंट्स के बारे में बोलेंगे। इस देश में बहुत बुद्धिमान लोग हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आपका समय काफी हो गया है। मैं सिर्फ पांच या दस मिनट ही दे सकता हूँ।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :** इस तरह से बीच में टोका जाएगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। यह दूसरा विषय है। मेरी पार्टी का टाइम भी होगा, इसके लिए चार घंटे का समय है और मेरी पार्टी के 24 या 25 मैम्बर्स हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** पार्टी को दस मिनट मिले हैं।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :** मेरे अभी भी तीन या चार मिनट बाकी होंगे, आपकी कृपा हो जाएगी तो दो या तीन मिनट टाइम और दे देंगे। मैं इसलिए कह रहा था कि वर्ष 1990 में तर्क दिया गया कि इनको नौकरी में आरक्षण देने की जरूरत नहीं है, इन्हें शिक्षित किया जाए। इन्हें शिक्षा के दाखिले में प्रॉयोरिटी दी जाए ताकि इनमें प्रतिभा और योग्यता आ जाए। लेकिन जब दाखिले का सवाल आ रहा है तब आत्महत्या हो रही है। ये लोग कहां जाएं? अब कह रहे हैं कि दाखिले में भी नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए माननीय मंत्री जी ने प्रयास किया है और यह बिल आया है, एडमिशन हो जाएगा। प्रोफेसर आप लोग हैं, चार साल में काट कर डिमेरिट कर दो या फेल कर दो, यह तुम्हारे हाथ में है। आप चिंता क्यों करते

हैं? क्यों ओबीसी की सीट घटाने में लगे हुए हैं? क्यों ओबीसी का स्टेटिक्स घटाने में लगे हुए हैं? चार साल में प्रोफेसर तुम ही हो, तुम ही वैल्यूएशन करोगे, तुम्हारे हाथ में मेरिट देना है, प्रेक्टिकल, ओरल या थ्योरी में फेल कर दोगे तो मेरिट नहीं होगी। आप दाखिला देने से क्यों डर रहे हैं? ओबीसी के एडमिशन में क्रीमी लेयर के नाम पर आयरन फिल्टर गेट क्यों लगाना चाहते हैं? दूध आया नहीं, एडमिशन हुआ नहीं और क्रीमी लेयर की बहस हो रही है। इस देश में गजब की बहस होती है, बहस का जो तरीका है, वह मेरी समझ के बाहर है। हम लोग कम बुद्धिमान हैं क्योंकि गांव से आते हैं, गरीबों के बीच से आते हैं, गांव में पैदा हुए हैं और बड़ी बुद्धि वाले लोग क्रीमी लेयर के संबंध में आजकल इतनी बहस करते हैं, आप वूमन बिल में भी क्रीमी लेयर लगा दीजिए तो फैसला हो जाएगा। आप इसे क्यों नहीं लगाते हैं? आप एक तरह का मापदंड रखिए। दूध आया नहीं कि क्रीमी लेयर की बात हो गई, एडमिशन हुआ नहीं और कहते हैं कि क्रीमी लेयर को रोको। यह मसविदा तैयार हुआ है और मैं विधायक पर बोल रहा हूं क्योंकि हिंदी ड्राफ्ट में क्रीमी लेयर का जिक्र है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह डिलीट कर दिया। दूध है तो दस या पन्द्रह साल इसे टैस्ट करो फिर क्रीम निकालो, दूध है ही नहीं है और क्रीम पर बहस हो रही है, यह मेरी समझ से बाहर है क्योंकि क्रीम तभी आएगी जब दूध होगा। आप एडमिशन के लिए दस या पन्द्रह साल प्रयोग कीजिए।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। वर्ष 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने पास किया तब नौकरी में आरक्षण लागू हुआ था, 14 साल हो गए हैं, अभी तक आईएएस और आईपीएस में यूपीएससी से कितना परसेंट आरक्षण मिला है, मैं यह बताना चाहता हूं, मैं आपको बताऊंगा तो आपको हैरत होगी कि यह 15.84 परसेंट है यानि लगभग 16 परसेंट। 27 परसेंट का आरक्षण अभी चौदह साल बनवास में है, 14 साल हो गए हैं और अभी तक 16 प्रतिशत मिला है इसका मतलब है कि 27 परसेंट तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि चरणबद्ध किया गया है और फेज़ वाइज तीन साल में लागू होगा। यह ठीक है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इसे एक साल में लागू कीजिए। पांच, दस या बारह परसेंट हायर या टेक्नीकल इंस्टीट्यूशंस में तीन साल में लागू करेंगे तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से 15 या 16 परसेंट 14 साल में लागू हुआ है, मैं यह दर्ज कराना चाहता हूं कि यह इंजीनियरिंग, मेडिकल, तकनीकी संस्था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईएम, आईआईटी में लागू नहीं हो पाएगा और पांच परसेंट ही कन्टीन्यू रहेगा।<sup>[15]</sup> पांच परसेंट का ही कन्टीन्यू चलता रहेगा। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं।

मैं अपने अंतिम बिन्दु में निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक प्रतिभा और योग्यता का सवाल है, प्रतिभा का क्या मापदंड होगा, उसे कैसे मापा जायेगा। उसका क्या पैरामीटर होगा। आप हमें तालाब में तैरने दो, एडमिशन भी दे दो, परंतु यदि हम तैराक नहीं निकलेंगे तो हमें यह कहकर फेल कर दिया जाएगा कि हमें तैरना नहीं आता। पानी में तैरने का अवसर, अपार्युनिटी नहीं दी और कहते हैं आपको तैरना नहीं आता, आप अच्छे तैराक नहीं बन सकते हैं, आप प्रतिभा वाले लोग नहीं हैं। आप गुणवत्ता खराब करेंगे। आप हमें तैरने तो दीजिए, साइकिल दीजिए, साइकिल पर चढ़ने दीजिए, जब ओ.बी.सी. के लोग आगे बढ़ेंगे तो साइकिल सीख लेंगे। यह राज-काज की हिस्सेदारी की लड़ाई है, यह हिस्सेदारी का सवाल है, यह इकोनोमिक सवाल नहीं है। इसलिए चाहे राज-काज हो, चाहे संस्था हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, उसमें भागीदारी का सवाल है। देश के 52-54 प्रतिशत जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें रा्ट्र की मुख्य धारा में लाना सरकार की सोशल रिस्पॉसिबिलिटी है, सरकार का सामाजिक दायित्व है। चाहे कोई भी सरकार हो। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के सामने मैंने जिन दो-तीन बिन्दुओं की जिक्र किया है, सरकार उन बिन्दुओं पर जरूर गौर करे। हमारे देश में मेडिकल आदि में जो इमरजेन्सी सेवा है, उसमें कुछ वर्गों की मोनोपोली है। इसलिए कुछ वर्ग के लोग समूचे देश में इमरजेन्सी सेवा बंद कर देते हैं। इसलिए आरक्षण बहुत जरूरी है। ताकि मेडिकल और इंजीनियरिंग में इन लोगों की मोनोपोली नहीं हो सके और इमरजेन्सी सेवाएं बंद नहीं हो सकें। किसी भी हालत में सबके लिए इमरजेन्सी सेवा चालू रखने की जो सरकार की रिस्पॉसिबिलिटी है, वह तभी पूरी हो सकेगी, जब सर्व वर्ग का समानुपात प्रतिनिधित्व हो, सामाजिक बैलेन्स हो। इस सोशल बैलेन्स को कायम रखने के लिए रा्ट्र को मजबूत रखने के लिए ओ.बी.सी. को मुख्य धारा में लाना बहुत जरूरी है।

**श्री खारबेल स्वाई (बालासोर) :** माइनोरिटी इंस्टीट्यूशंस में आपको रिजर्वेशन नहीं चाहिए।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :** आप संविधान चेंज मत करिये। संविधान में लिखा हुआ है, सबका राइट प्रोटेक्टेड है। ... (व्यवधान) आप हर चीज पर पालिटिक्स करते हैं।



श्री खारबेल स्वाई : पालिटिक्स आप ही करते हैं, हम नहीं करते हैं। ... (व्यवधान) ऐसे ही बोलते भी रहेंगे।... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, nothing should be recorded.

*(Interruptions)\* ...*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. Nothing should be recorded.

*(Interruptions)\* ...*

---

\* Not recorded

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): On behalf of the DMK Party, I welcome the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Bill, 2006. This Bill is a historical event in this august House.

Sir, I come from the soil of social justice where E.V.R. Periyar, Peraringar Anna, Karmaveerar Kamarajar and our *Thalaivar*, Dr. Kalaignar were born. They are all the warriors and crusaders of social justice.

Today, I thank *Annai Soniaji*, our hon. Prime Minister Manmohanji and our Minister, Arjun Singhji for bringing this historical Bill. We have to particularly thank Mr. Arjun Singh because despite all criticism and agitation, he has brought this Bill.

As our leader Dr. Kalaignar says in Tamil: "*Chonnathai Cheivom, Cheivathi Solvom*" --and in English, it is "what we say we will do; what we can do, we will say."-- today our Madam Soniaji

and the Prime Minister, Dr. Manmohanji at the Centre are fulfilling the Common Minimum Programme.

In the State of Tamil Nadu our DMK Government under the leadership of Dr. Kaliagnar Avargal has scrapped the entrance examination scheme in our State which will be helpful to the downtrodden people and promote social justice in our State.

Today, I am very happy that at last the Government of India has finally decided to pilot a Bill in Parliament to fulfil the long-awaited aspirations of the oppressed sections of the society, the OBCs and the SCs and STs. This effort of the Government, though belated, is in true sense, laudable as it is finally going to implement the provisions contained in Article 15(4) of the Constitution of India which empowers the States for making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens.

In our State, there was a case in 1951 – *Chambagam Durairajan Versus State of Tamil Nadu* – to provide a seat in the medical college. It was filed before the Madras High Court. At that time our Perarinar Anna, EVR Periyar, Karmaveerar Kamarajar and Dr. Kalaignar agitated in our State and successfully convinced the Central Government headed by Pandit Jawaharlal Nehru in enacting the first Constitution Amendment by adding Article 15(4) to the Constitution of India on 2.6.1951 to give effect to special provision for advancement of socially and educationally backward classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

It is a matter of great astonishment and surprise that much time has lapsed in manifestation of the fruits to this class of people for the addition of Article 15(5), which came into effect from 20.1.2006 by the 93<sup>rd</sup> Constitutional Amendment Act, 2005, the first constitutional endorsement to make special provisions for socially and educationally backward classes and Scheduled Castes and Scheduled Tribes in admissions to educational institutions including private, unaided institutions and excluding minority institutions. I once again thank our hon. Minister Shri Arjun Singh for having brought this Bill for successfully passing it on the floor of this House.

Article 16(4) of the Constitution of India (original and unamended provision) empowers the States for making any provision for the reservation of appointments of posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State is not adequately represented in the services under the State. The Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the OBCs of this country have failed to understand as to how they will be able to fill the posts reserved for them until and unless suitable number of seats are reserved for them in the educational institutions for such a long period. This means that making a house in the first floor without any staircase and education is the staircase here. As such, without proper education to the Backward Classes and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people how can we give the posts and services in the Government service? It is an injustice to the socially downtrodden people for the past fifty years.

The logical way of attending to the cause of the OBCs, SCs and STs should have been first reservation of seats in the educational institutions so that they get appropriate education and professional training at par with the other classes and then suitable reservations for them in the appointments or posts.

On behalf of my Party and on my own behalf, I would like to make our categorical stand on the following two important issues. We are totally against debarring any group of OBCs, Scheduled Castes and the Scheduled Tribes from getting the benefits of this reservation under the garb of creamy layer. We are also against the three-year phasing off of the reservation benefit for OBCs and earnestly urge the Government to reconsider the same for implementing this reservation in totality from the first academic year itself, thereby making it mandatory for the Central educational institutions to bring about the requisite increase in the strength of 27 per cent seats in the first year itself in one go.

This was stressed by our Dr. Kalaignar and the founder leader of the PMK Dr. Ramadoss who was stressing to delete the word in clause 5 of the Bill, Central educational institution, to increase the annual permitted strength over a maximum period of three years in certain exigencies. This should be deleted. As our Party is in the Government we cannot bring any amendment. Our sincere request to the hon. Minister is to delete those words in clause 5 for three years in certain exigencies.

I once again support this Bill. Before I conclude, I urge this Government to bring suitable legislation for the backward classes people, the Scheduled Castes, and the Scheduled Tribes people to give opportunity in the private sector companies.

### **15.00 hrs**

श्री मो. ताहिर (सुल्तानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के 59 साल बीत जाने के बावजूद भी संविधान में जो इनके लिए प्रावधान किया गया था, उसमें इनकी बराबरी की भागीदारी नहीं बन पाई है। उनके साथ पक्षपात बरता गया। मंडल कमीशन लागू होने के बाद भी सीटें नहीं बढ़ाई गईं। शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दुस्तान के दलितों, पिछड़ों और माइनोंरिटीज के साथ बड़े पैमाने पर पक्षपात हुआ। आज माननीय मंत्री जी इस बिल को लाए हैं, मैं और मेरी पार्टी के लोग इस बिल का समर्थन करते हैं। उच्च शिक्षा में आरक्षण मिल तो रहा है लेकिन प्राथमिक शिक्षा में अभी तक शिक्षा कम्पलसरी नहीं हुई है। यही कारण है कि उच्च शिक्षा में पिछड़ों, दलितों और माइनोंरिटीज को मदद की जरूरत पड़ रही है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और उसमें बताया गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भी कमजोर हालत माइनोंरिटीज की है। उनकी हालत को बेहतर बनाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे सही कदम उठाएं और सर्वे कराएं तथा संविधान की भावना के अनुसार आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों को इंसाफ दिलाएं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और अपनी बात यही समाप्त करता हूँ।

SHRI ARJUN SETHI (BHADRAK): Sir, at the outset, I must thank the hon. Minister of Human Resource Development for bringing this Bill on the floor of the House to get the approval of the House so that it becomes a law and specially, 27 per cent reservation is made available to the OBCs. I must say that I am neither a lawyer nor an expert. I am a common man from the rural village. I am going through whatever has been drafted again and again, but I do not find coherence, according to my knowledge. Whatever is said in the earlier part of the Bill, I must bring that to the notice of the hon. Minister.

Sir, clause 2(d) defines 'Central Educational Institution'. It is mentioned in the Act that 'Minority Educational Institution' means an institution established and administered by the minorities under clause (1) of article 30 of the Constitution and so declared by an Act of Parliament or by the Central Government or declared as a minority educational institution under the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004'. It means that this comes under Central educational institutions. That means whatever has been given in clauses 1,2,3 etc., that comes under Central educational institutions and there, this reservation will be applicable. According to my knowledge, when this Bill becomes an Act, reservation will be made available to SCs, STs and OBCs.[\[s52\]](#)

I would like to invite the kind attention of the hon. Minister to clause 4 (c), which says that : "The Act is not to apply in certain cases", and clause 4 (d) states that : "The Act is not to apply in certain cases." On the other hand, in this case, in clause 4 (c) it is mentioned that : "a minority educational institution as defined in this Act". It means that the reservation would not be available in these particular minority educational institutions.

I have already stated that I am neither a lawyer nor a Constitutional expert. I am a layman coming from the villages. I do not understand the difference between the earlier part of the Bill, and all that has been mentioned in clause 4 (c) of this Bill. Therefore, I would request the hon. HRD Minister to enlighten us about this issue, so that I can understand the issue and also tell the masses in my area as to what does the earlier one imply and what does this one imply.

I would like to highlight certain aspects of the reservation policy. It is there in the Constitution itself. If you permit me, then I would like to quote from article 30 (2) of the Constitution.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, you are allowed to quote from it.

SHRI ARJUN SETHI : The hon. Minister of HRD knows everything, but I would like to quote the latter part of article 30 (2), which states that :

"The State shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language."

This is the main point, which I would like to highlight here. I think that the issue -- which I had stated earlier, and the Constitutional provision in article 30 (2) are quite contradictory. How will

it be helpful in the court of law when it comes for adjudication in the court of law?

Secondly, I would like to bring to the notice of the hon. Minister that time and again the hon. Courts, especially, the Supreme Court and the High Courts are saying in their judgement that the creamy layer should be excluded from reservation, etc. Why is the Government or the hon. Minister not bringing this particular law, especially regarding reservation for Scheduled Tribes (ST) and Scheduled Castes (SCs) in the 9<sup>th</sup> Schedule of the Constitution? We know that 15 per cent reservation is there for SCs, and 7 ½ per cent reservation is provided in the Constitution for STs, and this has been implemented all along during these 59 years of our independence. But this particular reservation policy is being debated in the court of law. Sometimes, the hon. Judges in the Supreme Court, and also in different High Courts intervene, and say that the creamy layer should be excluded. At different times they have made this point. Therefore, I would like to ask the hon. Minister. Why are you not bringing this particular Act in the Ninth Schedule? The court's jurisdiction would be debarred from adjudication for the SCs, STs and the OBCs if this is done. It would also guarantee that a particular percentage of jobs would be reserved for these categories, namely, SCs and STs.

[153] So, I would request the hon. Minister of Human Resource Development to consider and bring this particular law into the Ninth Schedule of the constitution so that this argument that is raised in different times is set to rest and SCs, STs and OBCs are guaranteed the reservation that is being given to them.

As per the 2001 census, percentage of the categories of SCs has gone up. It was 15 per cent earlier and now it has become 16 per cent. As of now, the reservation given to SCs is limited to 15 per cent. Why should not the Government consider bringing in an amendment Bill before the House so that reservation is made available to the increased percentage of the SCs and other categories?

I would like to bring to the notice of the Government the staggered implementation that is suggested by the Moily Committee. Such staggered implementation would mean that in the first year, 27 per cent reservation would not be applicable to the OBCs; in the second year also certain students would be debarred from the benefit of reservation. That being the case, how can the Government ensure that the benefits sought to be given to the backward sections of the people reach those people?

With these words, I conclude my speech.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Deputy-Speaker, I rise to support the Bill. While I support the Bill, I must say that this should have been brought much earlier.

The proposal to give 27 per cent reservation for the OBCs itself created some problems in different institutions. Even students of different institutions came on to the streets and created many troubles. All that would not have happened if this Bill had been brought earlier.

Our country has accepted the reservation policy for undoing the injustice caused to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes. But this acceptance is not free from prejudice. It is not accepted by every section, by everyone in the country.[\[r54\]](#)

Caste system still persists in our country. There is a question. Why should there be reservation for the OBC? The Scheduled Castes and the Schedule Tribes may be treated as Backward sections. But apart from SCs and STs, why is OBC treated as a Backward section and why should reservation be provided for the Backward section? In our society, we are not blaming the present generation. Present generation is not responsible for that but the present generation cannot disown the past. They can not disown the present structure of our society; the injustice of our society.

The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are like slaves of our country. They were treated like that earlier, even in different parts of our country. Apart from slavery, there was untouchability. So, OBC is a section which has mainly suffered from untouchability. So, it is needed to distinguish OBC from SCs and STs.

Sir, I would like to say that the proposal of 27 per cent reservation for the OBC is very correct. This is not a new thing. It is contained in the Constitution. It is known to every hon. Member of this august House. In the Directive Principles of State Policy, it is stated that the State would promote with special care educational and economic interests of the weaker sections of the people. We are discussing here about access to education, particularly, access to higher education, not the economic aspect, so far as this Bill is concerned. It is clear and it is known to us that, the Ninety-Third Constitution (Amendment) Bill has been passed in this august House. It was passed unanimously by both Houses of Parliament. It was enacted with a view to promote educational advancement of the socially and educational Backward Classes of our society. So, those special provisions relate to admission of those belonging to the categories in all educational institutions, including private educational institutions, which are aided and unaided by the State. This kind of Bill is going to comply to that. It is our responsibility to support it and get it passed. This is our responsibility and we are going to comply to the Ninety-third Amendment but in this context, I would like to know from the hon. Minister as to what about the private institutions. It is only said about the Government-aided institutions. So far as the Union Government-aided institutions are concerned, it is all right but what about the State-aided institutions? What about the private institutions. Hence, all these should be there.

All points are being debated. Firstly, if 27 per cent reservation is provided to the OBCs, then the quality of education would be diluted. It is not understood. This Bill is for the access to higher education – for admission only. It is not that it would dilute the standard of education or the result of any class or category but only for giving the opportunity to have access to higher education. [\[r55\]](#)

So, what is the harm in it? I do not know why they are hesitating. I think they are working with some prejudice. Their mindset is such, that they think that they should not allow the children from the downtrodden families to sit with their children on the same bench and in the same class. I would say that this is the prejudiced mind. So, the Government should firmly come out with something concrete in this context.

Another point is being raised about the question of creamy layer. So far as our census is concerned, there is no such provision. We do not know which is the creamy layer and which is not. So, raising the question of creamy layer is nothing but diluting the whole process. I am not in favour of it. OBCs should be taken as a whole and 27 per cent reservation should be provided to them.

I thank the hon. Minister for having brought this Bill for consideration and passing. I once again support it.

[R56]

SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN (BHATINDA) :: Sir, I rise to support the “Central Educational Institutions (Reservation In Admission ) Bill, 2006”, which seeks to provide reservation to the SCs, STs and OBCs in Centrally-Aided Educational Institutions. However, there are several shortcomings in the Bill.

India attained independence in 1947. The British flag was lowered and the tricolour was raised. India was partitioned. Many things changed. However, there was no change in the fate of Dalits. Even 60 years after we became independent, the Dalits are still lagging behind in the fields of education, health and employment. The Congress Party is solely responsible for the miserable condition of the Dalits in the country as it was in power for almost 50 years. The Congress Party did not take any concrete steps to ameliorate the plight of the Dalits. It made empty promises and gave false assurances.

I thank the Hon. Minister for having tabled this Bill in this august House. It shows his concern for these deprived people. Better late than never.

Sir, we must strengthen the primary education sector in the country. Only then can these under-privileged sections reap the benefit of reservation. The primary education network in the country is in shambles. Things have come to such a pass that the drop-out rate of SC students is 72%. Among ST students, it is a whopping 80%. The drop-out rate among girl-students is even dismal. 80% primary schools do not have teachers. In many schools, there are only one or two teachers. Unless we bring a radical change in the primary education sector, providing facilities for higher education will serve no purpose.

Equal opportunity should be provided to all children at the primary education level. The syllabus of all education boards should be of the same level. Only then can the downtrodden segments of society reap the benefit of

---

\* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

reservation as outlined in the Bill. Children can compete with each other only when there is a level playing field for all. Otherwise, the children belonging to the weaker and backward sections of society will lag behind in education and employment.

Sir, English should be taught at the primary education level itself. Reservation for the SCs, STs and OBCs should be provided in minority educational institutions as well as in private educational institutions. 'Positive discrimination' is the need of the hour. The Government schools and colleges are in a mess. The private educational institutions constitute 90% of our educational institutions. The poor, the deprived and the under-privileged are a hapless lot. They cannot afford the high fees charged by the private and minority educational institutions. In Punjab, all higher educational institutions belong to the private parties or minorities. These institutions have been unwisely kept out of the purview of reservation. If the Government is really keen to uplift the condition of SCs, STs and OBCs, reservation should also be provided in the private and minority educational institutions.

The Bill has kept the educational institutions where 'Super Specialization' is needed, out of the ambit of reservation. Sir, I appeal to the hon. Minister that this too, should be brought within the purview of reservation. The poor people cannot win seats in these institutions for their children by doling out donations.

The Bill seeks to provide only 15% reservation to the SCs and 7.5% reservation to the STs in the educational institutions. It is a drop in the ocean. 38% population of Punjab belongs to the Scheduled Caste category. Keeping in view the ground reality, at least 25% seats in the educational institutions should be reserved for SCs and STs. In Punjab, there are 33 sub-castes that are included in the category of the Scheduled Caste. More than 50% of the Scheduled Castes belong to the 'Majhabi' and 'Balmiki' groups. Only 2% Scheduled Castes are getting the benefit of reservation whereas several other sub-groups are lagging far behind. They are the poorest of the poor and the most backward among the Scheduled Caste. When late Giani Zail Singh was the Chief Minister of Punjab, he had reserved 50% of the Scheduled Caste seats only for 'Majhabi' and 'Balmiki' groups. However, later on, it was discontinued. As a result, these groups were neglected. The Giani Zail Singh formula for reservation should be revived.

Sir, this Bill should ensure that the poorest of the poor and the most backward among the backwards get the benefit of reservation in educational institutions. The provisions of this Bill should be strictly implemented. Stringent punishment should be handed out to the cringing educational institutions. We have framed a plethora of laws. But, their implementation is tardy and not up to the mark. The 85<sup>th</sup> Constitution Amendment is a glaring instance. It is rather unfortunate that it has not yet been implemented in Punjab.

Sir, judiciary should also be brought in the ambit of reservation. Only the wearer knows where the shoe pinches. Only the deprived and the under-privileged can empathize with their fellow beings. Hence, the scope of reservation should be widened to include judiciary and other such



institutions. Only then can the SCs, STs and the OBCs reap the benefit of reservation as entailed in this Bill

DR. SUJAN CHAKRABORTY (JADAVPUR): Sir, I rise to support the Bill. Indeed, this is a very important occasion when this Bill has been placed in the Parliament. I believe all of us should support it. We should set the reference as we could do at the time of 93<sup>rd</sup> Constitution amendment where almost near unanimity was there for giving Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs - reservation even in private unaided institutions except in minority institutions as defined by article 30 of the Constitution. In this case also, with near unanimity, we should achieve it. I would request all the distinguished Members and Groups of Parliament that they should take the same sort of view on this issue also.[\[R57\]](#)

Sir, basically without reservation in education, in some cases, reservation in employment is getting diluted. We might remember that during the 90s when the proposal for reservation in employment for the OBC was mooted, then one of the very important arguments that were put forth by those who opposed it was what was the utility of reservation in employment without reservation in education. It is now amazing to note that when now reservation is being proposed in education, those same people are opposing it for reasons that are best known to them and is beyond the comprehension of any sensible person. They basically are opposing their own arguments that they had put forward against reservation in employment in the 90s. We must remind them this fact.

According to the Report of the Mandal Commission, the OBC population in the country is estimated to be in and around 52 per cent. This figure could be debated and disputed. Here it is the question of reservation of 27 per cent of seats. This means the scope of reservation is one in every 2 OBC population. Therefore, it does not mean giving full equity to the OBCs in their reservation. So, the opposition does not seem to have much sting in their argument in this regard.

We should consider the fact that there is already some kind of reservation working in the educational institutions today in the name of capitation fees. What should one call this otherwise? Does that not mean buying admission with money? Is it not some kind of a reservation in education for the richer sections of the society? Those who are opposing this reservation, why are they not opposing the reservation arising out of the payment of capitation fee system? I would not be amazed to find that those who are opposing this move of the Government are those people who are running institutions where students are admitted with capitation fees. Therefore, this logic is not tenable.

Sir, this whole question has cropped up primarily because of another reason. The Constitution dictates that there should be education for all and the scope of education may extend from the primary level to the highest level as far as possible. What has been the outcome? Had we achieved this objective, then there would not have arisen this question of reservation of seats for students belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes. But it is

unfortunate that even after 60 years of our Independence we have not been able to achieve that goal of 'education for all' and therefore, this question is cropping up time and again. There is a similar question on reservation in jobs as well. Would it be available and would it be so competitive? The opposition that is coming, I believe, would not have that scope to have that opposition. We should go into the basics. We should look at the society as it is stratified. We should accept the slogan of 'quantity, quality and equity'. If we adopt that approach, I think, things will be better.

In this case, enhancement of seats is being proposed. The Government should say this in a very systematic manner. Reservation along with enhancement of seats would mean that by enhancing the quantity, the Government is adjusting the equity problem coupled with assurance of quality. By increasing the number of seats the Government is allowing students of another section of society, who are not having the scope, to enter into the arena of higher education. Therefore, it is not the question of compromise with quality. It should be seen in proper perspective – along with enhancement of number of seats both the factors of equity and quality is being matched. In a country like India this is most essential. [\[R58\]](#)

While [\[MSOffice59\]](#) supporting this Bill, I have two or three reservations. The population of OBCs is 52 per cent while their reservation is 27 per cent. Why not the real oppressed get a chance? If that be the case, then the exclusion of creamy layer is a must and, by including the creamy layer and by allowing 27 per cent reservation for 52 per cent, we are basically not accepting the scope of the most oppressed sections within the same group. Thereby, I believe, this creamy layer should not be included and should be rather excluded in the whole approach.

The second point is this. This could have been done earlier also. The 93<sup>rd</sup> Amendment has enabled that this can be extended to private institutions also. I would strongly propose that while the creamy layer should be excluded, it should be extended to private institutions also. While enhancing the scope of education, the total quantity, the provision of funds and its arrangements should very carefully be done in such a way that a feeling of deprivation may not come to many of our social groups within the country. From that end, it should be tackled.

I would, therefore, conclude with the approach that basically, in a country like India where caste and class division is there, a number of differences are there within groups, equitable participation of all groups is a must. While doing so, obviously, we have to count the question of quality, and the quantity enhancement may be a solution. Striking a balance between quality and quantity is most important in the whole exercise. I hope this Bill will go a long way for the total advancement of the country as a whole in education, employment and in social development of the country.

From that end, I support this Bill.

डॉ. करण सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में सबसे पहले दलित और पिछड़े वर्गों की चिन्ता करने वाले बहुत ही योग्य मानव संसाधन मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चल रही मनमोहन सिंह

जी की सरकार द्वारा दलित वर्गों में शिक्षा का उत्थान करने के लिए दिए गए वायदे को इम्प्लीमेंट किया और सदन में महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आए। इसके लिए देश के समूचे दलित, पिछड़े और कुचले लोग आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने छूटे हुए रिजर्वेशन की कमी को पूरा किया। यह बात सही है कि मंडल कमीशन या रिजर्वेशन को इस मुल्क में इम्प्लीमेंट करने में सदैव दिक्कतें आईं। जब-जब रिजर्वेशन चालू हुआ, तब-तब ऐसी सभ्यता और संस्कृति वाले लोगों ने इस देश के जीवन को प्रभावित किया। आप जिस दिन इस बिल की परिकल्पना लेकर आए, मंत्री जी के मुंह से निकला हुआ पहला स्टेटमेंट जब अखबार में आया, उसके दूसरे दिन से ही अपने आपको चिन्तक कहने वाले लोगों ने बखेड़ा करके नौजवान साथियों को गुमराह करने की कोशिश की। दिल्ली का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट उसका एक केन्द्र बन गया। सारे देश में इस प्रकार की बात फैलाई जाने लगी जैसे देश में कोई बहुत बुरा काम किया जा रहा है। [\[MSOffice60\]](#) लेकिन सरकार की सूझ-बूझ से जो बिल आप लेकर आये हैं, निश्चित रूप से इन वंचित वर्ग के लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी। यह सही है कि शिक्षण संस्थाओं में खासकर प्रदेशों में पहले से ही अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की समुचित व्यवस्थाएं रही हैं। लेकिन यह बात भी सही है कि पिछले 50 वर्षों में उस आरक्षण का इम्प्लीमेंटेशन सदैव खामियों से भरा रहा चाहे नौकरियों में आरक्षण देने की बात हो या शिक्षण में आरक्षण देने की बात हो। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बहुत सारे मेडिकल कालेज हैं, संस्थाएं हैं जहां अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाता है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी के फैसले, सरकार के मंत्रियों के फैसले के बारे में बहुत स्पष्ट है कि इन वर्गों के वे लोग जो जनरल मैरिट में आते हैं, उन लोगों को आरक्षण के दायरे में शामिल नहीं किया जायेगा क्योंकि वे अपनी मैरिट से आये हैं। **They will be included in the general category.** ओबीसी के बचे हुए 27 परसेंट स्टूडेंट्स को आरक्षण दिया जायेगा। लेकिन आज भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर ओबीसी का कैंडीडेट यदि पहले नम्बर पर आता है, तो उसे रिजर्वेशन के 27 परसेंट कोटा में शामिल करके उसकी इतिश्री कर लेते हैं। उनको बोलने पर वे कहते हैं कि आपको 27 परसेंट दे तो दिया है जैसे कोई खैरात बांट दी हो। इसलिए जब आप इस बिल को लेकर आये हैं, तो मेरी चिन्ता इसकी इम्प्लीमेंटेशन की ओर है।

आज आप देखिये कि आईआईएम, आईआईटी और देश की राष्ट्रीय संस्थाओं के अंदर जो लोग इन संस्थाओं को कंट्रोल करते हैं, जो बुद्धिजीवी बैठे हैं, उन्होंने मीडिया के सामने बखेड़ा खड़ा किया कि हमारे पास आज इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। हम कैसे एक साथ सीटें बढ़ा देंगे? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट इतना बड़ा संस्थान है। वहां प्रति वर्ष 50 या 60 लड़कों को मेडिकल कालेज में एडमिशन दिया जाता है। अगर उनकी संख्या दुगुनी कर दी जाये, मैं स्वयं डाक्टर रहा हूँ, मैंने पेशे से मेडिकल कालेज में अध्ययन और अध्यापन किया है, मैं नहीं समझता कि आज वहां की संख्या को डेढ़ या दुगुना करने से उनके पास किसी हाल, लेक्चरर थैयटर, साइंटिफिक लेबोरेटरीज की कमी है। जिस संस्था पर 300-400 रुपये हर वर्ष खर्च किया जाता है वहां पर थोड़ा बहुत छात्रावास की कमी हो सकती है।

इसलिए मैं समझता हूँ कि आपने इस बिल में प्रावधान रखा है कि जिन संस्थाओं के अंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, ऐकेडेमिक स्टॉफ प्रॉपर नहीं है या उनकी कमी है, तो वे चाहें आने वाले तीन साल में जिसको आपने तीन चरणों में बनाने के लिए स्टेजर किया, उसके लिए भी इम्प्लीमेंटेशन इसलिए जरूरी है कि जो टेक्नीकल एजुकेशन की काउंसिल हैं **whether it is Bar Council Medical Council Of India or All India Institute Of Education.** इन सब काउंसिल्स में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, मुझे आज इस बात का एप्रिहेंशन है कि जिस दिन आप सीट बढ़ायेंगे, वे यह बात लेकर आ जायेंगे कि नहीं साहब, इससे एजुकेशन क्वालिटी डायलूट होगी। अभी तो यहां पर दो लेक्चरर, तीन एक्सरे मशीन और दो लेबोरेटरीज की कमी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कृपा इस बात को आप सुनिश्चित करें। उनकी मौनीटरिंग को आप फेज वाइज फेज वर्ष 2007 से चालू कर रहे हैं या नहीं? कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, जिनके पास बड़े-बड़े लम्बे चौड़े कैम्पस हैं, बहुत लम्बा-चौड़ा स्टाफ है। वे पहले साल में 27 परसेंट आरक्षण, 15 और 7.5 परसेंट करके इसको इम्प्लीमेंट करें। मैं एक दो और बातें करके अपनी बात समाप्त करूंगा।

इसमें सुपर स्पेशलाइजेशन को इस दायरे से बाहर कर दिया गया। हर चीज टुकड़ों में दी जा रही है। पहले आर्ट्स कालेज में दिया फिर साइंस कालेज में दिया। उसके बाद देश की अन्य संस्थाओं में दिया। अब सुपर स्पेशलाइजेशन को बाहर कर दिया है। हमारा कहना है कि जो लड़के एमबीबीएस करेंगे, वही आगे जाकर एमडी, एमएस करेंगे। वही लड़के आगे चलकर कार्डियो वैसकुलर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी और अन्य विधियों में सुपर स्पेशलाइजेशन करें। आप यहां जो दे रहे हैं, वे क्वालीफाई करके आ रहे हैं। सुपर स्पेशलाइजेशन के नाम से फिर लोगों को वंचित किया जा रहा है। [\[MSOffice61\]](#)

बहुत सी संस्थाओं, जिनको इसमें राष्ट्रीय महत्व की और बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट माना जा रहा है, उनके बारे में मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ऐसी बात नहीं है कि इस देश के एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों में ऐसे दिमाग के लोग नहीं हैं जो इन संस्थाओं में जाकर रिसर्च कर रहे हों। आज भी बहुत से ऐसे लोग वहां रिसर्च कर रहे होंगे, आप उनको थोड़ा सा मौका और दीजिए। मेरा निवेदन है कि इन संस्थाओं को भी इस परिधि से बाहर निकालना होगा और इस मुल्क में इन वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण देना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा निवेदन और करना चाहूंगा कि आईआईएम वगैरह ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें आज दो लाख-तीन लाख रूपए सालाना फीस देनी पड़ रही है। मैं समझता हूँ कि एससी,एसटी और ओबीसी के लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है। इसलिए इस फी-स्ट्रक्चर को भी देखना पड़ेगा। कुछ क्रास-सब्सिडाइजेशन का मामला देखना पड़ेगा, जो लोग एफोर्ड कर सकते हैं, उनसे ज्यादा फीस ली जाए और जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको कुछ छूट दी जाए। यद्यपि यह कहना आसान है कि आज देश में बैंक्स एजुकेशन के नाम पर ऋण दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सी बाधाएं हैं। बड़े लोन के लिए आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कुछ गारन्टी देनी चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर भी विचार किया जाए कि इन वर्गों को जब आप बढ़ावा दे ही रहे हैं तो इस फी-स्ट्रक्चर में भी ऐसे परिवर्तन किए जाएं जिससे ये लोग आगे बढ़ सकें। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि सरकार इन संस्थाओं में सीटों को बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए फण्ड्स में कहीं कोई कमी नहीं आने देगी और उनके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही पेनल्टी क्लॉज जरूर होनी चाहिए। जो संस्थाएं इसे इंप्लीमेंट करने में जानबूझकर आना-कानी और लापरवाही करें, उनको चलाने वाले लोगों को किसी तरह का दण्ड देने का प्रावधान होना चाहिए। इस देश में रिजर्वेशन का इंप्लीमेंटेशन ठीक तरह से न हो पाने का एक कारण यह भी है कि उसके पीछे कोई पेनल्टी क्लॉज नहीं रहा है। आदमी नॉट फाउण्ड सूटेबल कैण्डिडेट करके कैण्डिडेट्स को रिजेक्ट कर देता है और पिछले दरवाजे से भर्ती कर ली जाती है। खासतौर पर जिन संस्थाओं को हम ऑटोनॉमस संस्थाएं कहना चाहते हैं, मैं मंत्री जी का ध्यान उनकी ओर दिलाना चाहूंगा। मैं खेद के साथ कहना चाहता हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आज एससी,एसटी और ओबीसी के 5 प्रतिशत भी शिक्षक नहीं हैं जबकि यह ऐसी संस्था है जहां पर लोगों को पूरा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन वहां इस तरह कि लोग बैठे हुए हैं कि पिछले रास्ते से एड-हॉक एप्वाइंटमेंट करते गए, कोर्ट से स्टे लेते गए। अगर आप सर्वे करवाकर देखें तो जिन संस्थाओं को आप ऑटोनॉमस मानकर चला गया है, वहां लोगों ने बहुत मनमानी की है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन संस्थाओं पर जहां तक पॉलिसी मैटर्स का सवाल है, इस ऑटोनॉमी पर सरकार का शिकंजा कुछ कसा जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मानव संसाधन मंत्री जी को, इस देश के दलितों, गरीबों, पिछड़ों की ओर से तहेदिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इन संस्थाओं में इन वर्गों को आरक्षण देने कि लिए यह बिल लाए हैं। इसके लिए यह देश सदैव आपको याद रखेगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have a list of more than 25 Members who are yet to speak. So, those hon. Members who want to lay their speeches can lay their speeches. They can give their written speeches. That will form part of the proceedings of today.

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण देने कि लिए लाए गए इस बिल का मैं और मेरी पार्टी समर्थन करती है।

महोदय, पिछले कई महीनों से एक विवाद चल रहा है कि क्या मेधा पर समझौता किया जा रहा है, क्या मेरिट पर कंट्रोल किया जा रहा है। इस चर्चा के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि क्या किसी ने भारत के इतिहास की समीक्षा की है, भारत की पृष्ठभूमि का अध्ययन किया है। इससे एक चीज उभरकर आती है कि देश में जाति व्यवस्था एक सत्य है, यह इस समाज में उपस्थित है और जाति को लेकर कई प्रकार के विभेद, विभिन्न प्रान्तों में अलग-अलग हो सकते हैं। [H62]

**15.50 hrs**

(Shri Balasaheb Vikhe Patil in the Chair)

कहीं जाति के आधार पर, कुछ जगहों पर भाग के आधार पर यह है, लेकिन मेरिट किसी जाति विशेष की मोनोपली नहीं है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि इसमें समझौता होगा। मैं इस सम्बन्ध में उदाहरण देना चाहता हूँ। दक्षिण के कुछ प्रांतों में, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, वहां कई सालों से शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जा रहा है, विशेषकर उच्च शिक्षा में दिया जा रहा है और कोई समझौता देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए जो इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि यह सत्य है कि भारतीय समाज में जाति के आधार पर विभेद को मिटाने के लिए आरक्षण देना होगा। इस बारे में सरकार का यह एक सराहनीय कदम है और हम इसका समर्थन करते हैं।

इस बारे में मुझे जो आपत्ति है, जो मेरी असहमति है, उसे मैं जताना चाहूंगा। इस बिल में केन्द्रीय शिक्षण संस्थाओं के बारे में कहा गया है, लेकिन प्राइवेट संस्थानों के बारे में क्या होगा? मंत्री जी जवाब देते समय इसे स्पष्ट करें। अगर वह ऐसा करेंगे तो अच्छी चीज कर पाएंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि इसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमें करीब सात-आठ साल लग जाएंगे और इस पर लगभग 16,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मेरी मांग है कि इसे इसकी अवधि इतनी लम्बी न करें। अगर देश की ऐतिहासिक भूल को सुधारना है, जिन लोगों को वार्ड से इस चीज के लिए वंचित किया गया है, उन्हें इसका लाभ देने के लिए आप फेजआउट न करें और एक बार में ही इस पर व्यय करके लागू करना चाहिए।

कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक समुदाय के संस्थानों के बारे में जिक्र है, उन्हें इससे अलग रखा गया है, यह ठीक नहीं है और आपत्तिजनक है। आर्टिकल 30 यह अधिकार देता है कि चाहे लिंग्वेस्टिक माइनोरिटी हो या रिलीजियस माइनोरिटी हो, उन्हें अपने इंस्टीट्यूट्स चलाने का अधिकार है। इन अल्पसंख्यक संस्थानों से जो आय होगी, उनसे ये संस्थान चलाए जाएंगे और जो उनके द्वारा अर्जित सम्पत्ति है, उसमें सरकार हस्तक्षेप न करे, यह प्रोटेक्शन दिया गया है। मेरा कहना है कि अगर हमें संविधान में संशोधन करना हो, तो वह करना चाहिए और उन पर भी यह लागू करना चाहिए।

मैं इस सम्बन्ध में दो-तीन उदाहरण और देना चाहूंगा। दिल्ली में सेंट स्टीफन कालेज है। क्या वहां आदिवासी, हरिजन और पिछड़ी जाति के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, हम जानते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि आज उच्च शिक्षा व्यावसायिकता की ओर जा रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री आपत्ति करते हैं कि विदेशी युनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि एफडीआई उच्च शिक्षा में भी होना चाहिए। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि यह आज का विषय नहीं है। लेकिन जो गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उनका क्या हाल है, यह आप देखें। जैसे मनिपाल युनिवर्सिटी है। कई राज्यों में उसे माइनोरिटी का दर्जा हासिल है, कई में नहीं है। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। धार्मिक आधार पर भी आरक्षण होना चाहिए, ऐसा काम कुछ जगह करने की कोशिश की गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने शिक्षण संस्थानों में और अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी ने भी मुस्लिम वर्ग को आरक्षण देने की कोशिश की थी। [R63] देश की न्यायपालिका ने उसे टुकराया है। मैं आपके माध्यम से सरकार की दृष्टि इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज जिस आरक्षण की बात हम कर रहे हैं, इस आर्टिकल 31 (ए) को संशोधन करके निजी तथा माइनोरिटी में भी लागू करिए, तो आपकी नीयत स्पष्ट हो जाएगी और हम आपका पूरा समर्थन करेंगे।

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Mr. Chairman, Sir, on behalf of Pattali Makkal Katchi and its Founder President, Dr. Aijya who is a crusader for social justice, I support this Bill with unwavering commitment. Our Founder President, who is widely acclaimed as a protector of social justice, has requested me to convey his deep sense of appreciation and congratulation to the UPA Government headed by the world-renowned economist Dr. Manmohan Singh and ably guided by the UPA Chairperson Shrimati Sonia Gandhi and to the hon. Minister of Human Resource Development for piloting this very momentous legislation in this august House today.

Today, the 14<sup>th</sup> December, 2006 will be inscribed in golden letters in the annals of social history of India. It is a historic day, a day of joy and jubilation to all of us and to all lovers of democracy in this country because after attaining Independence nearly 60 years ago, for the first time we are opening up the doors of higher educational institutions of the Central Government to the OBCs who constitute 52 per cent of the population of this country. It is a victory for social reformers like Dr. Kalaignar, the Chief Minister of Tamil Nadu and Dr. Ayya, the Founder President of PMK, who are working for the social development of the people for many years. Perhaps, if Thanthai Periyar and Dr. Ambedkar had been alive today, they would have blessed this Government headed by Dr. Manmohan Singh and guided by Shrimati Sonia Gandhi from the bottom of their hearts because the dreams of these leaders are now becoming a reality. This Government has proved that Thanthai Periyar and Dr. Ambedkar were not mere utopians, but they were pragmatic and practical people's representatives and personalities. Therefore, we heartily appreciate this Government for bringing this Bill today in this House.

Sir, I should appreciate this Government for many things in connection with this Bill. Firstly, we always believe that any growth process without social justice is meaningless. Today, we are talking in terms of 8 per cent or 9 per cent growth rate. But this growth rate should percolate the benefits of growth to all sections of the people equitably so that we get social justice. Through this Bill, this Government has demonstrated to the world and to this country that this Government is working for economic growth with social justice.

Secondly, by opening the doors of opportunities of higher education to the OBCs, this Government has removed an important anomaly or a paradoxical situation that has been developing in this country for the last 60 years. We have made reservation in employment, but unless people of a particular community or class are educated, they will not be able to get employment. Therefore, this Bill, by opening up the doors of higher education to the people, helps us to get employment. Employment gives social status to the people, it provides purchasing power, it provides economic status to the people and therefore this Bill has to be welcomed by all of us.

Sir, one of the criticisms against higher education is that only 6 to 7 per cent of the respective age group of population is enrolled in higher education. When we come to the OBCs, we find hardly 2 to 3 per cent of the people in this age group are enrolled in higher education which is because we have not provided opportunities of education to them for a long time. But this Bill provides this opportunity and therefore the enrolment of the people from these communities as well as in higher education system will improve.[\[R64\]](#)

**16.00 hrs**

[r65] Another reason why we personally thank the hon. Minister for Human Resource Development is that we were given the apprehensive information that the creamy layer will be included in this Bill and we were told that the Standing Committee which perused this Bill has given the suggestion on the creamy layer, but we got a great relief when we found that the creamy layer was not included in this Bill. Therefore, we are happy and thankful to the hon. Minister.

While appreciating the hon. Minister for all these things and when we find that the under representation of OBCs is taken care of, this Bill will help to create an equitable society by equalizing educational opportunity to the people we feel elected. Although, we compliment for all these reasons, we would like to ask one or two questions from the hon. Minister.

The first one is with regard to the Bill. The Bill says, in the first line, that it is applicable to certain educational institutions. Why the word 'certain' should be included is not clear. If you put 'certain' it will provide an opportunity to the bureaucrats to interpret that word in whatever manner they like. Therefore, we feel that to provide for the reservation in admission of students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs to Central Educational Institutions established... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Kindly conclude now.

PROF. M. RAMADASS : Sir, please give me ten more minutes. I have many things to say.

MR. CHAIRMAN: No, please. Time is limited. You should conclude now.

PROF. M. RAMADASS : Sir, I have taken only two minutes.

MR. CHAIRMAN: No, please. Conclude now. You extend the time of the Bill, I do not mind. Please conclude now within one minute.

PROF. M. RAMADASS : Sir, I am talking about equality in this House, but you are not allowing me to speak.

So, we would request the hon. Minister to delete the word 'certain'.

Then, when we make definition clauses, we should do that carefully. In clause (k), the Bill is mentioning the courses which are available in agriculture, medical, engineering and law and it has left out all the courses which are taught in the Central institutions, specially, the Central universities. I wish, this should be taken care of.

According to clause 4, the legislation will not be applicable to some of the institutions of excellence and all institutions in the scheduled areas and at the post Doctorate level. This must also be removed and taken care of.

The most objectionable part of this Bill to us is clause 5, which says that there will be an annual increase of seats. Now, the implication of this clause is that unless seats are increased, OBCs

will not get even a single seat in any of these institutions. For example, today, in the existing situation, if there are 100 seats, SCs and STs get 23, OCs get 77 and therefore, the 100 is divided among them and the OBCs get 0 only.

After passing of this Bill, unless... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Silence please.

PROF. M. RAMADASS: Unless the seats are increased from 100 to 154, the OBCs will not get 27 per cent of seats. Therefore, what is given by the right hand is taken by the left hand and there is no guarantee that all the institutions will increase the seats.

Now, I would like to ask the hon. Minister, what is the need for increasing the seats in other institutions for implementing reservation. When Shri V.P. Singh implemented the job reservation of 27 per cent, he did not increase the jobs from 100 to 154. He did not do that. Therefore, if justice is to be maintained, the seats, as it is, must be given and 27 seats out of 100 seats must be given to the OBCs from the next academic year. I do not think, anywhere in the country or anywhere in the world or a court of justice this will be justified because in the last 60 years, the 52 per cent of the OBCs did not get even a single seat and ten per cent of the people were enjoying 77 per cent of seats.

Today, if you want to stagger, if you want to maintain this parity, what you should do is that you should reduce the seats from 77 to 50 and even then the ten per cent of the people will get 50 per cent. This is inhuman and unjust. In a democratic society, which provides for equal opportunities of education, this is unfair. Democracy is for the people, by the people and if the people cannot occupy the position in education, in employment in proportion to the population, it would not be possible to ensure proper democracy.

MR. CHAIRMAN: Kindly conclude now.

PROF. M. RAMADASS : Therefore, unless this is given, the OBCs have no say at all. [r66] Therefore, I request the hon. Human Resource Minister to try to provide 27 per cent reservation, maybe by keeping the seats as it is. We are not for increasing the seats, not staggering the seats, but to try to give the existing seats and thereby contribute to the social, economic and political development of these people. And the exclusion of some of the institutions is not correct. Clause 5 in our view, must be totally removed. Only then the Bill will have the stated objective of giving 27 per cent reservation. In one place you say 27 per cent will be given, and in the other place you will say it will be given in three years time... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Kindly conclude now.

Shri L. Ganeshan.

PROF. M. RAMADASS : Therefore, it is incompatible with the concept of social justice. Therefore, it should be deleted. For that you will require... (*Interruptions*)



MR. CHAIRMAN: Please cooperate now Prof. Ramadass. You are making good points but there is time constraint.

... (*Interruptions*)

PROF. M. RAMADASS : In our understanding in all the Central Universities of the country, you can straightaway give this 27 per cent reservation. In most of the IITs today, you can give 27 per cent.

MR. CHAIRMAN: Kindly conclude now. It is the same point.

... (*Interruptions*)

PROF. M. RAMADASS : We want this 27 per cent reservation at one go. And we would provide all our support to this Government for providing that kind of social justice. This is what would lead to the achievement of social justice. And I request this Government which is known for its social justice, which is known for social consideration to be able to take this legislation in the right earnest.

SHRI L. GANESAN (TIRUCHIRAPPALLI): Mr. Chairman, Sir, at the very outset, I would like to thank you for giving me this opportunity to express my views which, in certain respects, would be strange for the people from the North.

I am very proud to say that I come from a State which is one of the pioneer States in the field of social justice. All of us talk about reservation. None of us would have been born when the first communal GO was brought in Tamil Nadu in the year 1927. Therefore, Sir, when I say this, my point would be a little bit different. I appreciate, Shri Arjun Singh, the concerned Minister for having introduced this Bill. But at the same time, if I say it is belated, it is delayed, you should not be offended. I cannot say how long it is delayed, how much it is belated. Mr. V.P. Singh, the then Prime Minister provided for reservation in Central Services around 1989-1990. What is the use of making provision for reservation in services when we are not prepared educationally? Therefore, reservation in education should be given first and foremost priority. It was in 1990 and now it is 2006. After so many years, you have brought in this legislation. When we say it is belated, it is delayed, much delayed and yet better late than never. Therefore, to that extent, I welcome it and at the same time I would like to point out certain things.

As far as it is concerned, many great leaders have made much service for social justice. Reservation is not an end in itself; rather, it is only a means to an end. Social justice is the end. For this principle, our great leaders, our Thanthai Periyar – technically speaking in Tamil, PERIYAR means ‘great man’ he suffered. He sacrificed and fought tooth and nail for the sacred social justice. When many of you people never heard about social justice, our own Thanthai Periyar start[[r67](#)]ed the movement for social justice.

Then, great people like Anna and others were there. In 1927 – when I say this, my friends from the Congress Party should feel proud – when the Dravidian Movement people strived for certain rights, you should not feel shy, and you should be proud as much as we are. The communal GO of 1927 was struck down

by the Supreme Court of India as soon as the sacred Constitution of India came into force in 1950 and the High Court of Tamil Nadu and the Supreme Court of India held that the communal GO of 1927 was null and void. Then, we started the fight. Periyar and Anna agitated. I should be very frank. I should have to thank Kamaraj, the great leader. He persuaded Pandit Jawaharlal Nehru - it is a dignified way of saying. Almost he begged Pandit Jawaharlal Nehru, the light of Asia, the first Prime Minister of India, a great leader, a man with forward looking, a leader with farsightedness, and but for whom, India would not have been a democracy by now. I should thank Pandit Jawaharlal Nehru. He had brought in the first amendment to the Constitution in the year 1951. My friends from the Congress Party can feel proud of. Why should they feel shy? ... (*Interruptions*) I know. You come to Tamil Nadu, and not in Parliament.

I am proud to talk about Pandit Jawaharlal Nehru. He was the first man to move the Amendment Bill in the year 1951. The Minister of Human Resource Development has now moved this Bill. I would say that it is very much belated. Pandit Jawaharlal Nehru moved the Amendment Bill in 1951, and by means of which the policy of reservation still lives. Otherwise, everything would have gone to winds. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Kindly conclude within a minute or two.

SHRI L. GANESAN : Sir, I would like to quote the Resolution that was passed in the Tamil Nadu Assembly in 1989. It says:

“This Assembly resolves to request the Union Government to play a major role in the advancement of socially and educationally backward communities as enshrined in Article 340 of the Constitution of India by extending reservation and special provisions under Articles 15 (iv) and 16 (iv) of the Constitution of India, and take a positive role to this important area of social justice expeditiously with due regard to recommendations contained in the Report of the Backward Classes Commission, 1980 headed by Thiru Mandal appointed by the Union Government. ”

This Resolution was passed in 1989 in the Tamil Nadu Assembly. That means, that was passed by Dr. Kalaignar. How long has it taken? Not only that, we have contributed many things towards this cause. Dr. Ramadoss in our State had fought for reservation to most backward communities. He fought. No doubt they have suffered. Some precious lives had been lost.

Subsequently, when Kalaignar came to power in the year 1989, 20 per cent reservation had been provided to most backward people, and we should thank him

for that.[\[R68\]](#)

Sir, now, I am coming to the last part of my speech.

Mr. Minister, even today, you are not taking speedy steps. You are moving at snail's pace. I do not know, why. Why certain exemptions are given in the higher level of education, say, in Clause 4, I do not know. If they are not given exemptions, what harm will be caused, I do not know....  
(Interruptions)

Do you mean to say that it is the experience?... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please address the Chair.

SHRI L. GANESAN : About exemption in admission to provide reservations in higher level of education, I do not know why such certain exemptions are given. You have given exemption for institutions from implementing this reservation. I would like to know why do you have such an exemption. Please simply scrap it up.

In the end, I would request you, Mr. Minister, to be more dynamic. You are dynamic, there is no doubt about it, and we thank you for that. But you kindly be still more dynamic.

Sir, as my hon. friend, Prof. Ramadoss said, you scrap Clause 5, and throw away Clause 4 and implement every other things.

With these few words, I conclude.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Ratilal Kalidas Verma. I would request you to be brief. मेरी सदन के सभी माननीय सदस्यों से दरखास्त है कि थोड़े समय में अपनी बात समाप्त करिए क्योंकि अभी और भी कई स्पीकर्स बाकी है। पता नहीं अभी कितना समय लगेगा? Kindly cooperate.

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जब भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है, समय कम पड़ जाता है। यह बड़े दुख की बात है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: जनजाति का सवाल नहीं है। यह कोआपरेशन की बात है। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से अपील कर रहा हूँ कि थोड़ा कोआपरेट करें।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : सभापति महोदय, आजादी के 58 साल के बाद भी...(व्यवधान) जब भी चर्चा का विषय आता है, समय कम है, बोलने के लिए कम समय मिलेगा।...(व्यवधान) समय कब मिलेगा?

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : कल चर्चा चलाइए अगर आज नहीं होती है।...(व्यवधान)

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : बिल्कुल ठीक बात है।

सभापति महोदय: यह तो बिजनैस एडवाइजरी कमेटी ने डिसाइड किया है। वह तो उनसे बात करनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल लेकर आए हैं, सबसे पहले इसे लाने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अभी शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन की बात है, यह सवाल बहुत गहरा है और बहुत चिंतन करने वाला सवाल है। अभी मैं पार्लियामेंटी एससीएसटी कमेटी का चेयरमैन हूँ, पहले भी चार साल रह चुका हूँ। पूरे देश का हम लोग दौरा करते हैं, चाहे बैंक हों या ऑयल कंपनियां हों या प्राइवेट सैक्टर कंपनियां हों, हर जगह अनुसूचित जाति के भाइयों का रोना ही रोना है। आज आप इसमें एडमिशन के लिए लाए हैं, लेकिन एडमिशन के अंदर काम होगा और जब एडमिशन मिलेगा

तो पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो आगे जाएंगे और आगे जाएंगे तो भारत सरकार की ओर से एससी और एसटीज के लिए जो रिजर्वेशन निश्चित किया गया है, वह पूरा होगा लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 58 साल के बाद भी आज रिजर्वेशन कोटा पूरा नहीं हुआ है। आज भी बैकलॉग है और उसे पूरा करने के बाद नयी पॉलिसी अपनाई जाने वाली थी। लेकिन उसे पूरा किये बगैर नयी पॉलिसी अपनाने लगे। आज सारे देश के अंदर कर्मचारी लोग इससे नाराज हैं।

दूसरी बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, वह यह है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट में जो मुझे आंकड़े मिले थे, 1.1.1965 में एससी और एसटी का नौकरी में क्या प्रतिशत था, In A group, it was 1.64 per cent; in B group, it was 2.82 per cent; in C group, it was 8.88 per cent; and in D group, it was 17.75 per cent. This is the increase, which the research has shown.

आज मेरे पास सन् 2003 के आंकड़े हैं। उसको देखने से आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी इंक्रीज हुई है। ए ग्रुप में 11.93, बी ग्रुप में 30.32 प्रतिशत, सी ग्रुप में 16.29 प्रतिशत और डी ग्रुप में 17.98 प्रतिशत ही इतने साल के बाद वृद्धि हुई है। अभी तो पूरा नहीं हुआ है और यह केवल एससी की बात है। एसटी की हालत और भी ज्यादा दयनीय है।

As on 1.1.96, for ST, the figures were like this. In A group, it was 0.75 per cent; in B group, it was 0.3 per cent ; in C group, it was 1.14; and in D group it was 3.39 per cent. This is the increase in A group, B group, C group and D group.

सन् 2003 में ए ग्रुप में 4.18 प्रतिशत, बी ग्रुप में 4.32, सी ग्रुप में 6.54 तथा डी ग्रुप में 6.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह मैं आपके सामने 2003 के आंकड़े बता रहा हूँ।<sup>[r69]</sup> क्या पोजीशन है, अभी तक रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है। लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, इसके पहले क्रिमीलेयर की बात हो रही है कि इसे हटाओ। इसके पहले रिजर्वेशन न करने देने के लिए सारे देश में आन्दोलन चल रहा था इस बात का दुख है कि एससी, एसटी को जजमेंट से पहले ही जोड़ दिया गया है। यह इस प्रकार से एससी, एसटी के साथ अन्याय किया जा रहा है। मैं 1989 से लोकसभा में इस रिजर्वेशन के लिये मांग करता आ रहा हूँ कि रिजर्वेशन को 9वें शेड्यूल में डाला जाये ताकि उसके साथ कोई छेड़छाड़ न कर सके और उसे रिव्यू न कर सकें। इसे 9वें शेड्यूल में नहीं डालने के कारण हमारे लिये दी गई सुविधा निकल रही हैं।

सभापति जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी कमेटी की ओर से पार्ट टाइम नौकरी देने के लिये कहा गया । कहा गया था कि स्वीपर को प्युन बनाया जाये, वाचमैन मैसेंजर बनाया जाए । मिनिस्ट्री ने सरकुलर निकाला लेकिन बाद में उसे रद्द कर दिया गया, जिससे सारे देश के चौथे वर्ग के कर्मचारी खासकर स्वीपर बहुत दुखी हैं । सरकार बार-बार कानून लायेगी लेकिन देश में ब्यूरोक्रेसी की मानसिकता को बदलने की जरूरत है। यह मानसिकता बदलने की आवश्यकता इसलिये भी है क्योंकि जब हम किसी शहर या राज्य में जाते हैं तो यही स्थिति पाते हैं।

सभापति महोदय, अब मैं पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करता हूँ। वर्ष 2004 के आंकड़ों के अनुसार ए-ग्रुप में एस.सी. के 12.61 प्रतिशत, एस.टी के 3.99 प्रतिशत, ग्रुप-बी में एस.सी. के 13.18 प्रतिशत, एस.टी. के 6.12 प्रतिशत और सी ग्रुप में एस.सी. के 19.74 प्रतिशत तथा एस.टी. के 9.77 प्रतिशत लोग थे। यह इतना कम है। जब प्राइवेटाइजेशन हो जायेगा, तब उनकी क्या हालत होगी, आप समझ सकते हैं। यह बात प्राइवेट वाले मानने को तैयार नहीं हैं। यह किस प्रकार का ब्लेम दिया जाता है कि अगर एस.सी.एस.टी. के अधिकारियों की भर्ती की जायेगी तो उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जायेगी, संस्था का काम खराब हो जायेगा। मैं पूछता हूँ कि काम कैसे खराब हो जायेगा। समय समय पर एस.सी.एस.टी. के लोगों को प्रमोशन नहीं दिया गया, उनकी सी.आर. खराब कर दी जाती है और जब प्रमोशन का वक्त आता है तो इनकी सी.आर. देखकर कहा जाता है कि **You are not fit for this post.** हमें यह जवाब मिलता है। जब उसके बाद हम पूछते हैं तो कहा जाता है कि **There is no suitable candidate available.** कैसे सूटबल कैंडिडेट नहीं मिलता? आज देश में लाखों दलित पढ़-लिखकर बेकार बैठे हुये हैं। वे बी.ए., एम.ए. पास हैं, बी.एड. हैं, टीचर्स हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। उन्हें मात्र दो-दो हजार रुपये मिल रहे हैं। इसलिये मेरी मांग है कि प्राइवेट संस्थाओं में उन्हें नौकरी मिलनी चाहिये।

सभापति महोदय, जब लघु उद्योगों में नौकरी न देने की बात आयी तो हम लोगों ने विरोध किया, धरने दिये और रैलियां निकाली। हम किसी की दया पर नहीं जीते हैं, यह हमारा अधिकार है, कोई भीख नहीं है। हम लोग इस समाज में हजारों सालों से मुसीबतें झेल रहे हैं, इस समाज में हम लोगों पर अत्याचार हुये हैं, इस समाज ने अपमान सहा है, हमारी मां-बहनों के साथ बलात्कार किया है। जब डा. अम्बेडकर ने पूरे देश में ऐसा होते देखा तो उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों का उत्कर्ष करना है तो उनके लिये आरक्षण जरूरी है। यह उनका अधिकार है, कोई भीख नहीं है। एस.सी.एस.टी. किसी भीख के नाते यह अधिकार नहीं मांग रहा है। सरकार की ओर से इस का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिये। सरकुलर निकलने से कुछ होने वाला नहीं है, पौलिसी का इंप्लीमेंटेशन होना जरूरी है।

सभापति जी, एस.सी.एस.टी. कमेटी की ओर से सदन के पटल पर हम जो रिपोर्ट रखते हैं, उस पर अमल नहीं हो रहा है। बैंकिंग वाले नहीं मान रहे हैं, ऑयल कम्पनी वाले नहीं मान रहे हैं। अगर आप क्लास-1 और क्लास-2 में प्रमोशन नहीं देंगे तो वह कहाँ से आगे बढ़ेगा? **There is no reservation for Directorship.** रिजर्वेशन क्यों नहीं है? इसी प्रकार ज्युडिशियरी में रिजर्वेशन होना चाहिये। हाई कोर्ट का सीनियर जज प्रमोशन के लायक था **But there is no reservation in Supreme Court.** जब तक रिजर्वेशन नहीं होगा, उसे न्याय नहीं मिलेगा। हमारी मांग है कि उनका हर क्षेत्र में रिजर्वेशन होना चाहिये। मेरा नम्र निवेदन है कि जैसा मैंने कल बच्चों के बारे में बोला था [§70]। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग विदेशों में पढ़ने लायक हैं, उनका अच्छा प्रतिशत है। इस देश में 80-90 प्रतिशत तक लाने वाले अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं। मंत्री जी, आप हमारे बुजुर्ग एवं सीनियर नेता हैं, इसलिए मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है कि जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 80-90 प्रतिशत लाने वाले स्टुडेंट इस देश में हैं, अगर वे विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें हर तरह की आर्थिक सहायता केन्द्र सरकार की ओर से मिले और 50 प्रतिशत सहायता स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मिले, क्योंकि वहां कोई रिजर्वेशन का विरोध नहीं करता है। आज विदेश में कोई नहीं पूछता, **in which caste you were born. They are not asking any question about the caste. So, I request you to personally sanction some grant for the students of S.C. and S.T. to study abroad so that all the students of S.C. and S.T. will always be remembering you just like they remember Babasaheb Dr. B.R. Ambedkar. It is my personal request to you.**

**SHRI A. SAI PRATHAP (RAJAMPET):** Mr. Chairman, Sir, I thank you for this opportunity. I rise to support the Bill introduced by the hon. Minister Shri Arjun Singhji helping the OBC families with 27 per cent reservation in Central educational institutions. The policy of reservation for the S.C. and S.T. was being implemented through executive order by the Central Government. The present Bill would provide statutory basis for reservation of seats to the S.C. and S.T. Besides, this Bill would provide, for the first time, reservation for students belonging to the Other Backward Classes in educational institutions maintained and funded by the Central Government keeping in view the following recommendation of the Mandal Commission.

“Seats should be reserved for OBC students in all scientific, technical and professional institutions run by the Central as well as the State Governments. This reservation will fall under Article 15(4) of the Constitution and the quantum should be the same as in the Government services, that is 27 per cent. The States which have already reserved more than 27 per cent seats for OBC students will remain unaffected.”

While the recommendation of the Mandal Commission was implemented by the Central Government for reservation in Government jobs, it could not be done for admission in educational institutions.

The Congress Party, which is the champion of the S.Cs., S.Ts., OBCs and the downtrodden had earlier constituted such Backward Classes Commission on 29<sup>th</sup> January, 1953 headed by Kaka Sahib Kalekar, the then Member of Parliament. The Commission had recommended 70 per cent seats in all technical and professional institutions for qualified students from the backward classes. It was decided to leave it to the State Governments to draw up their own OBC lists. It is the Congress Party again which is bringing forward this Bill on reservations. On behalf of the families of OBCs, I convey my sincere thanks and best wishes to the hon. Minister Shri Arjun Singh.

In this connection, I would like to draw to the hon. Minister Shri Arjun Singh that the students from the other communities also are facing lot of inconvenience and difficulties. For example, I would like to mention about my State, the largest communities – Kapu, Balija, Vontari Telaga and other communities are also seeking and they are fighting with the State Government to consider them as Backward Classes. The State is yet to consider them so. It has been referred to the Commission. The Commission is yet to decide the matter. Till such time, the students are facing a lot of inconvenience.

In these circumstances, I would request the hon. Minister and also all the colleagues here and the Union Government to consider such cases and specially the communities that I mentioned which are in large numbers – Kapu, Balija, Vontari Telaga. The students who could also be benefited if they could come in the mainstream of this reservation.

There is no provision providing for reservation for women OBC students. I would request the Government to look into this aspect also and give special attention to the women students of OBCs. [\[MSOffice71\]](#)

Sir, before concluding, I would like to request the hon. Minister that infrastructure-wise, he has to take care of institutions, especially those in township areas. Normally, the students study in district headquarters. Then, they come to cities and well-developed cities. Naturally, there will be difference between them and as compared to the students who have studied in the cities, they may not be as competent. In order to overcome such a thing, I would request the hon. Minister to give adequate funds to the institutions developed in rural township areas.

At the end, I would request the Parliament, which had displayed a rare unanimity in enactment of 93<sup>rd</sup> Constitution Amendment Bill in January to provide

legal support to the policy of reservation in admission to educational institutions, to show the same spirit in unanimously passing the historic Bill which is going to benefit millions of students belonging to the economically weaker sections of our society.

With these words, I conclude.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, reservation is a matter of right. It is a right conferred under the provisions of the Constitution. Unfortunately, there is a tendency to picture this right as a matter of quota. Quota involves concession, but this is not a matter of concession. We have heard about quota of kerosene, quota of food materials etc. They are concessions, but this is not a concession. This is a matter of constitutional right conferred to the weaker sections of the society who are socially and educationally backward. So, please treat it as a quota system, but it is a matter of right. This must be made clear without any ambiguity.

I have many things to mention, but I will take two points – exclusion of minority institutions and exclusion of creamy layer. These two are the basic issues. Before I go into the details about these two major issues, I would say that these two issues will come up for debate for a long time to come.

When this Bill was introduced in the House, the matter went up before the Apex Court in the form of a Public Interest Litigation. Hon. Apex Court made some observations and those observations are pertinent in this context. Let me tell the first observation. On a careful reading of the Supreme Court judgement, we find that they were of the opinion that the concept of creamy layer should be made applicable to OBCs, and not only to OBCs but also to SCs and STs. That is the judgement that was given by the Bench. But the Government came with the clarification that the Supreme Court did not make such an order, and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are not excluded on the basis of creamy layer. They said that this concept of creamy layer is not applicable to them. That was the explanation given and let it be there. The Supreme Court went forward to the extent of saying that it was interference with their rights.

Then, when the Apex Court was hearing a petition about validity of this Bill, they observed that the Government is not having sufficient data. So, they said that let us have the data on the basis of which the Government took the decision of giving reservation in institutions of higher education. It was said in the court that the matter was being investigated by a Standing Committee of Parliament. The court went on to direct the Attorney-General that the Report of the Standing Committee may be placed before that court for verification in a sealed cover. That was the first observation made by the Supreme Court.[\[s72\]](#)

We must understand the point that when a document is placed before this House, then it becomes a public document and there need be no sealed cover for it. Why should there be an issue of sealed cover when the Report has been presented before the House? Why should the court direct the Attorney General to place the Report in a sealed cover? Subsequently, they clarified this issue, but the intention of the Supreme Court was to get the Report even before it was presented in this House. Otherwise, there was no need to make an observation that it must be produced in a sealed cover. Subsequently, they also changed their position on this issue.

We would like to inform the public that the doctrine of Mandal Commission is accepted by a final decision of the Supreme Court, and it is not violating the basic structure of the Constitution. It is a right, and it has been accepted.

As regards the issue of creamy layer whether it could be extended to SCs and STs is a matter to be debated subsequently. The Standing Committee also recommended that the creamy layer should be excluded in this 27 per cent reservation. But the Supreme Court -- in dealing with the Mandal Commission case -- evolved a new formula, and that formula is the creamy layer formula. It is still there. How far it will go -- when we pass this Bill -- is a matter to be seen afterwards? Anyhow, our Party has taken a decision in exclusion of creamy layer in the matter of OBCs. This is a debatable point, which will come up for discussion at a later stage. Therefore, I am not going to pass any remarks on it. But the creamy layer evolved by the Supreme Court is applicable for OBC, and this is the present legal position. Anyway, I leave it to the competent authority to decide on it.

As regards the issue of exclusion of minority institutions, it is a very very important point so far as my State is concerned. Christians and Muslims form the national minority, but in my State, 40 per cent of the population constitutes these two communities. If I may put it, about 80 per cent of all the higher educational institutions are controlled by these 'minority communities'. It would mean that Shri Arjun Singh's law will be available only for these 20 per cent of the institutions, which is a very grave situation.

Who is to decide about the minority community? In clause 2 (f), minority institutions have been defined. Minority institution is defined as a minority educational institution under the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004. I may recall that in 2005, when the amendment to the Constitution, namely, 93<sup>rd</sup> Amendment, was introduced in this House, I raised this very important point that there should not be any blanket exclusion to the minorities. Unfortunately, you have given a blanket exclusion to the minorities. What was the purpose of doing it? I am asking this because it is a very dangerous position. Now, Kerala is reeling under that position.

The Kerala Government has brought in a new Educational Act, and that is being challenged on the definition of minority institutions. If that is upheld, then the whole thing will go. Therefore, I would request the hon. Minister to make a clear stand with regard to the definition of minority communities. Otherwise, this Bill will not help the poor people, the backward community as well as the SCs and STs in my State. It would not help them because it is only 20 per cent there. Why do you give reservation if this is the case? I am asking this because it becomes a futile exercise. We have taken an unwise decision of giving total protection to minority institutions, which is uncalled-for, and unjustified in the nature of the case.<sup>[r73]</sup>

<sup>[r74]</sup>

When that amendment Bill was being discussed in the House, I humbly drew the attention of the House to this fact. The hon. Minister would say, "Who is to decide the minority institutions". The State Government should be given the power to define a minority institution. How are they defined? An institution may be managed by a minority community but about 70-80 per cent of the students studying there are from non-minority communities. The students who are studying in a so-called minority community institution belong to a majority community but the management rests



with the minority community. This is the position. How can we correct that position? Who is to define a minority community institution? It is defined nowhere.

The Minorities Commission will always say that if it is conducted by a trust or some other agency, it is called a minority community institution leaving it to, if I may put it that way, the mercy of God the fate of these poor people belonging to the majority community, the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Hindus as a whole who study in these institutions paying lakhs of rupees as capitation fee and tuition fee. How can we help them? I would like tell the Minister that he has done a very wrong thing in giving complete and total protection to minority communities without taking into consideration the circumstances obtaining in each and every State.

You take the case of the North-East. Christians are in majority there. So, a minority in a particular State may not be a minority in another State. It may vary according to the circumstances available in the State. These two questions, creamy layer and the minority institutions, will form the topic of the discussion. God save the hon. Minister Arjun Singh ji. This is my humble submission.

I support the Bill and we will ensure that the Bill is passed. But I would say that without defining the minority educational institutions, the Kerala State will be in difficulties always.

With these words, I conclude.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Thank you for giving me this opportunity. I rise to support the Bill that has been tabled in the august House. I have got some important points to bring to the notice of the august House.

The Sachar Committee report has been tabled in this House. It clearly states the educational backwardness of the Muslim community. According to Sachar Report, there are 39 per cent OBCs and 0.8 per cent Scheduled Caste in the Muslim community.

I support this Bill which provides reservation in Central Universities to SCs, STs and OBCs. However, I would like to know as to how fair it is to deny the benefits of reservation on the basis of religion, especially after the Government has tabled the Sachar Report in this august House which shows how bad my educational standards are and my conditions are.

I would just like to quote one point here as far as the report is concerned. Page 73 of Sachar Report clearly says, "The percentage of population of graduates, as far as the Muslims are concerned, is 1.2 and those attending P.G. courses is 16.3." It is lesser in Muslims than in dalits also. You are not implementing these minority universities over there. But why is it that I am being denied such benefits? Moreover, the Presidential Order of 1950 contravenes the basic fundamental rights given in the Constitution.[\[r75\]](#)

How is it that only SCs belonging or professing the religion of Hinduism or Sikhism or neo Buddhism are being given reservation? Why not Dalit Christians and Dalit Muslims? This question has to be pondered over by the Government. I would request you sincerely, Sir, that the Government should come forward and ensure that the 1950 Presidential Order, Schedule III is amended. It says that only a person professing Hinduism or Sikhism or neo Buddhism can be classified as Schedule

Caste. How is that possible? This Report of yours clearly says this. There is this argument about Muslims and OBCs. Why is it such a low percentage is there? This has to be looked into.

Lastly, about Jamia Milia University, how is that the present Vice-Chancellor wants to implement this present Bill in Jamia Milia University? Why has the Vice-Chancellor overnight changed this position? Why are we being denied such benefits? I would request you that this issue has to be taken care of. They have applied to the National Minority Education Commission also. It is pending over there. If Jamia Milia University is not a minority University, then, which is a minority university? This is a very important question. These are important points I wanted to bring to the notice of the august House.

I support this Bill. I hope that this UPA Government will take affirmative action and will not deny us reservation under Article 16(4). If people are opposed to reservations to Muslims, they should look into the pre-native history of Article 16(4). It is none other than Sardar Vallabhai Patel, who has stated 'classes' means 'Minorities'. He was the Chairman of that Advisory Committee. Why are Muslims having reservations in Kerala, Tamil Nadu and Karnataka? Why can they not be given reservations nationwide? It has to be done. Literacy rate of 13 per cent of population is only 59. There is a huge difference between literate and educated persons. You can very well imagine 13 per cent of population with a literacy of 59 per cent. Hence, I would request that the Government should come forward with the proposal and I hope that the hon. Minister, when he stands up to reply would respond to this or this UPA Government has to amend 1950 Presidential Order. They have to take affirmative action under Articles 15(4) and 16(4).

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, हम केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण विधेयक), 2006 पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आईआईटी, आईआईएम आदि समकक्ष शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण देना है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को आरक्षण देने के पक्ष में रही है। अन्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को भी आरक्षण देने के पक्ष में रही है, अर्थात् ओबीसी को भी आरक्षण देने के पक्ष में रही है। जहां-जहां हमारी राज्य सरकारें हैं, वहां इस प्रकार के कानून भी हैं। ओबीसी में मुस्लिम ओबीसी भी हैं, जो वहां आरक्षण की सुविधा पा रहे हैं। एक गलतफहमी हमेशा फैलाई जाती है। यह मैंने इसलिए कहा ताकि यह गलतफहमी बहुत से माननीय सदस्यों के मन-मस्तिक से दूर हो जाए। विधेयक की धारा 4(ग) - इस अधिनियम में यथापरिभाषित कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था, अर्थात् इसमें यह लागू नहीं होगा - मैं कहना चाहता हूँ कि देश की आजादी की कल्पना करने वालों ने कभी यह नहीं सोचा था कि इस देश में हिन्दू, मुसलमान, सिख, इसाई को अलगाववाद की ओर ले जाने का काम होगा। परन्तु देश की आजादी के बाद लगातार जब-जब कांग्रेस सरकार को कानून बनाने का अवसर मिला, उन्होंने ऐसे ही कानून बनाए और इस देश में विशोकर मुसलमानों को देश की राष्ट्रवादी मुख्य धारा में लाने का कभी कोई काम करने का प्रयास नहीं किया।

सच्चर कमेटी बनाई गई। उसकी रिपोर्ट आई। उसमें जो बिन्दु उठाए गए हैं, हमारी पार्टी भी इस बात से इंकार नहीं करती कि मुसलमानों की हालत आर्थिक दृष्टि से बहुत खराब है। [MSOffice76] उनकी खराब हालत के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो देश और राज्यों में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जिन्होंने 50- साल तक लगातार राज किया। आज वे 'नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली' वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। इस बिल के जरिये मंत्री जी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में एससी/एसटी और ओबीसी को आरक्षण देने का प्रावधान नहीं कर रहे हैं। वे इसका कारण बता रहे हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 कहता है कि मुस्लिम संस्थाओं या अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को संस्था स्थापित करने, प्रशासन चलाने, धन अर्जन करने, भाषायी और धार्मिक आधार पर शिक्षा देने का अधिकार है। हम कहना चाहते हैं कि इस बिल में अगर यह प्रावधान कर दिया जायेगा कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में एससी/एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिया जायेगा, तो उन तीनों बातों का, जो अनुच्छेद 30 में कहा गया है, उसका कहीं भी उल्लंघन नहीं होगा। संस्था उनकी होगी, स्थापना का अधिकार उनको मिल गया और प्रशासन भी उनका होगा। फिर धार्मिक और भाषायी आधार पर भी वे शिक्षा देने का काम कर सकते हैं। जो संस्था वह चलायेंगे, उससे उनको धन अर्जन करने की भी पात्रता होगी क्योंकि एससी/एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलता भी है, तो सरकार की ओर से आरक्षण से संबंधित जो सुख-सुविधा मिलती है, वह पैसा उन संस्थाओं को दिया जायेगा। यह परम्परागत व्यवस्था है कि वे पैसा देते हैं। उन तीनों बातों का किसी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होगा। इससे एक अच्छी बात होगी कि हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई भी उन शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने लगेंगे। वे आपस में एक-दूसरे के साथ रहेंगे। इससे उनका प्रेम भाव बढ़ेगा, अमन-चैन बढ़ेगा। इस देश में इस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि उन संस्थाओं में ऐसी व्यवस्था की जाये।

इस अवसर पर मैं पूर्व में जो विधेयक पारित किया गया है, उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहले जो विधेयक पारित किया गया, उसमें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में एससी/एसटी और ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया। उसका दुपरिणाम यह हुआ कि पंजाब में जितनी यूनीवर्सिटीज हैं, वे सिख संस्थाएं चलाती हैं। गोवा में जितनी यूनीवर्सिटीज हैं, वे सामान्यतः ईसाई धर्म द्वारा संचालित होती हैं। केरल में मुस्लिम संस्थाओं की ओर से यूनीवर्सिटीज संचालित होती हैं। अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को उन यूनीवर्सिटीज में छात्र-छात्राओं के रूप में पढ़ने से वंचित होना पड़ रहा है। उसका दुपरिणाम यह हो रहा है कि उन छात्रों को राज्य छोड़ कर बाहर जाना पड़ रहा है। कहीं-कहीं ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं कि कुछ छात्र-छात्राएं धर्म परिवर्तन करके उन संस्थाओं में प्रवेश ले रही हैं। मैं इस सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि वह इस प्रकार का प्रावधान करके धर्मांतरण को भी बढ़ावा देने का काम कर रही है। यह निंदनीय है और भारत के संविधान के खिलाफ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में भी एससी/एसटी और ओबीसी को आरक्षण देने संबंधी प्रावधान इस विधेयक में करें। माननीय मल्होत्रा जी और वीरेन्द्र जी ने जो संशोधन दिया है, उसे आप स्वीकार करें।

**सभापति महोदय :** तेजस्विनी जी, आप पांच-सात मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।

**SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH (KANAKAPURA):** For the first time, I find it difficult to cooperate with the Chair but I would try to give respect to the Chair's observation. I thank you for giving me this opportunity to speak.

I would say that the UPA Chairperson, Shrimti Sonia Gandhi, hon. Prime Minister, Shri Manmohan Singh and HRD Minister, Shri Arjun Singh are doing justice. It was a decade long injustice, which they are trying to correct and thereby trying to give justice to 60 per cent of the OBC people who were deprived of this Constitutional guarantee so far. We should bow our heads to them.

The Mandal Commission says that 52 per cent of our population is OBC but in reality it is 60 per cent. When the rest of India is enjoying the fruits of independent India, why 60 per cent of India should remain backward? Let my friends first give me an answer to this.

The word 'class' says, it is the divide between the rural India and urban India. Health, education, economy, social equality, civilization, all are vital factors which keep a society in balance. [\[R77\]](#)

Today, why is this imbalance? Opportunity is the greatest thing in the society. Rural children are unable to get proper education today. They are unable to get proper food. That is why, we have to achieve the spirit of the Constitution. It is the right of the OBCs. It is not a privilege for the OBCs to get 27 per cent reservation. That is why, with pride our forefathers like Pandit Nehruji and Dr. Ambedkarji brought the first amendment in 1951 to correct this measure. The Directive Principles of the State enshrined in the Constitution direct the States to take care of the weaker sections including OBCs and save them from social injustice. That is why, we brought this Bill. It is because education is playing a vital role and education is a leveler. Today, there is no awareness. That is why, when the Bill for reservation for OBCs was introduced, a section of the society behaved in a manner as if heavens are going to fall and as if a crime is being committed on this Earth. If this 60 per cent people of the population rise and start protesting, where will be peace in the society? That shows their ignorance even today. We have not divided the society. Who has divided the society? As long as society is there, there will be caste and religion also. But that should not deprive rural India or poor people or OBC people of their constitutional right.

My second point is that today there is an urgent need to increase seats in the universities and educational institutions. There is a great demand for the education. Why our children, brothers and youths should be deprived of having higher education and quality education? After all India needs to take everybody together on this great motherland. Once I heard that the quality will suffer. Who has built this nation, your infrastructure and your buildings? All these things have been built by everybody. They have not been built by one section of the people.

As far as judicial battle is concerned, I can understand that it is a decade long battle. We have a history of that. Why have we come to Parliament? We have come to Parliament to correct these mistakes. We are representing different sections in Parliament. We are facing different situations. So, we have to correct this inequality in the society. It is the order of the day, need of the day and the demand of the day that we must provide proper reservation to the OBCs. Today, we are running Scheduled Castes and Scheduled Tribes Forum to address that problem. Can we answer why such a social cry and untouchability is there even today in this civilized society even after 60 years of our Independent India? As long as we are unable to correct these social evils, it is our duty to protect their basic rights. That is why, I once again compliment the Minister for bringing this brave Bill. In our State we have achieved this and for that I compliment the Government of Karnataka. I would appeal to all my friends from different Parties to accept this. We are seeking only 27 per cent reservation for 60 per cent population. So, there is nothing wrong that we are doing. All of us should raise our heads in pride that at least we are doing justice after 60 years through this Bill. I would like to see equality in this Independent India.

With these words, I would like to thank the Chair for giving me this opportunity.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Sir, I thank you for giving me this opportunity. The Preamble of the Constitution of India begins with assuring social, economic and political justice. The letter and spirit of the social justice has been reaffirmed by the first constitutional amendment moved by Panditji. Article 15(4) of the Constitution provides for special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Under Article 340 of the Indian Constitution, the Kelkar Committee and the Mandal Commission were constituted by the then Government.[\[R78\]](#)

### **17.00 hrs**

Based on the recommendations of the Committee, the Government had given 27 per cent reservation for the persons belonging to the Other Backward Classes in Government institutions and Public Sector Undertakings. But at that time they did not provide for reservation in the educational institutions. In the year 1990 Shri V.P.Singh was the Prime Minister and Shri Ram Vilas Paswan was the Minister of Social Justice and Empowerment. At that time we were studying in University and had questions in our mind about this issue. We felt that without reservation in education, reservation in jobs would have little value. How can people belonging to Other Backward Classes occupy higher positions without having the requisite higher education? How could they become eligible to fill such posts? Since then there have been agitations going on, this has been delayed but even then now the hon. Minister has brought this legislation and I would like to appreciate his efforts for that.

This was also an assurance given in the Common Minimum Programme. The UPA Government had made a promise to the country, to the people belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes that 27 per cent reservation would be provided to them in educational institutions without any control. But according to this Bill, if one were to look at Sections 4 and 5, it would be seen that the Government proposes to put some speed breakers by saying that there would be some quota in the first year and then some quota in the subsequent years. I would like to appeal to the Government not to put these restrictions and provisions of Sections 4 and 5 may be removed from the Bill. The promise made by the Government in the Common Minimum Programme is that they would provide 27 per cent reservation for people belonging to the Other Backward Classes; 15 per cent for people belonging to the Scheduled Castes and seven and a half per cent for people belonging to the Scheduled Tribes. Then, why is the Government now putting these restrictions?

### **17.02 hrs**

(Shri V. Radhakrishnan *in the Chair*)

Though my Party appreciates the effort, yet would like to request the Government to remove such restrictions. The Forum of the OBCs led by Shri Hanumantha Rao met the hon. Minister and the hon. Minister also was kind enough to accede to their representation. My demand is that provisions as contained in Sections 4 and 5 of the Bill should be removed and only then the people

belonging to the Other Backward Classes, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes would be happy. These are my suggestions.

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री, प्रधान मंत्री और यूपीए की अध्यक्ष सोनिया जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने काफी जद्दोजहद के बाद इस विधेयक को यहां रखने का काम किया है। केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था विधेयक, 2006 का मैं तहेदिल से स्वागत और समर्थन करता हूँ।

आजादी के 59 वां बाद जो अधिकार और हक गरीबों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, एस.सी. और एस.टी. के लोगों को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया। देश की आजादी के बाद चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में देश की सम्पत्ति रही, कला, संस्कृति और शिक्षा रही। आजादी की लड़ाई में देश की इस 75 प्रतिशत आबादी ने जी-जान लगाकर काम किया था और यह सपना देखा था कि जब देश आजाद होगा तो हमें भी मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने जितने अधिकार इन लोगों को देने चाहिए थे, वे नहीं दिए गए। इसका नतीजा यह है कि इन लोगों को उनके लिए लड़ना पड़ रहा है।[\[R79\]](#)

महोदय, आजादी के बाद यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। संवैधानिक अधिकारों में साफ तौर पर कहा गया है और इसका प्रावधान है। हम बाबा साहब अम्बेडकर को याद करना नहीं भूलेंगे जिन्होंने कहा था कि जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उन्हें विशेष अवसर मिले और उस विशेष अवसर के रूप में यह आरक्षण मिलने जा रहा है। पिछड़े वर्ग को नौकरियों में आरक्षण के लिए दो बार आयोग बनाया गया - पहली बार काका केलकर की अध्यक्षता में और दूसरा 1980 में श्री वी.पी.मंडल की अध्यक्षता में आयोग बना था। 1980 में उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। लगातार 10 वर्षों के संघर्ष के बाद जब श्री वी.पी. सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब उस मंडल आयोग को लागू करने का प्रयास उसने किया गया। न्यायालय में मामला गया और न्यायालय ने भी निर्णय दिया और जो आरक्षण के प्रावधान थे, उन पर मुहर लगाई, जिससे 1993 में इन्हें नौकरियों में आरक्षण मिला।

अभी बीजेपी के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि जब से जनसंघ बना है, तब से हम आरक्षण के पक्ष में हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो बहाना कर उन्होंने कमंडल निकाल दिया और देश को जलाने का काम किया। अगर मंडल लागू नहीं होता तो कमंडल नहीं निकलता। यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है - कहने को कुछ और, और करने को कुछ और। ये लोग बहुत परेशान और बेचैन थे। बाद में जब इनकी सरकार बनी, तब ये आरक्षण लागू करने की हिम्मत जुटाते। ये समर्थन नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, आज भी विरोध कर रहे हैं। कोई भी नीति नीयत से बनती है और यूपीए सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ हैं, इसीलिए उसने 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करके, विरोध करने वालों के मुंह पर कालिख पोती है। मुझे दर्द के साथ कहना पड़ रहा है, मैं हमारे नेता लोहिया जी की चर्चा यहां करना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा था कि सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वह राजा का बेटा हो या रंक का बेटा हो, प्रधानमंत्री का बेटा हो या चपरासी का बेटा हो। मैं उस व्यक्तित्व को नमन करना चाहता हूँ। यदि हम सबको बराबरी पर लाना चाहते हैं और समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो हर चीज में बराबरी प्रदान करनी पड़ेगी। यदि शिक्षा नहीं देंगे तो ये लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। जब नौकरियों में आरक्षण दिया गया, तो कहा गया कि शिक्षा में आरक्षण दीजिए, नौकरियों में आरक्षण मत दीजिए, मेधा की कमी है। आप शिक्षा में बराबरी लाना चाहते हैं, एक तरफ बच्चे बड़ी-बड़ी इमारतों में पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ कई स्कूलों में छप्पर तक नहीं हैं। एक तरफ बच्चे सनमाइका और महंगे बेंचों पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईंटों पर बैठकर बच्चे पढ़ते हैं। एक तरफ स्कूलों में बच्चों को हलवा पूरी खाने को दे रहे हैं और दूसरी तरफ नमक के साथ रोटी खाने के लिए भी नहीं है। इस दो तरह की व्यवस्था में कैसे गरीब बच्चे आगे निकल सकते हैं। मैं दावा करना चाहता हूँ कि एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चों को समान रूप से अवसर प्रदान करें, अगर समान सुविधाएं बच्चों को दी जाएंगी तो इनकी मेधा दूसरे बच्चों से 20 गुना ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। लेकिन व्यवस्था ऐसी रही है, जिसके अंतर्गत हमने इन्हें बहिष्कृत करने का काम किया है, अपमानित करने का

काम किया है।<sup>[MSOffice80]</sup> <sup>[a81]</sup> हम इन्हें पिछड़ा, ओबीसी और दलित कह कर अपमानित कर रहे हैं। गांवों में आज भी अपमान सहना पड़ रहा है। हमारा संर्धा और लड़ाई जारी रहेगी। आपने आरक्षण दिया, लेकिन उसमें 27 परसेंट कट कर दिया और धारा लगा दी कि फेज वाइज करेंगे। मॉयली रिपोर्ट को देखने के बाद हमें अफसोस हुआ। पता नहीं किस भावना से वह रिपोर्ट पेश की गई है। अगर आपकी मंशी सही है तो फिर किस लिए डरते हैं? आप उसे लागू कीजिए। पैसे का प्रावधान हो जाएगा। आपके पास हजारों करोड़ रुपए हैं। दूसरी चीजों से पैसा काटिए। अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग आगे बढ़ें, तो उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था कीजिए। यह कह कर कि जगह की कमी है, पैसा नहीं है, एक साथ कैसे हो जाएगा, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर उनके साथ अन्याय होगा। जिस प्रावधान के अन्तर्गत आप फेजवाइज 27 परसेंट आरक्षण देना चाहते हैं, उस पर पुनर्विचार कीजिए। उनको एक साथ देने का काम कीजिए, यह मेरा निवेदन होगा। यूपीए के कॉमन मीनिमम प्रोग्राम में सोशल जस्टिस की बात कमिट की गई है। उसके अनुसार आरक्षण का लाभ उन्हें देने का काम करें। आप कुछ संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं देंगे। आपने कैसे आकलन कर लिया कि पिछड़े वर्ग के बच्चे उन संस्थानों में जाकर ठीक काम नहीं कर पाएंगे? कौन से पैमाने से मापने का काम किया? यह अन्याय है। आप कुछ संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। केन्द्रीय स्तर के जो विद्यालय हैं, नवोदय तथा केन्द्रीय विद्यालय हैं, उनमें आरक्षण का प्रावधान किया है या नहीं, वह इस बिल से साफ नहीं होता है। मैं समझता हूं कि उच्च शिक्षा में आप रिजर्वेशन कीजिए।

अंत में निवेदन करना चाहूंगा कि आपने सच्चर कमीशन बनाया था, उसकी रिपोर्ट के अनुसार इस बात को स्वीकार किया गया है कि मुसलमानों और अल्पसंख्यक वर्ग की स्थिति शिक्षा और दूसरे कई मामलों में अच्छी नहीं है। जिस वर्ग की आबादी 12-13 परसेंट है उनके उत्थान के लिए आपने आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की? अगर आरक्षण की व्यवस्था की होती तो उनके साथ न्याय होता। आप इसमें संशोधन करें। जिस वर्ग की सबसे अधिक आबादी है, उनको राट्र की मुख्य धारा में लेकर आएं। इसलिए उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं और माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह इन कमियों को दूर करें। कहने वाले तो कहते रहेंगे, विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे, देश के लोगों ने आपको मैंडेंट दिया है, आप उनकी आशा को साकार करें। वे लोग राट्र की मुख्य धारा से आज तक जुड़ नहीं पाए हैं। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय यूपीए चेयरपर्सन, माननीय प्रधान मंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) :** आदरणीय सभापति महोदय, केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए जो विधेयक यहां पेश किया गया है और उस पर चर्चा करने का मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।<sup>[a82]</sup>

इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह जी, यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और मानव संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी को बधाई देता हूं। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि स्वराज हमें 59 साल पहले मिला था, लेकिन इतने सालों बाद अभी भी हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को न्याय देने जा रहे हैं, इसमें बहुत विलंब हुआ है। मैं बहुत तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लोगों को आजादी के बाद जो मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया है। अपर क्लास के लोगों ने हमारी आजादी का हिस्सा बहुत खा लिया, बहुत हजम कर लिया, इसलिए अब हमें ज्यादा न्याय देने का समय आ गया है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि अभी सिर्फ साढ़े सात परसेंट एसटी को, 15 परसेंट एससी को और 27 परसेंट ओबीसी को देने से काम नहीं चलेगा। यदि जनरल कम्युनिटी की पॉपुलेशन आज बढ़ गई है तो जरूर एससी, एसटी और ओबीसी की पापुलेशन भी काफी बढ़ गई है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि अब आरक्षण की मात्रा बढ़ाकर अनुसूचित जाति के लिए 20 परसेंट, अनुसूचित जनजाति के लिए

कम से कम 15 परसेंट और ओबीसी के लिए कम से कम 30 परसेंट रिजर्वेशन कोटे में वृद्धि करनी चाहिए तभी इस सोसायटी के लोगों को न्याय मिल सकेगा।

मैं एक और मांग करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जहां ज्यादातर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लोग हैं, वहां अलग से आईआईटी, आईआईएएम, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खोलने की जरूरत है। मैं खास तौर से बोडो लैंड के लिए अलग से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग करता हूँ। मैं वहां के लिए एक आईआईटी, एक आईआईएएम, एक सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स की मांग करता हूँ। आज हमारे वहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एक भी पॉलीटेकनिक इंस्टीट्यूट नहीं है। इसलिए बोडो लैंड में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और एम्स की तरह का इंस्टीट्यूट खोलने की जरूरत है। हमारे प्रदेश में जितने बोडो लड़के और लड़कियां बोडो भाषा के माध्यम से शिक्षा ले रहे हैं, उनके लिए अच्छे स्कूल का प्रबंध नहीं किया गया है, वे काफी संख्या में प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और ऐसे गैर सरकारी स्कूलों को कोई सरकारी अनुदान नहीं दिया जाता है। So, Sir, through you, I would like to appeal to the hon. Minister of Human Resource Development to pressurize the Assam Government to bring all the non-provincialised primary schools, middle-level English Schools, High Schools and Higher Secondary Schools under provincialisation system. हमारे वहां शिलांग में नॉर्थ-ईस्टर्न इंदिरा गांधी मेमोरियल रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस है, लेकिन इसमें रिजर्वेशन कोटा लागू नहीं होता है। अगर आरक्षण लागू नहीं होगा तो उस संस्थान में ट्राइबल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए मौका कैसे मिलेगा? वहां भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। So, I would like to appeal to the Government of India to bring this premier Health and Medical Science Institute also within the ambit of the Bill for providing reservation at least to the Scheduled Tribes of North-Eastern region.

[r83]

MR CHAIRMAN : Your time is already over.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Shri S.K. Kharventhan wants to lay his written speech on the Table of the House. He is allowed to lay his speech. I thank him.

SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI) : I am thanking the Hon'ble Prime Minister of India Shri Manmohan Singhji and Hon'ble Madam Soniaji and our Hon'ble Minister Arujun Singhji for the introduction of this landmark Bill for the welfare of scheduled castes, the scheduled tribes and other backward classes of citizens of this country.

As per a 3<sup>rd</sup> amendment during the year 2005 the clause 5 was inserted in Article 15 of our Constitution, with a view to promote the educational advancement of the socially and educationally backward classes of citizens, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes through special provisions relating to assistance of students belonging to these categories in all educational institutions, including private educational institutions whether aided or unaided by the State.



Originally there was no such provision in Article 15 of our Constitution. In the case of Champakam Dorairaj, state of Madras set aside the reservation of seats in educational institutions on the basis of caste and community provided by the then Government of Madras and by great leader Shri K.Kamaraj. Then late leader Shri K.Kamaraj requested Shri Jawahar Lal Nehru to amend the constitution to provide reservation for weaker section in the society. Shri Jawahar Lal Nehru the then Prime Minister requested Dr. B.R.Ambedkar the then Union Law Minister to amend the article 15 of our Constitution. Dr.B.R.Ambedkar amended the article 15 and inserted sub clause 4 and it provide a blanket provision that nothing shall prevent the state from making special provision for the advancement of SC/ST and OBC people.

About 72% population and fervent work force of the country is still living in rural India. Out of the total rural workforce 39.50 per cent are cultivators and 33.20 per cent are agricultural labourers. The agricultural labourers needs reservation but it continues to by-pass them. As regards cultivators, all those upon the semi-medium size of holdings and who are wholly dependent on agriculture and other connective activities deserve the benefit of reservation.

---

\* The speech was laid on the Table

Mandal Commission refer to the need for reservation in Educational Institutions. There are dozen recommendations in the report, which propose, apart from reservation in Government jobs and educational institutions, separate coaching facilities for students aspiring to enter technical and professional institutions and special vocation-oriented education facilities to upgrade the academic and cultural environment of OBC students.

The Reservation in education and public service began in the Madras Presidency as early as 1831. The British Rulers initiated this in response to demands from various groups. Then this movement was developed and achieved by late Leaders Shri K.Kamaraj and Shri E.V.Ramasamy Naicker. Tamil Nadu had 69% reservation even before the Mandal Commission recommendations. In Andhra Pradesh it was initiated in the 1970s while in Gujarat and Maharashtra the schemes were formalized 1980s and 1990s. At present Karnataka is having 50 per cent reservation out of which 32% for OBCs and 18% for SCs and STs in all the higher education institutions. From 1992 to 2002 over 25000, OBC students were able to get admission in professional colleges in Karnataka. Andhra Pradesh has 49.5% reservation and Kerala has approx. 50 per cent reservation for its OBC, SC and ST populations.

The present Bill pave way for poor rural students to get admission in Central Educational Institutions. By introducing reservation in Central Education Institutions whether it will affect the merit? Certainly not. Thousands of youths from rural areas are working in IT Sector throughout the world. Most of them hail from very poor families and studied in corporation schools or panchayat union schools. Some anti-reservationists are arguing that OBC communities cannot throw up sufficient number of bright students to fill up their quotas in Higher Education Institutions. It is totally false. Assuming that 5000 students were to be admitted to IIT's every year and 27 per cent reservation was made for students belonging to OBCs, it would work out to 1350 seats for the OBCs. The number of ITTs aspirants from the OBC communities is about one lack. Reservation

exists in many well known universities yet the quality or prestige of these universities has not been vitiated.

Even in USA affirmative action was promoted by President Lydon Johnson in 1974 to promote American Blacks who were deprived of most opportunities. The affirmative action was successful in Japan, Former Soviet Union, Former Socialist Countries of East Europe along with Cuba and Vietnam.

Immediately after the revolution, Lenin proclaimed the affirmative action known as “KORENIZATSIIS” to provide affirmative preferences for non-Russians, Backward Ethnic Groups and poor Russians.

In this juncture, I want to mention the words of Rabindranath Tagore: “If our political progress is to be real, the underdogs of our society must be helped to become men”.

Through this Bill our UPA Government decided to uplift the poor students to higher level.

Out of 110 crore population nearly 90 crore are poor OBCs, SCs and STs. All are thanking our Hon’b le Minister Shri Arjun Singhji for this landmark historic achievement.

**श्री संतो गंगवार (बरेली) :** सभापति महोदय, बहुत से विद्वान वक्ताओं ने यहां बहुत सी बातें यहां रखी हैं, परंतु लगता यह है कि कांग्रेस की सरकार को जब वोटों की चिंता होती है या लगता है कि किसी विशेष बिरादरी के वोट हमसे न निकल जाएं, तब ऐसी चीजें वे आधे-अधूरे मन से लेकर आते हैं। मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन मंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगा कि आज सुबह ही लॉर्ड मेघनाथ साहा जी का एक लैक्चर हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की प्रगति न होने का एकमात्र कारण यह है कि यहां की प्राथमिक शिक्षा उपयुक्त और दुरुस्त नहीं है। देश में छः लाख से अधिक गांव हैं। हम लोग जिस समाज की चिंता कर रहे हैं, उस समाज के सौ में से 75-80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, लेकिन उसका लाभ उनके बच्चों को नहीं मिल रहा है। स्कूलों में कोई व्यवस्था है या नहीं, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं और गांव का व्यक्ति एक लाख रुपये देकर अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। जब आप शैक्षणिक संस्थाओं में उच्च स्तर पर आरक्षण करेंगे तो निचले स्तर का व्यक्ति वहां तक कैसे आ पायेगा। मैं माननीय सदस्य, श्री राम कृपाल यादव और श्री रघुनाथ झा जी से पूछना चाहूंगा कि गांव के बच्चे कितने प्रतिशत आते हैं और कैसे आते हैं और इस आरक्षण का उस बच्चे को कैसे लाभ मिलेगा।

यह बात पूरे देश में सर्वविदित हैं कि अल्पसंख्यक चरित्र के जितने विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में सारे लोग लालायित रहते हैं कि उनके बच्चे का उसमें दाखिला हो जाए और हमें अपने बच्चे के लिए अच्छी दिशा मिल जाए। उसमें भी हम लोग अपने बच्चे का दाखिला नहीं करा सकते और गांव के स्कूल में पढ़ाकर हमारी वर्तमान सरकार ने पहले ही मान लिया कि 80 प्रतिशत बच्चों के पास दिमाग नहीं है। इसलिए आपने जो 17 उच्चस्तरीय संस्थाएं छांटी हैं, उनके लिए आरक्षण लागू नहीं रहेगा, जबकि विज्ञान यह कहता है कि सभी आदमियों के दिमाग का आई.क्यू. एक सा रहता है और हर अगली पीढ़ी का आई.क्यू. बढ़ता है। बच्चा चाहे गांव में पैदा हो या सबसे निचले स्तर पर पैदा हो, चाहे किसी बड़े परिवार में पैदा हो, परंतु दुर्भाग्य यह है कि यह सरकार हमें बांटने का काम कर रही है और ये आरोप लगाते हैं कि हम विरोधी हैं। हम कहते हैं कि एन.डी.ए. सरकार में आरक्षण की सारी प्रक्रियाएं हमने बिना किसी भेदभाव के सही ढंग से लागू कीं, सब व्यवस्थाओं में हमने सही ढंग से काम किया, लेकिन उसके बाद भी जब लगता है कि फलां नाराज हो रहा है, इसलिए सच्चर समिति भी आ जाए, उसके हिसाब से भी आरक्षण हो। अब यदि सरकार में हिम्मत हो तो सच्चर समिति के ऊपर बहस करा ले। अल्पसंख्यक कौन होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में बहस कर ले, परंतु सरकार में बहस करने की इच्छा नहीं है और इस ढंग से आधे-अधूरे मन से इन बातों को लेकर आते हैं, जो इस बात को साफ जाहिर करता है कि हम राजनीतिक आधार पर फैसला कर रहे हैं। परंतु इस राजनीतिक आधार के फैसले का लाभ इस समाज के दो-तिहाई तबके को कितना मिलता है। मैं गांव में रहता हूँ और आप लोग भी गांवों में रहते हैं, आप जरा सर्वे करके देखिये कि गांव के अंदर कितने बच्चे आगे आकर सही ढंग से पढ़ पाते हैं। कहीं ऐसा है कि एक परिवार के सारे बेटे आई.ए.एस., डाक्टर और इंजीनियर हैं और कहीं किसी परिवार में यदि दस बच्चे भी हैं तो उनमें से एक भी हाईस्कूल पास नहीं है। अब इस बात की ओर कौन ध्यान देगा। हम उन बच्चों को ही अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते, है, हम उन बच्चों को ही आई.आई.एम. में एडमिशन देना चाहते हैं। हमारी सरकार ने जब आई.आई.एम. की फीस कम करने का काम किया तो पूरे देश में एक बवंडर मच गया। सब लोग कहने लगे पता नहीं क्या कर रहे हैं, जबकि आपने उस फीस को कम करने का काम नहीं किया, बल्कि उसे बढ़ाने का काम किया। आप यह जरूर कहते रहे होंगे कि हम इसमें सहूलियतें देंगे, सहायता देंगे, सारे काम करेंगे, परंतु इसका वास्तव में लाभ कहां मिल रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसे इस ढंग से लाइये जिससे वास्तव में समाज के हर तबके को लाभ मिल सके। आप जो आरक्षण ला रहे हैं, इसमें किसी का विरोध नहीं है, परंतु इसका वास्तविक लाभ माननीय अर्जुन सिंह जी तभी मिल पायेगा कि जो अल्पसंख्यक चरित्र की शैक्षणिक संस्थाएं हैं, आप उनमें आरक्षण नहीं देंगे, मैं जिस जिले में रहता हूँ, वहां 15 विद्यालय ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक चरित्र के हैं और उनमें दाखिले के लिए लाइनें लगती है। ... (व्यवधान) दिल्ली के अंदर ऐसे सैकड़ों विद्यालय हैं, जहां हमारे बच्चे का दाखिला नहीं हो सकता है, जहां आप एक-दो लाख रुपये जमा करें तो भी मुश्किल से दाखिला होगा[MSOffice84]। मेरा सुझाव यह है कि आप अपनी नीयत को साफ करिए और जब तक आप अपनी नीयत साफ नहीं करेंगे तब तक इस समाज को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये केवल कोरी बातें हैं। अगर इन बातों के आधार पर हम चाहें कि समाज में बहुत भारी परिवर्तन कर दें, तो वह परिवर्तन संभव नहीं है। इस आधार पर ही बच्चे अपने आप कलैक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं और सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कृपा की बात हो रही है। लेकिन कृपा की बात यह है कि सबको समान स्तर मिले, सभी को बराबरी का भाव मिले।

एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जब कालेलकर जी की रिपोर्ट आई थी, उस समय ओबीसी की संख्या 2000 थी। बाद में ओबीसी की जातियां 6500 हो गईं - यह 6500 कैसे हो गई? क्या नयी जातियां बन गईं? लोगों को लग रहा है कि हमें फायदा मिल रहा है, इसलिए हम अपनी जातियों को इसमें शामिल कर दें। इस बारे में आपकी राय बननी चाहिए कि वास्तव में कौन सी जातियां एससी, एसटी और ओबीसी के लिए योग्य हैं या योग्य नहीं हैं और उसके हिसाब से आपको फैसला करना चाहिए, क्योंकि इसमें दिक्कत यह होती है कि जब हम आरक्षण देते हैं तो उसका फायदा वे लोग उठा लेते हैं जिन्हें वास्तव में सामान्य जाति में रहना चाहिए और जो वास्तव में पिछड़ी जाति के हैं, उनको वह लाभ नहीं मिल पाता है।

मैं यहां अधिक न बोलते हुए केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने अमेंडमेंट में यह दिया है कि आप अल्पसंख्यक चरित्र की संस्थाओं को इसमें शामिल करें। शहर के अंदर पढ़ने वाला बच्चा, जो कम्प्यूटर ऑपरेट करना जानता है और कक्षा 6 का बच्चा जो गांव के स्कूल में पढ़ता है, उसकी आई.क्यू. क्या है, उसका समझने का सिलसिला क्या है, उसमें काफी अंतर है। जब तक इस अंतर को आप दूर नहीं करेंगे, तब तक जो हमारा उद्देश्य है और जिस समाज को हम जो सुविधाएं तथा सहायता देना चाहते हैं, वह हम नहीं दे पाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बिल को आप इस रूप में प्रस्तुत करें ताकि वास्तव में समाज के व्यक्ति को जो समाज के आखिरी तबके का व्यक्ति है, पंडित दीनदयाल जी ने यह बात सर्वप्रथम कही थी कि हम समाज के उस तबके को उठाना चाहते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि वर्तमान यूपीए सरकार को उस तबके के बारे में

कोई चिंता नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि गरीबी दूर नहीं हो रही है, गरीब दूर हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस ओर सरकार चिंता करे और आम आदमी का हम कैसे हित कर सकते हैं, इस हिसाब से विचार करे।

**प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा) :** सभापति महोदय, जो विधेयक इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया है, शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन का जो प्रावधान इस बिल में रखा गया है, मैं उसका समर्थन और स्वागत करता हूँ। मैं सबसे पहले आज श्रीमती सोनिया गांधी, जो हमारी यूपीए की अध्यक्ष हैं और डा. मनमोहन सिंह, जो हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं तथा श्री अर्जुन सिंह, जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि बड़ी जद्दोजहद के बाद इस बिल को इस सदन में रखा गया और एक सिलेक्ट कमेटी ने इसके कुछ प्रावधान जो थे, उनको बड़े गौर से देखा और उसमें जो क्रिमी लेयर के लिए प्रावधान रखा गया था, उसको हटाया गया है उसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ। जब मंडल कमीशन लागू किया गया तो इंदिरा साहनी वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया। उस वक्त श्री शांता कुमार जी हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री थे और मैं वहां विधायक था। श्री शांता कुमार जी ने सरकारी खर्चे से एक वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया कि इंदिरा साहनी वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया में बैकवर्ड क्लासेज के जो लोग हैं, उनको किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने बैकवर्ड क्लासेज के हक में फैसला दिया। इंदिरा साहनी वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया केस के निर्णय में कहा गया कि कांस्टीट्यूशन में इसका प्रावधान है, रिजर्वेशन का प्रावधान पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए - ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग के हक में फैसला किया। लेकिन उसमें भी क्रिमी लेयर का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में आया है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आपने इस बिल में जो क्रिमी लेयर को हटाया है, परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमी लेयर को रखा है। जब आप इस बिल को पास कर देंगे और जब इसके रूल्स फ्रेम होंगे तो उसमें यह देखना पड़ेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिजीजन है, उसकी लाइमलाइट में आपको यह अमेंडमेंट दुबारा लाना पड़ेगा [\[r85\]](#)

इस बिल के जरिये पार्लियामेंट में क्रिमिलेयर को वेव ऑफ किया जाये - आपने शेड्यूल में ऐसे प्रावधान रखे हैं, जिनमें ओ.बी.सी. के लिये रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं रखा गया है। जैसा जिक्र किया गया है कि रिमोट सैसिंग डिपार्टमेंट में सैटेलाईट मेसेज आते हैं, उनके आधार पर इंटरप्रीटेशन किया जाता है और वह इंटरप्रीटेशन फील्ड में दिया जाता है। अगर सैसिंग डिपार्टमेंट से कोई मैप आता है तो उसका भी इंटरप्रीटेशन किया जाता है। हमारे गांव में रहने वाले किसानों को उससे मालूम होता है कि मौसम कैसा है, मिट्टी किस प्रकार की है, एग्रीकल्चर बेस क्या है, किस प्रकार की टैक्नोलौजी है, जो हमें गांवों में देनी है।

सभापति महोदय, आपको जानकर हैरानी होगी कि सैक्शन-4बी में जो शेड्यूल रखा गया है, उसमें रिमोट सैसिंग इंस्टीट्यूट में कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं किया गया है। इसी तरह और कई इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें ओ.बी.सी. के पढ़े-लिखे लोगों के लिये आरक्षण का प्रावधान होना चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूँ कि सैशन-4बी में जो शेड्यूल रखा गया है, उसे ओपन कर देना चाहिये ताकि हर आदमी अपनी योग्यता के अनुसार वहां आ सकता है।

सभापति महोदय, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स और मैडिकल इंस्टीट्यूट्स में सरमायेदार कैपिटेशन फीस देकर अपने बच्चों का एडमिशन करा देते हैं, लेकिन यह नहीं देखा जाता है कि कैपिटेशन फीस देने वाले बच्चे कितने कम्पिटेंट होते हैं? आज यूनिवर्सिटीज में घोटाले हो रहे हैं। सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं। ये कौन कर रहा है, क्या ओ.बी.सी. या एस.सी.एस.टी. का आदमी कर रहा है? इस सब के पीछे एक गैंग काम कर रहा है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जब भी वह यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन का प्रावधान रखें तो एक सिलेक्ट कमेटी होनी चाहिये जिसमें एस.सी.एस.टी. के एक मैम्बर का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिये ताकि जो भी सिलेक्शन हो, वह फेयर हो, ठीक हो और गरीब आदमी को इंसाफ मिले। यू.पी.एस.सी और स्टेट सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन बने हुये हैं। उनमें एस.सी.एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोगों को ड्यू रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, उनके साथ पार्शिएल्टी की जाती है। इसके लिये एक मकैनिज्म होना चाहिये ताकि बोर्ड में उनके मैम्बर का रिक्लूटमेंट हो सके और उन्हें इन्साफ मिल सके, जो गरीब तबके से है, गरीब किसान और मजदूर है, उनके बच्चों को न्याय मिल सके।

सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस बिल के जरिये एस.सी.एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोगों के लिये रिजर्वेशन का प्रावधान करेंगे।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, as per the List of Business, we are to take up the Half-an-Hour Discussion at 5.30 p.m. But I would like to get the sense of the House whether we shall continue with the discussion on the Bill or take the Half-an-Hour discussion.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI B.K. HANDIQUE): Sir, let us continue the discussion on the Bill and if the hon. Member does not mind, the Half-an-Hour discussion may be postponed to tomorrow. The hon. Minister also has an engagement and shall not be present in the House if this is taken up after this Bill is passed...  
(Interruptions)

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Tomorrow is Friday and we have Private Members' Business... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: We can postpone the Half-an-Hour Discussion to tomorrow.

SHRI B.K. HANDIQUE: We can have Half-an-Hour Discussion after the Private Members' Business.

MR. CHAIRMAN: All right. We will continue the discussion on the Bill and the Half-an-Hour discussion can be taken up tomorrow.

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति जी, माननीय श्री अर्जुन सिंह जी सदन में एक महत्वपूर्ण बिल लेकर आये हैं। यह केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में एस.सी.एस.टी. और ओ.बी.सी. के विद्यार्थियों को आरक्षण देने वाला बहुत ही क्रान्तिकारी बिल है।

[s86]

सभापति महोदय, हमारे देश के जो एससी, एसटी और ओबीसी के लोग हैं, आजादी के 60 वां पूरे हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा में उन्हें जितना एडमिशन मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अर्जुन सिंह साहब को मेरी सूचना है कि केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में तो आप आरक्षण दे रहे हैं, मगर जो प्राइमरी, हाई स्कूल एवं कॉलेज हैं, वहां भी आरक्षण होना चाहिए। कही ऐसा है, मगर हर संस्थान में आरक्षण नहीं दिया जाता है। दूसरे प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण देने के संबंध में हमें विचार करना चाहिए। जिस तरह एससी के लिए 15 प्रतिशत, एसटी के लिए साढ़े सात प्रतिशत एवं ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत, इस तरह कुल मिलाकर 49.5 प्रतिशत एडमिशन देने का यह प्रस्ताव है। मेरी सूचना एवं मांग है कि दूसरे उच्चवर्गीय लोगों में भी, समाज में भी इकोनोमिकली बैकवर्ड क्लास के काफी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए। इसमें साढ़े दस प्रतिशत आरक्षण उन वर्गों के लिए भी होना चाहिए, जिस वर्ग में इकोनोमिकली बैकवर्ड क्लास के परिवार हैं। ऐसे परिवार के लोगों

को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए इसमें टोटल 60 प्रतिशत आरक्षण करने की आवश्यकता है। इसके लिए कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। आज तक बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, आज तक 105 अमेंडमेंट कांस्टीट्यूशन में हो चुके हैं।

**17.37 hrs**

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

उपाध्यक्ष महोदय, बाबासाहेब अम्बेडकर जी, जो संविधान के शिल्पकार थे, वे कहते थे कि जब वक्त आएगा तब संविधान में उस समय की परिस्थिति के मुताबिक परिवर्तन होना चाहिए। पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने का अधिकार है। अगर आज हम 50 प्रतिशत के आगे नहीं जा सकते, लेकिन 50 प्रतिशत से भी ज्यादा आरक्षण देने के संबंध में विचार करने की आवश्यकता है। आरक्षण और समर्थन के विरोध में हमेशा संघर्ष चलता रहा है। उन लोगों को लगता है कि हमें बहुत कुछ मिल रहा है और हमें लगता है कि उन्हें ज्यादा मिल रहा है। सदियों से वे लोग लेते रहे हैं, अब हमें थोड़ा सा मिल रहा है, लेकिन उन्हें लगता है कि हमें बहुत कुछ मिल रहा है। इसलिए उन्हें भी मिलना चाहिए तथा हमें भी मिलना चाहिए। तुम भी खाओ और हमें भी खाने दो -, लेकिन आज तक खाली आप ही खाने का प्रयत्न करते रहे हैं।

उपाध्यक्ष जी, आप तो जानते हैं, आप पंजाब से आए हैं और मैं महाराष्ट्र से आया हूँ - हमें महाराष्ट्र की स्थिति मालूम है और पंजाब की स्थिति भी मालूम है। सभी लोग बातें करते हैं, लेकिन आज तक इन नीचे के वर्गों को ऊपर उठाने का काम हुआ है। मैंने पार्लियामेंट में बोला था कि नीचे के लोगों को अगर ऊपर उठाना है तो ऊपर के लोगों को नीचे लाने की आवश्यकता है और जब तक ऊपर के लोग नीचे नहीं आते हैं, तब तक नीचे के लोग ऊपर नहीं जाएंगे। हम ऊपर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ऊपर के लोग ऊपर जाने का प्रयत्न करते हैं और वे ऊपर जाते हैं, इसलिए हम नीचे जाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए अगर नीचे के वर्गों को ऊपर उठाना है तो उन्हें ताकत देने की आवश्यकता है। मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी हमारे साथ हैं। सब कुछ हमारे साथ है, लेकिन जब तक अटल जी और आडवाणी जी हमारे साथ नहीं आते हैं, तब तक हम ऊपर कैसे जाएंगे? ये लोग बोलते हैं कि हमें नीचे रहना चाहिए, मगर अब हम मल्होत्रा जी, नीचे रहने वाले नहीं हैं, हम ऊपर के लोगों को नीचे लाएंगे और नीचे के लोगों को ऊपर ले जाएंगे। इस तरह का काम हम सब लोगों को करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अर्जुन सिंह जी का आरक्षण का जो प्रस्ताव है, यह बहुत अच्छा है। मैं कविता में कहता हूँ - हमारे मनमोहन सिंह साहब का यूपीए सरकार बहुत है अच्छा, ये बहुत काम कर रहे हैं सच्चा, सोनिया गांधी जी को हर घर का बधाई दे रहा है दलित का बच्चा, लेकिन उनके लिए आपको बहुत काम करना होगा अच्छा - इसलिए आप अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन सिंह साहब द्वारा लाये गए विधेयक का हम पूरा समर्थन करते हैं। अगर हमारे स्टुडेंट्स को ज्यादा शिक्षा मिलेगी तो फिर हम मेरिट में आ पाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि आप उपाध्यक्ष का पद नहीं संभाल सकते थे, लेकिन जब आपने उपाध्यक्ष का पद संभाल लिया तो लोग बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे उपाध्यक्ष हैं।[\[rep87\]](#)

महोदय, मेरे मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट बनने से पहले मुझे लोग बोलते थे कि मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूँ और इन लोगों की खटिया खड़ी करने का काम कर रहा हूँ। हम यहां गरीबों को न्याय देने के लिए आए हैं। इसलिए हमें गरीबों के लिए सोचना चाहिए और उनके लिए काम करना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, there is no time available to any Party but still I have four or five speakers more on this Bill. So, it is my humble request to all of them to finish their speeches within two minutes.

Now, Shri Satpathy.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am grateful to you for giving me this opportunity to speak on the Central Educational Institutions (Reservations in Admission) Bill, 2006.

Sir, we know that the human nature does not allow that anybody gives anything to anyone else, and you have to be able to receive it. If we go according to this belief, we find that in this Hindu community in India, the upper castes, the *Brahmins*, the *kshatriyas* and others have been considered as the creamy layer and thus deprived of reservation, which I wholeheartedly support because the perception is that they are ahead of the others. But, Sir, when we see the effects of reservation for the past sixty years, whether for OBCs or SCs and STs, we find that amongst that section of the society, those who have become the creamy layer, the upwardly mobile and those who have been benefited, are unwilling to let go of the benefits that they have received. Therefore, it can be safely assumed that in this country, today there is a backward race. Everyone wants to become backward. As Shri Gangwar has said earlier, from 2000 institutionalized or registered OBC castes, now we have 6,500. This number alone shows that we have got into a sick mode, a mode where people have become mentally sick, and everybody wants to be backward. People are tricking this system to get themselves registered as backward. Those who can try to manipulate and become backward and are willing to be registered as backward because they want the benefits. It is a 'grab grab' situation. We, politicians, here and who have been elected to this August or September or October House are unwilling to speak the truth. This is no more a august House. ... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, give me some more time.

Sir, we are unwilling to find the truth; we are unwilling to say what the truth is; and we are unwilling to accept the reality of this country. It is a race. Everybody wants to become the champion of the backward. It does not matter if the champion is a *Rajput* or a King or a *Zamindar*. We saw that in 1990 when Shri V.P. Singh ventured out and wanted to be the champion. Now, we are seeing many more champions. But it is a sad state for this country that there is nobody who is willing to come up and say: "बस भाई 10 वॉ के लिए आरक्षण था।" The founding fathers of the Constitution in this country said that after ten years, you get rid of this reservation. Today, we are in a backward race, and we want to become more and more backward so that we get the benefits of this nation. Sir, when do we change this mindset? Will we remain as we are or will we change ourselves? That is the question.

Sir, it is a question of what kind of a society we want to create. I would like to question the hon. Members of Parliament from both sides of the House to give in writing that when they go to CGHS dispensary or RML Hospital, it should be mandatory that they should get a doctor who comes from their community or from the backward community, and they shall not ask for a doctor who is qualified. [\[R88\]](#)

If you say, on the one hand that there is no merit; if you say, on the one hand that merit does not matter; on the other hand, you are saying globalization; you are saying that we want to be

competitive internationally. You have to recognize merit; you have to recognize merit only when you bring in the OBC or ST or SC from the lowest of the low, from the poorest of the poor. If they are fed well, clothed well, educated well, then they become competitive. We do not do that; we cheat them; we try to take their votes; we try to benefit from their backwardness; and we give them solace that: "Listen, you are backward; we will do something for you."... (*Interruptions*)

But it is not them that we are benefiting. We have our eyes in the coming UP elections; we have our eyes on becoming the champions of the backwards.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down now.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, this is a repressive step; this is a very reactionary mindset, and I hope and believe that this Government and those who are present in this House today, will really consider this step and will think of the nation, think of India's future; and not become caste ridden, religion ridden, petty or small, but grow beyond all that. They have to rise above personal greed and party interests.

With these words, I conclude.

SHRI P. MOHAN (MADURAI) : Sir, I would like to extend my wholehearted support to this Bill on behalf of my party, CPI(M). I would like to point out that this is a historical and momentous one to benefit the backward sections of the society hailing from SC/ST and OBCs. All these days we have had the cart before the horse. Now we are setting right the fallacy and put the horse before the cart. Now the clock has been put back.

Based on the recommendations of the Mandal Commission the OBCs have been extended with the right to have job reservations in central government offices. After providing for job reservations to SCs/STs and OBCs only now we are going in for providing reservations in central educational institutions.

This Bill when passed will enable the backward sections of the society to get higher education. This will arrest the trend that was there for the past 59 years. From now on the higher education will be at the reach of the deprived sections like SCs/STs and OBCs. According to the statistics dished out by the Government only 6 per cent of our children would go upto the level of pursuing higher education. Only 6 persons among hundred people who go to schools have the consummation in the form of higher education. Most of the children from the backward sections of the society are not able to offer higher education because of their poor background, standard of living, poverty conditions, financial impairments and social disabilities. Their standard of living, their educational background and their economic conditions were posing problems and causing hurdles preventing them from going for higher education. This Bill will pave way for the children from the SCs/STs and OBCs to go for higher educations and job opportunities reserved for them.



---

\*English translation of the speech originally delivered in Tamil

Today we are in the age of Information Technology. We are witnessing a social divide that is emerging. We find computer literates on the one side and making money while there is another section not having access to the computers. This deprivation will lead them to further social and economic deprivation. A danger is looming large. As one who comes from Tamil Nadu that has championed the cause of social justice even before independence and one from Tamil Nadu that gave Thanthai Periyar to the world, I feel proud to welcome this Bill. As far as Tamil Nadu is concerned, it has always been in the forefront to ensure social justice by way of providing reservation in jobs and education. Only now the Centre is legislating in this regard. This needs to be implemented properly.

In this age of globalisation education is increasingly becoming a commercial venture. If we are to implement this Act in a full fledged manner we must ensure that education is not commercialised further. Privatisation of education and commercialization of education should be stemmed.

Education must get 6 percent of GDP as agreed upon in the National Common Minimum Programme that was given to the Government led by the UPA. I would also like to impress upon the Minister to ensure that the misleading word “certain” in clause 5 of this Bill is removed to allay apprehensions in the minds of the people as spelt out by some of my esteemed colleagues who spoke ahead of me.

Let me conclude with one suggestion. When a student from SC or ST or OBC community is applying for admissions in central educational institutions like IIM or IIT, even if they had indicated so in their applications, if they could get higher percentage of marks and find place in the merit list their names must find place in the merit list for open candidates. This is necessary because some more deserving and waiting candidates from the SC/ST and OBCs can get the benefit from the reserved list.

Even if they get 90% of marks they should be automatically taken to the open category lists. Only then we would be rewarding meritorious candidates from among the SCs/STs and OBCs while providing social justice in toto. Extending my support to this Bill, let me conclude my speech.

**प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) :** महोदय, यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। मैं यहां कुछ मुद्दों के बारे में बताना चाहूंगा। भारतीय संविधान के निर्माता डाक्टर भीम राव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1947 को भारत के राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद को संविधान समर्पित करते हुए कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम राजनीतिक समानता प्राप्त करेंगे, परन्तु सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में असमानता प्राप्त करेंगे। हमें इस विरोधाभास को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करना होगा, वरना जो अपमान के शिकार होंगे, वे प्रजातंत्र के ढांचे को ध्वस्त कर देंगे, जिसे हमने बड़े परिश्रम से तैयार किया है। वास्तविक रूप से यदि हम देखें तो पिछले साठ वॉ के काल में हमने इस ढांचे को समानता में लाने का प्रयत्न नहीं किया। इस बिल में कुछ सुधार की आवश्यकता है।

हम देखें कि आखिर ओबीसीज कौन हैं? जो गांव में मूल रूप में रहने वाले किसान और मजदूर हैं, उनमें पचहत्तर प्रतिशत लोग ओबीसीज में हैं। मेरी पहली मांग है कि भारतीय संघटना में परिवर्तन करें और लोकसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन को देश में लागू करें। इसके साथ-साथ जो अल्पसंख्यक संस्थायें हैं, उनमें भी इस बिल को लागू करें, उनमें सुधार करें। इसके साथ ही उसमें आरक्षण की व्यवस्था करें। विशेष रूप से हमने उच्च संस्थाओं में तो ऐसा कर लिया, लेकिन जो मूल ढांचा है, जो हमारी और आपकी कल्पना थी कि राष्ट्रपति, कलेक्टर और सफाई कामगार का बेटा एक स्कूल में पढ़ेगा, वह अभी संभव नहीं हो रहा है। उसका कारण फीस है। स्कूलों में फीस बहुत ज्यादा है। कलेक्टर अपने बेटे को ज्यादा फीस देकर सेंट्रल स्कूल या अन्य स्कूलों में पढ़ा लेता है, मगर सफाई कामगार का बेटा, नगर परिषद में और ग्राम पंचायतों या झोंपड़ी के स्कूल में पढ़ते हैं। इसलिए निचले तबके का बेटा ऊपर नहीं आ पा रहा है, यह सच बात है। ओबीसी की जनगणना अभी तक नहीं हुयी है। हमारे देश में जैसे एससीज और एसटीज की जनगणना हुयी, वैसे ही ओबीसी जनगणना शीघ्रातिशीघ्र कराने की आवश्यकता है।

महोदय, कुछ समय पहले एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण किया गया था। उसमें जो संख्या सामने आई है, उसके आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि 27 प्रतिशत आरक्षण केवल हमने कुछ संस्थाओं और आर्गनाइजेशंस में दिया, लेकिन इसका विस्तार लोकसंख्या के आधार पर करने की आवश्यकता है। नीचे जो एजुकेशन का ढांचा है, उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। जब तक नीचे के ढांचे में सुधार नहीं होगा, तब तक इस देश में समानता असंभव है। अगर यह अभी नहीं हो सकता, तो आगे चलकर करें। लेकिन सरकार अपने दिमाग में रखे कि इस बिल को केवल वोटों की राजनीति की दृष्टि से नहीं, बल्कि देश में समानता लाने की दृष्टि से देखे।

महोदय, आप केवल घटना दुरुस्ती का कारण वगैरह बतायेंगे। यह इस देश का सर्वोच्च सभाग्रह है। घटना दुरुस्ती करनी होगी, तो वह हो सकती है। इसलिए उस पद्धति से घटना दुरुस्ती करके लोकसंख्या के आधार पर स्टडी करनी होगी। उनकी जनगणना करनी होगी। लोकसंख्या के आधार पर नीचे से ऊपर तक लोग कैसे जाएं, इसे ध्यान में रखते हुए परिवर्तन करना होगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट कालेजेज, मेडिकल कालेजेज, इंजीनियरिंग कालेजेज हैं, उनमें आज बहुत ज्यादा फीस है। पन्द्रह-पन्द्रह लाख रूपए केवल छोटे-छोटे डेंटल कालेजेज में कैपिटेशन फीस लेते हैं, जो एबव रिकार्ड है। इसका मतलब है कि रिकार्ड में कुछ नहीं होता है। मेडिकल कालेज में तो साठ-साठ लाख रूपए लिए जाते हैं। क्या आपको इसका पता नहीं है? यह सब को पता है। इसलिए इसे रोकने की दृष्टि से कुछ प्रयत्न करने की आवश्यकता

है, ताकि जो छोटे तबके के लोग हैं, जिन्हें एडमीशन नहीं मिल पाता है, वे नीचे से ऊपर पहुंच सकें। अगर आपने परिवर्तन नहीं किया, तो मैं बताना चाहूंगा कि केवल किसान ही आत्महत्याएँ नहीं कर रहे हैं।<sup>[v89]</sup> आज किसान के बेटे महाराष्ट्र में टैंक पर चढ़कर शोले फिल्म की तरह ढांचा ध्वस्त करने में लगे हुए हैं।... (व्यवधान) यह हो सकता है कि वे हाथ में मशाल लेकर सड़कों पर आ जाएं।... (व्यवधान) उनके हाथ में मशाल लेकर सड़क पर आने से पहले, इस सारे ढांचे को सुधारें। इस दृष्टि से इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, मेरी पार्टी ने भी इसका समर्थन किया है।

**श्री वीरचन्द्र पासवान (नवादा) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण विधेयक) 2006 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह विधेयक आज सदन के समक्ष बहुत सारे चिन्तन, मनन, समर्थन और प्रतिकार के बाद इस रूप में उपस्थित हुआ है। इस दौरान काफी चर्चा हुई और उसमें हर तरह के विचार सामने आये। हम आदि काल से देख रहे हैं कि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं, जो बहुसंख्यक जनता को अपनी कूटनीति, रणनीति से हमेशा सताने, दबाने और शोषण करने का काम करते रहे हैं। इस चर्चा में बहुत ज्यादा मेघा, यानी मैरिट की चर्चा हुई। इसमें दलितों, पिछड़ों और डाउनट्राँडन लोगों के ऊपर, उनकी मैरिट के ऊपर, योग्यता के ऊपर अंगुली उठाने का काम हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी चर्चा करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने अतीत में इस देश की जिम्मेवारी ली थी, इस देश पर शासन करने, इस देश को आगे बढ़ाने का काम लिया, इस देश की रक्षा करने का काम लिया, इस देश के आवाम को खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़ाकर, उन्हें तरक्की की राह पर ले जाने का वायदा किया, लेकिन वे उन्हें तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा सके और न ही उनका विकास करा सके, बल्कि इस देश की अस्मिता को भी नहीं बचा सके। जो लोग अपनी काबलियत और योग्यता का दम्भ भरते हैं, जब उनके कंधो पर इस देश को बचाने का काम था, तब उन्होंने इस देश को गुलाम बनाने का काम किया। जब यहां सिकन्दर आया तो उसने इस देश को रौंद डालने का काम किया। मुगलों ने आकर इस देश को गुलाम बनाया। ... (व्यवधान) सुलतानों ने आकर इस देश को गुलाम बनाया। अंग्रेजों ने यहां आकर काफी वार्ड तक शासन किया। ... (व्यवधान) तब इनकी काबलियत और योग्यता कहां थी? ... (व्यवधान) आज जब यह योग्यता की बात करते हैं, मैरिट की बात करते हैं, तब हमारे लोगों के मन में बड़ी हलचल होती है। ... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Nothing is going on record. Please sit down.

*(Interruptions) ... \**

**श्री वीरचन्द्र पासवान :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं नया मैम्बर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आसन से मुझे सहयोग मिलेगा। ... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is not the way. Nothing is going on record. Please sit down.

*(Interruptions\*) ...*

---

\* Not recorded

उपाध्यक्ष महोदय: अपनी बात कहने का यह रास्ता नहीं है।

...(ब्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकार्ड नहीं हो रही है। [MSOffice90]

... (Interruptions)

**18.00 hrs**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Tapir Gao. You may speak for two minutes.

... (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय: पासवान जी, आपका कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

(Interruptions) \* ...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is going on record. You are wasting the time.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is going on record. Please sit down.

(Interruptions) \* ...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is going on record.

(Interruptions) \* ...

उपाध्यक्ष महोदय: छः बज गये हैं। अगर हाउस चाहे, तो जब तक यह बिल और जीरो ऑवर खत्म नहीं होता तब तक के लिए हम हाउस को एक्सटेंड कर देते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : ठीक है। (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down now. Nothing is going on record. You are wasting the time.

(Interruptions) \* ...

उपाध्यक्ष महोदय: गाव जी, आप बोलना चाहते हैं या नहीं?

...(ब्यवधान)

श्री तापिर गाव : सर, वे भी अपने दलित भाई हैं। ... (ब्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down now.

... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Tapir Gao. You may speak for only two minutes.

श्री तापिर गाव : उपाध्यक्ष महोदय, आप उन्हें पहले बैठने के लिए कहिये। ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आठवले जी, आप पहले बोल चुके हैं इसलिए बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Tapir Gao will speak. You may speak for only two minutes.

SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST): Hon. Deputy-Speaker, Sir, you are allotting me only two minutes to speak, but constitutionally, being a tribal, I have got 7.5 per cent right. So, I am converting it into minutes! ... (*Interruptions*) Sir, I am the last Member to speak on this Bill. Really, on behalf of the SC, ST and OBC community of this country, I salute the hon. Minister, Shri Arjun Singh. He is really working hard for the SC, ST and OBC people of this country. I can term Shri Arjun Singh as Arjun of *kalyug* but sometime, I find that Shri Arjun Singh stands without arms and ammunition in the warfield, fighting for the SC, ST and OBC community of this country. So, I would request him to equip himself with arms and ammunition so that in the warfield, he can really fight for the cause of the SC, ST and OBC community of this country.

First of all, I would like to mention that you are extending reservation in admission to Centrally-aided institutions, but I would request that the intention of the institutions should also be safeguarded.[\[s91\]](#)

It is a safeguard in the sense that पहले उस इंस्टीट्यूशन के नियम को ठीक करना पड़ेगा। The intention of the institutions will have to be rectified. The OBC, ST and SC students are being mentally harassed when they get admission, and they are being harassed even for getting their ratings in the institutions. Therefore, they become blacksheep in the institutions.

We are aware that there is a law against atrocity. How we are to implement this law against these institutions? This could have been added in this Bill, which could have been a protection, and a weapon to protect and prevent the STs, SCs and OBCs atrocity in institutions. I would have felt happy, and the people of this country would have felt happier if reservation in admission for SCs, STs, OBCs and the minorities was also provided in the private institutions. It would have been made a better Bill. Hence, I termed you as a warrior without arms and ammunition as this is creating a social imbalance. We need to mix with the minorities, and we need to mix with the high-class people

where the private institutions are doing a good academic job. Please give me some more time. ...  
(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not possible for me to give you five more minutes to speak on this issue.

... (Interruptions)

SHRI TAPIR GAO : The OBC, SCs, STs, and even the minorities could have been given quota in the private institutions. This would have made this a better Bill for the social development as well as the overall development of this country.

You are a good astrologer in the sense that you can determine that the tribal boys, girls and OBC cannot become scientists. I am saying this because you have excluded the creamy institutions of the country. Nearly 18 institutions have been left out where the SCs, STs, and OBCs cannot have reservation. You will have to find an institution like the Bhaba Atomic Research Centre for the SCs, STs and OBCs in this country where the OBCs, STs, and SCs can have the privilege to become scientists, doctors, superlative human beings, etc. But you have excluded these institutions.

Lastly, I need a clarification from the hon. Minister on one issue. Unlike other Ministers, you will take a very short time to respond, and within this short time I need a clarification on minorities. Is it the linguistic minorities or religious minorities? This has not been clarified in this Bill. Therefore, I seek your clarification on this issue, and I am sure that you will make it clear in the short span of your deliberations.

One Member said that the BJP has not done anything. ... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Gao, thank you very much. Please sit down.

... (Interruptions)

SHRI TAPIR GAO : But in 1997, Shri I. K. Gujral dereserved the reservation policy with five official memorandum, but the BJP restored those five official memorandum. This is the record of the BJP in this country. ... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Thank you very much. Now, I would like to request the hon. Minister to respond to the discussion.

SHRI TAPIR GAO : Further, political reservations have been extended by the BJP in this House. So, the BJP should not be blamed for it. BJP supports reservation, and the BJP supports the SCs, STs, OBCs and even the minorities of this country. Thank you very much for allowing me to speak on this issue.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, I request the hon. Minister to respond to the discussion.

... (Interruptions)

SHRI MANORANJAN BHAKTA (ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS): Sir, I would request you to give me two minutes to speak on this very important issue. ... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am very sorry, but I have already called the hon. Minister to respond on this issue.

... (*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, इस बिल के बारे में हमने अमेंडमेंट्स दिये हैं, जब अमेंडमेंट्स मूव करेंगे, उसके बारे में कह दें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right, you can speak at that time.

... (*Interruptions*)

SHRI MANORANJAN BHAKTA : Sir, I will take only two minutes time from you to speak on this issue, and I will follow it too. ... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Minister, please sit down for two minutes.

श्री रामचन्द्र पासवान जी का नाम किसी वजह से छूट गया है, पहले कृपया उनको बोलने दीजिए।[\[r92\]](#)

**श्री रामचन्द्र पासवान (रोसड़ा):** उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में यह सदन सर्वोच्च है और आज हम इस सदन में देश के दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के हित का काम करने जा रहे हैं। आजादी के सैंकड़ों साल के बाद भी दलितों को आरक्षण का मुद्दा अभी तक चल रहा है, क्योंकि अभी तक इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। आज देश में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सका है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि इन वर्गों के लोगों का जो बैकलॉग है, उसे कब तक भरा जाएगा और कब इनका कल्याण होगा? यह कहने की बात नहीं है और न ही भाग देने का समय है।

हमें एक मिनट का समय मुश्किल से मिला है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। सरकार की ओर से क्रीमी लेयर के बारे में कहा गया है और कोर्ट ने भी अपनी बात रखी है। मैं सदन में मांग करता हूँ कि न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है इसलिए पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को न्यायपालिका में भी आरक्षण मिलना चाहिए।

हमारा पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है इसलिए वहां भी आरक्षण होना चाहिए। जब पब्लिक सेक्टर में आरक्षण था और अब जबकि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, वहां इन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, तो ये लोग कहां जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर चर्चा करते हुए कई माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बातें कही हैं। आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपका सम्मान करते हुए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में भी दलितों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए।

इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और इस बिल का समर्थन करता हूँ।

SHRI MANORANJAN BHAKTA : Sir, I support the Bill piloted by Arjun Singh ji who is a very senior leader of the Congress party. There is only one point that I would like to bring to the kind notice of the hon. Minister. There are a number of communities in Andaman and Nicobar islands who are asking for Scheduled Tribe status but are not getting it. So, before you he does all this, the hon. Minister must also kindly consider and see as to why communities like Oraon, Munda, Kiriya who are living in these areas are not getting this status. I would request the hon. Minister to kindly consider this.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) : Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am very grateful to all the hon. Members who spoke in the debate today and I am particularly obliged to them that they kept in view the fact that this proposal is the result of the Constitutional Amendment made in the 93<sup>rd</sup> amendment. The spirit behind that amendment has been kept in tact and an effort has been made to take a view which is as close to unanimity as possible.[\[r93\]](#)

At the outset, I would like to say that the Legislative Department has already issued a Corrigendum with regard to the mistake that was pointed out in the Hindi version and that Corrigendum was distributed also but still I apologise for the inconvenience that some Members had to face.

The first thing that I would like to mention very categorically is about the un-aided institutions, because there has been some confusion in the speeches that have been made as to whether this reservation will also be applicable to the un-aided institutions. In this regard, I would like to say that a Bill is under preparation, and very soon it will come before the House, which will take care of that aspect also.

Various points have been raised and I will put them in separate categories. Firstly, the suggestions have been made about the implementation of this law. Those suggestions are most welcome and I would like to assure you that at the time of its implementation, we will try to consult all Members of this House in various ways so that the implementation of this Act also becomes as unanimous as it is possible.

The minority issue seems to have focused the attention of some of the Members of the House. If I may say so, this issue has already been decided by the Constitutional amendment itself and, therefore, this law is obviously within the four-corners of that amendment. I cannot go beyond that in satisfying some hon. Members about the minority issue. Therefore, kindly bear with me as it is not within my power to do so. That decision was taken by this House on a Constitutional amendment and that is the last word, so far as we are concerned.



PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : That was only an enabling clause. You can easily delete the word 'minority'.... *(Interruptions)*

SHRI ARJUN SINGH: It was a Constitutional amendment and now, when the Constitution stands amended, how can I say that this enables me to do this or that?

The other point which has been made is that the Schedule that has been drawn up, is being treated as if we have made a division between institutions. The Schedule was introduced not because we are trying to divide the institutions but the Schedule was introduced... *(Interruptions)*

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : Not the institutions alone but you are dividing the nation also.... *(Interruptions)*

SHRI ARJUN SINGH: Get out of that obsession of dividing everyone. Think of including everyone. That should be the spirit.... *(Interruptions)*

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : You are excluding the private institutions run by the.... *(Interruptions)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing, except the speech of hon. Minister, will go on record.

*(Interruptions)\* ...*

SHRI ARJUN SINGH: I do not want to enter into this debate because it does not help anyone. So far as these institutions are concerned, they have been included in the Schedule because basically they are not institutions where students are admitted for studies. They are basically research institutions. They have to be kept separate so that confusion does not arise there. If and when they become teaching institutions and they admit students, in the normal way, they will be attracted by this Bill.[\[R94\]](#)

---

\* Not recorded

At the moment they do not. They can also be amended by the permission of Parliament because none of this is going to go behind the back of this August House. All these institutions as they are, are research-based and in that we do not want to create any confusion. That is the basic reason.

So far as the question of Sixth Schedule in the North-East is concerned, we have kept all the institutions of the Sixth Schedule in the North-East out because they are predominantly populated by tribals and there we do not want this issue. So, it is a conscious decision and a decision which has been endorsed by the Standing Committee.

Many of the States, in fact, have already initiated action and they have made some laws in this regard to ensure the objectives of the Constituion Amendment. But this was needed because the Central institutions which are under the Central Government have to be made eligible for giving reservations to students in all Central institutions and this was a pledge which had been given by us at the time of moving the amendment to the Constitution.

Sir, a question has been raised about staggering and why this cannot be done at one go. Let me tell the hon. Members that the law permits any institution which wants to introduce it in one go can do it. There is no prohibiting it. But the fact remains and the hon. Members would kindly bear with me that there are practical difficulties as faculty and other factors are concerned and, therefore, the principle has to be of ensuring any question of convenience in the institutions. If they so desire and if it is necessary, they can do it within three years. So far as the Central Government is concerned, it will assist all these institutions in ensuring that ultimately the reservation for 27 per cent of OBCs becomes a reality in all Central Institutions without any fail.

So far as the question of reservation in minority institutions is concerned, I have to say that...  
(*Interruptions*)

PROF. RASA SINGH RAWAT (AJMER): In case of reservation for minorities, it will be for minority institutions only... (*Interruptions*)

SHRI ARJUN SINGH: If you are aware of the basic recommendation of Mandal, it has already enumerated, in that list, the persons who are considered to be OBCs, whether they are Muslims, whether they are Christians or whether they are Hindus. Why can they not be admitted where everyone else is? What they want to do is certainly up to the Minority institutions. I have no objection if Minority Institutions, on their own, wants to admit any people from there.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Will a Muslim OBC get admission in a Christian institution?

SHRI ARJUN SINGH: If the institutions want to do it, who is stopping them?

SHRI KHARABELA SWAIN : But as per this law, he will not get admission.

SHRI ARJUN SINGH: As per this law, all people who come under the category of OBC are eligible to admission on the Central institutions. This is not for any individual institution. This is for Central institutions. If there is any default, you let us know and we will try to address it. [\[R95\]](#) Sir<sup>[MSOffice96]</sup>, I think these are some of the basic issues that were raised.

There is one thing which I would like to point out. In fact, the whole question of reservation started with the First Amendment of the Constitution which was moved by Pandit Jawaharlal Nehru which took into account all the movements that have ultimately contributed to the freedom of India. The fact is, the Indian Freedom Movement is not only a political movement. It was a social movement also in which all the streams joined and then presented such a formidable opposition to the British empire that they had no choice but to pack up. All those social movements, whether they were in the South or in Maharashtra or anywhere else, constitute a very powerful stream in our

national ethos and therefore, I would like to say that when Panditji moved his First Amendment, he was only taking note of what had gone into the Freedom Movement and what ultimately helped us to achieve freedom. Therefore, the 93<sup>rd</sup> amendment was moved and now, for the first time, a law is being made under that amendment so that all the rights that accrue to the SCs, STs and the OBCs become a statutory law which can be enforced. There should be no doubt that this is the will of this Parliament. There should be no confusion that this Parliament has decided both to amend the Constitution and now, to, with your help, amend the law and bring this law which will be the will of the Parliament and we stand by this law.

With these words, I would like the hon. House to pass this Bill. (*Interruptions*)

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या लोक संख्या की जनगणना करेंगे?

MR. DEPUTY-SPEAKER: No clarification is allowed. Please take your seat.

... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That the Bill to provide for the reservation in admission of the students belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes of citizen, to certain central educational institutions established, maintained or aided by the Central Government, and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

*The motion was adopted.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

## **Clause 2**

## **Definitions**

*Amendments made:*

Page 2, for lines 22 and 23, *substitute* –

‘(e) “faculty” means the faculty of a Central Educational Institution;’ (1)

‘(j) “teaching or instruction in any branch of study” means teaching or instruction in a branch of study leading to three principal levels of qualifications at bachelor (undergraduate), masters (postgraduate) and doctoral levels.’ (2)

(Shri Arjun Singh)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That clause 2, as amended, stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.*

*Clause 2, as amended, was added to the Bill.*

*Clause 3 was added to the Bill.*

#### **Clause 4**

**Act not to apply**

**in certain cases**

उपाध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी आप अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं?

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : I beg to move:

Page 3,--

*omit line 12. (3)*

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज 4 में पृष्ठ 3 पर 12वीं पंक्ति में लिखा है “The provisions of Section 3 of this Act shall not be apply to” and it is written as “Minority educational institutions as defined in this Act”. मैं चाहता हूँ कि इसे रिमूव कर दिया जाए और सभी माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन्स में भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहां यह मिल रहा है जैसे केरल में 70 से 80 परसेंट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अदर बैकवर्ड क्लास को दाखिला मिलता है, लेकिन इसके बाद दाखिला मिलना बंद हो जाएगा। [r97] इसी तरह से दिल्ली के सेन्ट स्टीफन कालेज में जो दाखिला मिलता है, उसमें भी दाखिला मिलना बंद हो जायेगा। हिन्दू कालेज में दाखिला मिलेगा, लेकिन सेन्ट स्टीफन कालेज में दाखिला नहीं मिलेगा। सेन्ट स्टीफन में 99 परसेन्ट हिन्दू पढ़ते हैं, वहां पर टीचर्स भी 99 परसेन्ट हिन्दू हैं। परंतु उसके बावजूद भी because it is being managed by Christians. इसलिए वहां पर जो दाखिला आज तक मिल रहा है, वह मिलना बंद हो जायेगा। लेडी श्री राम कालेज में दाखिला मिलेगा, लेकिन क्वीन मैरी कालेज में नहीं मिलेगा। क्वीन मैरी कालेज में इसके बाद दाखिला मिलना बंद हो जायेगा, जो आज मिल रहा है। आज वहां कम्पलसरी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एडमिशन होता है। इसी तरह से देश भर में और भी इंस्टीट्यूशंस हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें भी दाखिला मिलना बंद हो जायेगा।

सभापति महोदय, इस पर विचार करने की जरूरत है कि पंजाब के अंदर हायर एजुकेशन के जितने भी कालेजेज हैं, उनमें से कोई क्रिश्चियन मैनेज्ड हैं, कोई सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा मैनेज्ड हैं और कोई आर्य समाज द्वारा मैनेज्ड हैं। इतना ही नहीं, इसमें यह भी कहा गया है कि लिंग्विस्टिक माइनोरिटी भी है। आंध्र प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति ने गाजियाबाद में एक डेंटल कालेज खोला है, **it becomes a minority institution.** उसमें भी एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. को दाखिला मिलना बंद हो जायेगा। इसी तरह से अगर पंजाब का आदमी तमिलनाडु में चला जाए तो वहां भी वह लिंग्विस्टिक माइनोरिटी की वजह से माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन बन जायेगा। मैं समझता हूं कि यह जो आप करने जा रहे हैं, इसमें नम्बर कम हो जायेंगे। आज लोगों को जो दाखिले मिल रहे हैं, वे 50-60 परसेन्ट बंद हो जायेंगे और जो बढ़ेगा, उससे भी वह कम्पैन्सेट नहीं होगा। यह बहुत गलत स्टेप है और इसलिए मैं इस अमैन्डमेंट को मूव करता हूं और मैं आशा करता हूं कि इस अमैन्डमेंट को स्वीकार किया जायेगा कि ओ.बी.सी. और एस.सी., एस.टी. का रिजर्वेशन माइनोरिटी इंस्टीट्यूशंस में भी लागू होना चाहिए। ... (व्यवधान)

**श्री खारबेल स्वाई :** सर, मैं भी एक मिनट बोलना चाहता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप एसोसिएट कर लीजिए।

**श्री खारबेल स्वाई :** हमने अलग-अलग अमैन्डमेंट दिये थे, एक साथ नहीं दिये थे।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आपके एक साथ हैं।

**श्री खारबेल स्वाई :** हमारे एक साथ नहीं है। मैंने अलग दिया था। ... (व्यवधान) हमने अलग-अलग दिये हैं, एक साथ नहीं दिये हैं। इसमें लिखा है, लेकिन जब हमने दिये थे, अलग-अलग दिये थे। आप हमारे नोटिस देखिये, हम तीनों ने अलग-अलग दिये थे।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आपका तीन नम्बर पर है।

**श्री खारबेल स्वाई :** वह हो सकता है, लेकिन हम तीनों को क्लब कर दिया गया है। लेकिन हमारे नोटिस अलग-अलग थे। ... (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** ठीक है, आप बोलिये।

**SHRI KHARABELA SWAIN :** The hon. Minister has said that because of the Constitutional Amendment, his hands are tied. ... (*Interruptions*) Why should minority educational institutions be excluded from the reservation for OBCs? Does it mean that the upliftment of the OBCs of this country is the responsibility of only the Hindus and that minorities do not have any responsibility towards them? That is the major question I am asking. Does it mean that minorities will share only the resources of this country and not the responsibility? That is why I am just asking this. Then, everybody says, everybody is a patriot. People also say that the country does not belong to the BJP alone. If that be so, then let the minorities also share the responsibility of uplifting the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the OBCs. That is my appeal. If that be so, then 12<sup>th</sup> line should be deleted.

**श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल माननीय मंत्री जी के द्वारा लाया गया है, हम इसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात छोड़ दी गई है, इसमें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के आरक्षण को नहीं जोड़ा गया है। इसके कारण समाज में जो आर्थिक, सामाजिक समरसता की जो खाई है, वह बड़ी होगी। इन वर्ग के लोगों को इन संस्थाओं में एडमिशन नहीं मिलने के कारण वे अपनी शिक्षा से वंचित होंगे और इन वर्गों के लोगों की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि ये लोग लम्बी-चौड़ी राशि देकर, लम्बा-चौड़ा पैसा देकर या डोनेशन देकर इन बड़ी संस्थाओं में प्रवेश ले सकें। अतः माननीय मन्होत्रा जी ने जो अमैन्डमेंट रखा है, मैं उसे मूव करता हूं।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपको भी कुछ कहना है[MSOffice98]।

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Sir, please give me a chance to speak. ...  
(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No. You have not given the notice.

... (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, he has not given the notice. How can he speak? ...  
(Interruptions)

श्री अर्जुन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : खेद होना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : खेद तो है ही। आपके कारण। ...(व्यवधान) यह अमेंडमेंट लाकर जो हमने पहले ही संवैधानिक प्रबन्ध किया है, उसका उल्लंघन करने का प्रयास तो यह है ही लेकिन साथ ही साथ मैं बहुत साफ तौर से कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर जो आज बहुत से इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, बिना इस संशोधन के भी उनमें ओबीसी, हरिजन तथा आदिवासियों का एडमिशन हो रहा है।...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अब बंद हो जाएगा।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : क्यों बंद हो जाएगा? ...(व्यवधान) सुन तो लीजिए। अब आप बोल चुके हैं। क्या बार-बार आप ही खड़े होकर बोलते रहेंगे? हम किसलिए हैं? ...(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत : मंत्री जी को गुस्सा नहीं करना चाहिए।

श्री अर्जुन सिंह : गुस्सा मुझे नहीं आता है। एक मजबूरी है।...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो आया है, यह सेन्टर से एड्ड सैन्ट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए आया है। जो ऑलरेडी आज माइनोंरिटी से चलाये जाने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, हम लोगों को तो फ्रक होना चाहिए कि उनमें से करीब-करीब अधिकांश ही देश में ओबीसी, हरिजन और आदिवासियों को एडमिशन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं।...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अब बंद हो जाएगा।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : बंद कैसे हो जाएगा? क्या आपके कहने से बंद हो जाएगा? ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record. आपकी कोई बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।

(Interruptions)\* ...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is going on record.

(Interruptions)\* ...

श्री अर्जुन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों के लाख कहने के बाद भी ये माइनोंरिटीज इंस्टीट्यूशंस अपने दरवाजे इस देश के उन लोगों के लिए बंद नहीं करेंगे जिनको वे सदियों से अपने साथ रखते आये हैं।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall put Amendment No. 3 moved by Prof. Vijay Kumar Malhotra, Shri Virendra Kumar and Shri Kharabela Swain to the vote of the House.

*The amendment was put and negatived.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That clause 4 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.*

*Clause 4 was added to the Bill.*

*Clauses 5 to 7 were added to the Bill.*

*The Schedule was added to the Bill.* [\[a99\]](#)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Sir, please give me a minute.... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No rule permits me to allow you.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : I have my right to speak. I will not take more time.

---

\* Not Recorded

उपाध्यक्ष महोदय: मैं बिल पास होने से पहले आपको टाइम दूंगा।

... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.*

*Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.*

SHRI ARJUN SINGH: I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed.”

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill, as amended, be passed.”

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Sir, on the eve of passing of this very important and crucial Bill, I have to make an observation. There is no OBC Parliamentary Committee to look after whether reservation is properly implemented or not. We have been ensuring the implementation of reservation in jobs. We are now giving reservation facility in the educational institutions. So, my request to the Government of India is that it should appoint one Parliamentary OBC Committee to review the implementation of this thing. That is my request.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That the Bill, as amended, be passed.”

*The motion was adopted.*

---